

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

*A Thesis Project
submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the
degree of*

Bachelor of Planning

By

Sampurna Mandal

Scholar No. 2211002119

Under the Guidance of

Dr. Alka Bharat



**Department of Architecture and Planning
Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal**

May 2026

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A
CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

DECLARATION

I SAMPURNA MANDAL, Scholar No 2211002119 hereby declare that the thesis titled Transforming Agricultural Wastelands Into Agro-Productive Lands: A Case Of Bankura District Of West Bengal submitted by me in partial fulfilment for the award of degree of Bachelor of Planning, at Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal, India, is a record of Bonafide work carried out by me. The matter/result embodied in this thesis has not been submitted to any other University or Institute for the award of any degree or diploma.

Sampurna Mandal

Signature of the Student

Date: 07/05/2026

CERTIFICATE

This is to certify that the declaration made by SAMPURNA MANDAL is true to the best of my knowledge and that the student has worked under my guidance for one semester in preparing this thesis.

RECOMMENDED

[Signature]
7/05/26

Signature of the Guide
(Dr. Alka Bharat)

ACCEPTED

[Signature]
8.5.26

Signature of

Head, Department of
Architecture and Planning
(Dr. Nakul Dhagat)

Date: _____

Place: _____

[Signature]

Signature of

Thesis Coordinators,
Department of Architecture and
Planning
(Dr. Preeti Onkar &
Dr. Premjeet Das Gupta)

Date: 7/05/26

Place: Bhopal

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

सारांश

विश्वभर के कृषि परिदृश्य आज पर्यावरणीय क्षरण, अस्थिर भूमि उपयोग प्रथाओं और जलवायु अस्थिरता के कारण गंभीर दबाव में हैं। विकासशील देशों, विशेषकर भारत में, यह चुनौती और भी गहरी है क्योंकि ग्रामीण आजीविकाएँ कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों पर निर्भर हैं। भूमि क्षरण केवल पारिस्थितिक समस्या नहीं है, बल्कि यह खाद्य सुरक्षा, रोजगार और क्षेत्रीय विकास से जुड़ा सामाजिक-आर्थिक मुद्दा भी है। कृषि परित्यक्त भूमि—जो प्राकृतिक सीमाओं या मानवजनित क्षरण के कारण अपनी उत्पादकता खो चुकी है—एक चुनौती और अवसर दोनों प्रस्तुत करती है। यदि इन्हें अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो यह गरीबी, पलायन और पारिस्थितिक असंतुलन को बढ़ाती है; लेकिन यदि रणनीतिक रूप से पुनः प्राप्त किया जाए तो यह ग्रामीण लचीलापन और सतत विकास लक्ष्यों को मजबूत कर सकती है।

इस राष्ट्रीय और वैश्विक विमर्श के भीतर, पश्चिम बंगाल का बांकुरा जिला भूमि पुनर्वास और कृषि-उत्पादक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र प्रस्तुत करता है। यह जिला छोटानागपुर पठार और बंगाल बेसिन के बीच स्थित है, जिससे इसकी विशिष्ट "राहें" भौगोलिक संरचना बनती है—लाल-लेटराइटिक ऊँचाइयाँ, नीची नमी वाली घाटियाँ और खंडित कृषि क्षेत्र। यह असमान भू-आकृति जल वितरण में असंतुलन पैदा करती है, जहाँ मध्यम वर्षा होने पर भी कृषि सूखा देखा जाता है।

बांकुरा की मिट्टी की संरचना इस समस्या को और बढ़ाती है। यहाँ की प्रमुख मिट्टियाँ लेटराइटिक और लाल-पीली हैं, जो अम्लीय, पोषक तत्वों (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम) से गरीब और कार्बनिक पदार्थों में कम होती हैं। इनकी मोटी बनावट और कठोर परतें जल धारण क्षमता और जड़ों की पैठ को सीमित करती हैं, जिससे भूमि का बड़ा हिस्सा अनुपयोगी या कम उत्पादक हो जाता है।

फिर भी, ऐसी भूमि स्थायी रूप से खोई हुई नहीं है। यदि स्थानीय भूगोल, मिट्टी, जलविज्ञान और सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप पुनर्वास रणनीतियाँ अपनाई जाएँ तो इन्हें बहु-कार्यात्मक परिदृश्य में बदला जा सकता है—जो खाद्य उत्पादन, पारिस्थितिक पुनर्स्थापन और ग्रामीण आजीविका को एक साथ समर्थन दें।

इस अध्ययन में बहु-विषयक ढाँचा अपनाया गया है जिसमें भू-स्थानिक विश्लेषण, रिमोट सेंसिंग और क्षेत्रीय पारिस्थितिक रणनीतियाँ शामिल हैं। सेंटिनल-2 और लैंडसैट उपग्रह चित्रों का उपयोग कर बांकुरा की परित्यक्त भूमि का वर्गीकरण किया गया है। इन आंकड़ों को भू-आकृति, मिट्टी, वर्षा और वनस्पति संकेतकों के साथ जोड़ा गया है। MCDA और AHP पद्धतियों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है जहाँ पुनर्वास से अधिकतम पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक लाभ मिल सकते हैं।

अध्ययन से पता चलता है कि बांकुरा की भूमि पुनर्वास क्षमता को तीन प्रबंधन क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है:

पश्चिमी क्षेत्र अत्यधिक क्षरणग्रस्त है और यहाँ गहन पारिस्थितिक पुनर्स्थापन की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में एग्रोफॉरेस्ट्री, कंटूर ट्रेचिंग और बायोमास पुनर्जनन जैसी तकनीकें अपनाई जानी चाहिए। इन उपायों से मिट्टी को स्थिर किया जा सकता है, कटाव को कम किया जा सकता है और पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यक्षमता को पुनः स्थापित किया जा सकता है।

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

मध्य क्षेत्र मध्यम क्षरण वाला है और यहाँ उत्पादकता-वर्धक तकनीकों का प्रयोग उपयुक्त है। सूखा-रोधी फसलें, एकीकृत खेती प्रणाली और सूक्ष्म सिंचाई जैसी विधियाँ इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन को बढ़ाने और भूमि की उपयोगिता को बनाए रखने में सहायक होंगी।

पूर्वी क्षेत्र अपेक्षाकृत स्थिर और उपजाऊ है। इस क्षेत्र में उच्च-मूल्य वाली बागवानी, फसल विविधीकरण और किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से संस्थागत सुदृढीकरण किया जा सकता है। इन उपायों से कृषि का अनुकूलन होगा और किसानों को बेहतर आर्थिक अवसर प्राप्त होंगे।

इस शोध की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह मौजूदा नीति ढाँचों से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और राज्य स्तरीय उशर्मुक्ति परियोजना जैसी योजनाओं से तालमेल बैठाकर यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रस्तावित ढाँचा व्यवहार्य और विस्तार योग्य रहे।

अंततः, यह अध्ययन दर्शाता है कि क्षरित कृषि भूमि को पुनः कल्पित कर लचीले कृषि-परिस्थितिकी तंत्र में बदला जा सकता है। बांकुरा का उदाहरण यह साबित करता है कि भूमि पुनर्वास केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं है, बल्कि ग्रामीण परिवर्तन, जलवायु अनुकूलन और सामाजिक-आर्थिक समानता की दिशा में एक मार्ग भी है। प्रस्तुत ढाँचा अन्य अर्ध-शुष्क और पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों के लिए भी एक अनुकरणीय मॉडल प्रदान करता है।

ABSTRACT

Agricultural landscapes across the world are under increasing strain as environmental degradation, unsustainable land-use practices, and climate variability continue to reduce the productivity of once-viable land systems. This challenge is particularly acute in developing countries such as India, where rural livelihoods remain deeply tied to agriculture and allied sectors. In such contexts, land degradation is not simply an ecological issue; it is also a socio-economic concern that directly affects food security, employment, and regional development. Agricultural wastelands—lands that have lost their productive value due to natural constraints or human-induced degradation—represent both a challenge and an opportunity. If left untreated, they intensify poverty, migration, and ecological imbalance. If strategically reclaimed, however, they can become productive assets that strengthen rural resilience and support sustainable development goals.

Within this national and global discourse, the district of Bankura offers a compelling case for studying land reclamation and agro-productive transformation. Located in the western part of West Bengal, Bankura occupies a transitional geographical zone between the ancient rock formations of the Chotanagpur Plateau and the younger alluvial plains of the Bengal Basin. This unique setting gives rise to the district's characteristic “Rarh” landscape—an undulating terrain marked by lateritic uplands, low-lying depressions, and fragmented agricultural fields. While visually distinct, this terrain presents considerable challenges for conventional agriculture. The elevated ridges, locally known as *Tanr*, often experience rapid runoff during monsoon events, while shallow depressions, called *Kanali*, retain seasonal moisture for limited durations. This uneven distribution of water creates a persistent hydro-climatic imbalance, where even regions receiving moderate rainfall can experience agricultural drought due to poor infiltration and storage.

The ecological difficulties of Bankura are further intensified by its soil profile. The district is dominated by lateritic and red-yellow soils, both of which are products of prolonged weathering and leaching under tropical climatic conditions. These soils are typically acidic, deficient in essential nutrients such as nitrogen, phosphorus, and potassium, and contain low levels of organic carbon. Their coarse texture and hard-

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

crusting tendencies reduce water-holding capacity and restrict root penetration, making them unsuitable for intensive agriculture without intervention. As a result, large portions of cultivable land remain underutilized, seasonally abandoned, or converted into low-productivity scrublands. Such conditions have contributed to cycles of declining agricultural returns, land abandonment, and socio-economic vulnerability among farming communities.

Despite these constraints, degraded agricultural lands should not be viewed as permanently lost. Rather, they hold latent potential for restoration through context-sensitive planning, ecological engineering, and policy-supported interventions. The central premise of this research is that wastelands can be transformed into agro-productive systems if reclamation strategies are aligned with local geography, soil conditions, hydrological patterns, and socio-economic realities. This approach moves beyond traditional conservation methods by framing degraded land as a resource that can be rehabilitated into multifunctional landscapes—supporting food production, ecological restoration, and rural livelihoods simultaneously.

To operationalize this vision, the study adopts a multidisciplinary framework that integrates geospatial analysis, remote sensing, and field-based ecological strategies. Multi-spectral satellite imagery from Sentinel-2 and Landsat archives is employed to map and classify wasteland typologies across the district, including gullied land, fallow tracts, scrublands, and erosion-prone zones. These spatial datasets are combined with terrain, soil, rainfall, and vegetation indicators to build a comprehensive understanding of land capability. Through Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) and the Analytical Hierarchy Process (AHP), diverse variables are standardized and weighted to identify priority zones for intervention. This methodological approach enables the detection of “pockets of opportunity”—areas where restoration efforts are most likely to yield high ecological and socio-economic returns.

The findings of the study reveal that Bankura’s reclamation potential can be structured into three broad management zones, each requiring distinct intervention strategies. The western belt, characterized by severe degradation and fragile ecological conditions, is best suited for intensive ecological recovery measures such as agroforestry, contour trenching, and biomass regeneration. These practices aim to stabilize soils, reduce erosion, and restore ecosystem functions. The central belt functions as a transitional

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

zone where moderate degradation can be addressed through productivity-enhancing measures such as drought-resistant crops, integrated farming systems, and micro-irrigation. The eastern belt, relatively more stable and fertile, offers opportunities for agricultural optimization through high-value horticulture, crop diversification, and institutional strengthening through Farmer Producer Organizations.

A significant strength of this research lies in its alignment with existing policy frameworks. By connecting technical recommendations with national initiatives such as the Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana and state-level programs like the Usharmukti Project, the study ensures that its proposed framework remains actionable and scalable. Rather than presenting reclamation as an isolated technical exercise, the research situates it within a broader governance ecosystem where financial support, institutional convergence, and community participation are essential for long-term success.

Ultimately, this study contributes to the larger discourse on sustainable land management by demonstrating how degraded agricultural landscapes can be reimagined as resilient agro-ecosystems. Through the case of Bankura, it establishes that land restoration is not merely an environmental imperative but also a pathway toward rural transformation, climate adaptation, and socio-economic equity. The proposed framework offers a replicable model for other semi-arid and ecologically fragile regions facing similar challenges, reinforcing the idea that the future of agriculture depends not only on expanding cultivated area, but on restoring the productivity and dignity of the land already under stress.

TABLE OF CONTENTS

Contents

CHAPTER 1: INTRODUCTION AND BACKGROUND	11
1.1 The Global and National Imperative of Land Reclamation.....	11
1.2 Geographical Delineation: The Rarh Tract and Bankura's Landscape	14
1.2.1 Land Utilization in Bankura District	18
1.2.2 Agro-Ecological Contrast Across the District	21
1.2.3 Traditional Topographic Classification	21
1.3 Pedological Constraints and the Chemistry of Degradation.....	22
1.4 The Hydro-Climatic Paradox of the District	24
1.5 Socio-Economic Vulnerability and the Developmental Gap	29
1.5.1 The Land-Tenure Trap and Rental Burden.....	30
1.5.2 Labor, Wages, and the Cycle of Indebtedness	31
1.5.3 Migration as a Survival Strategy.....	32
1.5.4 Reclamation as a Pathway to Inclusive Development.....	33
1.6 Conceptualizing the Transformation Framework	34
1.6.1 A Multi-Disciplinary Integration	35
1.6.2 Site-Specific Ecological Interventions	35
1.6.3 Socio-Economic Alignment and Resilience	37
1.6.4 Toward a New Development Paradigm.....	38
CHAPTER 2: AIM, OBJECTIVES, AND RESEARCH QUESTIONS	38
2.1 Overarching Research Aim	39
2.2 Research Objectives.....	40
2.2.1 Objective 1: Systematic Parameter Identification and Database Compilation	40
2.2.2 Objective 2: Spatial Delineation and Prioritization via Geospatial Analysis...	40
2.2.3 Objective 3: Meta-Analysis of Reclamation Best Practices and Scalability	41
2.2.4 Objective 4: Formulation of Evidence-Based Site-Specific Strategies	41
2.3 Research Questions	42
2.3.1 Impediments and Spatial Distribution.....	42
2.3.2 Optimization of Geospatial Modeling	43
2.3.3 Adaptability of Proven Techniques.....	43

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A
CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

2.3.4 Institutional Sustainability and Climate Resilience	43
CHAPTER 3: LITERATURE REVIEW	45
3.1 Theoretical Framework of Land Degradation	46
3.2 Global and National Perspectives on Wasteland Taxonomy	47
3.3 Technological Interventions: Geospatial and RS Applications	48
3.3.1 Spectral Indices as Diagnostic Tools	49
3.3.2 Predictive Modeling of Erosion Hotspots.....	51
3.3.3 LULC as the decision making tool.....	51
3.4 Reclamation Strategies: Agroforestry and Watershed Management	53
3.4.1 Models for High-Temperature Resilience	53
3.4.2. Watershed Management as the Hydrological Backbone	54
3.4.3 Low-Cost, High-Impact Interventions	54
CHAPTER 4: POLICY ANALYSIS AND STRATEGIC CASE STUDIES	57
4.1 National Level Policy Frameworks	57
4.2 State Level Policy Frameworks (West Bengal).....	58
4.3 National Case Study 1: Rajnagar IWDP, Jharkhand	59
4.4 National Case Study 2: Neeranchal National Watershed Project (NNWP).....	60
4.5 International Case Study 1: Loess Plateau Rehabilitation, China	61
4.6 International Case Study 2: Farmer-Managed Natural Regeneration (FMNR), Sahel	62
4.7 Synthesis: A Policy-Driven Framework for Bankura	63
CHAPTER 5: PROFILE OF THE STUDY AREA – BANKURA DISTRICT	65
5.1 Geographical Location and Administrative Setup.....	65
5.2 Physical Environment and Physiography	68
5.3 Climatic Conditions and Hydrology	70
5.3.1 Thermal Variations and Air Quality	70
5.3.2 Cycle and Precipitation	70
5.3.3 Drought and Vulnerability	71
5.3.4 Flash Floods and Drainage.....	71
5.3.5 Ground Water Level Monitoring (2019-2022).....	72
5.4 Socio-Economic Structure and the Agrarian Economy.....	72
5.4.1 Regional Disparities in Soil and Productivity	72
5.4.2 The Challenge of Rain-fed Agriculture	73
5.4.3 Irrigation Infrastructure and Historical Systems	73
5.4.4 Principal Crops and Livestock.....	74

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A
CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

5.4.5 Modernization and Support Schemes	74
5.5 Land Transformation and the Wasteland Context	75
CHAPTER 6: METHODOLOGY- AN INTEGRATED GEOSPATIAL FRAMEWORK.....	78
6.1 Data Acquisition and Pre-processing	78
6.1.1 Remote Sensing Data and Image Restoration	78
6.1.2 Topographic Modeling via DEMs	79
6.1.3 Data Normalization and Spatial Integration	79
6.2 Geospatial Analysis and Feature Extraction	79
6.2.1 Land Use/Land Cover (LULC) Classification	80
6.2.2 Biophysical Indexing for Environmental Health.....	80
6.2.3 Proximity Analysis and Connectivity Modeling	80
6.3 Multi-Criteria Decision-Making (MCDM) Framework.....	81
6.3.1 Parameter Standardization and Reclassification	81
6.3.2 The Analytic Hierarchy Process (AHP) and Pairwise Comparison	81
6.3.3 Weighted Overlay and Composite Suitability Mapping	82
6.4 Synthesis and Zonation.....	82
CHAPTER 7: ANALYTICAL FRAMEWORK AND METHODOLOGY.....	84
7.1 Overview of the Analytical Approach	84
7.2 Spatial and Remote Sensing Analysis.....	84
7.2.1 Advanced Spectral Indexing	85
7.2.2 Topographic Modeling and Geomorphology	89
7.2.3 Hydrological Flow and Watershed Simulation.....	89
7.3 Structured Decision-Making: The Analytical Hierarchy Process (AHP)	89
7.4 Economic Feasibility and Policy Integration	90
7.4.1 Cost-Benefit Analysis and Financial Sustainability	91
7.4.2 Regulatory Alignment and Zoning Compliance	91
7.4.3 Synergy with Government Programs and Subsidies	91
CHAPTER 8: ANALYSIS AND FINDINGS- DETAILED ASSESSMENT.....	93
8.1 The Western High-Risk Zone.....	95
8.2 The Central Transitional Buffer	96
8.3 The Eastern Productive Zone	97
8.4 Synthesis: A Differentiated Strategy for Resilience	98
CHAPTER 9: PROPOSALS AND STRATEGIES: A COMPREHENSIVE FRAMEWORK.....	100
9.1 Spatial Zonation via GIS-Based Suitability Analysis.....	100
9.1.1 Zone I: Intensive Ecological Recovery	100

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A
CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

9.1.2 Zone II: Productivity Enhancement	101
9.1.3 Zone III: Optimization and Market Integration	101
9.2 Integrated Planning Approaches	102
9.3 Strategic Outcomes	103
9.3.1 Environmental Resilience and Ecological Restoration	103
9.3.2 Economic Growth and Livelihood Security	103
9.3.3 Proactive Governance: The Disaster Management 2.0 Shift.....	104
CHAPTER 10: EXPANDED IMPLEMENTATION FRAMEWORK: A MULTI-DIMENSIONAL STRATEGY	105
10.1 Phased Implementation Roadmap	105
10.1.1 Phase I: Foundational Stabilization (0–2 Years)	106
10.1.2 Phase II: Productivity Enhancement and Scaling (2–5 Years).....	106
10.1.3 Phase III: Systemic Sustainability and Resilience (5+ Years)	107
10.2 Stakeholder Collaboration and Institutional Synergy	107
10.2.1 Government Agencies as Strategic Facilitators	108
10.2.2 Local Institutions and Community Leadership	108
10.2.3 Technical, Academic, and Private Sector Partnerships	109
10.3 Financial Mobilization Strategy	109
10.3.1 Public Financing and Government Synergy	110
10.3.2 Institutional Funding and International Climate Finance	110
10.3.3 Community Contributions and "Sweat Equity"	111
10.4 Integrating Dimensions for Sustainability	111
10.4.1 The Technical Dimension: Science and Scalability	112
10.4.2 The Institutional Dimension: Capacity and Governance	112
10.4.3 The Social Dimension: Inclusion and Cultural Resonance	112
CHAPTER 11: CONCLUSION AND FUTURE DIRECTIONS	114
11.1 Pilot-Scale Validation and Site-Specific Testing	114
11.2 Longitudinal Monitoring and Bio-Physical Recovery	114
11.3 Socio-Economic Impact and Policy Synergy	114
11.4 Advanced Technological Integration	115

CHAPTER 1: INTRODUCTION AND BACKGROUND

1.1 The Global and National Imperative of Land Reclamation

Across the world, the condition of land has emerged as one of the defining environmental concerns of the twenty-first century. Productive landscapes that once sustained communities, biodiversity, and economic systems are increasingly being degraded through unsustainable agricultural practices, deforestation, excessive resource extraction, urban expansion, and climate-induced stress. Land degradation is not simply the visible erosion of soil or the abandonment of barren fields; it is the gradual weakening of the ecological systems that support human civilization. When land loses its capacity to regenerate, the consequences ripple outward—affecting food production, water security, livelihoods, and the long-term resilience of entire regions.

At the global level, this challenge has taken on unprecedented urgency. Rapid population growth and changing consumption patterns have intensified pressure on finite land resources, pushing ecosystems beyond their natural carrying capacities. In many parts of the world, particularly in drylands, tropical belts, and semi-arid regions, soils are being depleted faster than they can recover. Agricultural intensification, while initially boosting productivity, has often come at the cost of soil fertility, biodiversity loss, and declining ecosystem health. The result is a growing imbalance between human demand and ecological renewal. This imbalance is not only environmental in nature; it has become deeply interconnected with broader humanitarian and geopolitical issues. Declining agricultural productivity contributes to food price instability, economic vulnerability, forced migration, and, in some contexts, competition over shrinking natural resources.

Recognizing the scale of this crisis, international institutions and national governments have increasingly positioned land restoration at the center of sustainable development agendas. Initiatives aligned with the United Nations Sustainable Development Goals, particularly those related to climate action, life on land, and zero hunger, emphasize the urgent need to reverse degradation trends. The concept of Land Degradation Neutrality has emerged as a critical policy objective, advocating that any future degradation must be balanced by restoration and reclamation efforts elsewhere. This approach reflects a

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

broader understanding that the health of land is inseparable from the health of economies, communities, and ecosystems.

In India, the imperative of land reclamation carries even greater significance due to the country's demographic and economic realities. A substantial proportion of India's population continues to depend directly or indirectly on agriculture and allied sectors for income and sustenance. Unlike economies where agriculture represents a smaller share of employment, rural India remains closely tied to the productivity of its land. Consequently, when land becomes degraded or unproductive, the effects are immediate and deeply felt. Reduced yields translate into lower household incomes, increased indebtedness, and heightened vulnerability among already marginalized communities. Land degradation, therefore, is not an isolated environmental issue—it is a structural development challenge with direct implications for rural welfare and national food security.

India's agricultural wastelands must be understood within this larger framework. These lands are not merely barren spaces devoid of use; they are often the outcome of long-term ecological stress combined with unsustainable land management practices. Over-irrigation, monocropping, excessive dependence on chemical fertilizers, deforestation, and poor watershed planning have all contributed to the decline of land productivity across different agro-climatic regions. In many cases, these human-induced pressures interact with natural vulnerabilities such as salinity, acidity, erosion, or low water retention, accelerating degradation processes. What emerges is a landscape where large tracts of land remain underutilized despite their latent productive potential.

The case of the Rarh region in eastern India, particularly districts such as Bankura, illustrates this dynamic vividly. Here, the dominance of lateritic and acidic soils, coupled with erratic rainfall and undulating topography, creates inherent constraints for conventional agriculture. However, these physical limitations are often worsened by historical neglect, fragmented landholdings, and inadequate infrastructure. As a result, significant portions of the region remain trapped in cycles of low productivity and rural distress. Yet these same landscapes also hold opportunities for transformation when approached through restorative and context-sensitive planning.

The national policy shift toward Land Degradation Neutrality reflects an important evolution in thinking. Traditional approaches often emphasized conservation—

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

protecting what remains of productive ecosystems. While conservation remains essential, it is no longer sufficient in a context where degradation has already affected millions of hectares. The emerging paradigm prioritizes proactive transformation: restoring damaged landscapes, reclaiming wastelands, and reintegrating them into productive systems. This shift acknowledges that sustainable development cannot be achieved solely by preserving existing assets; it also requires rehabilitating lands that have been excluded from mainstream planning.

Reframing wastelands as “marginal assets” rather than “lost causes” is central to this transition. Such a perspective recognizes that degraded lands can be reimagined as spaces for agroforestry, horticulture, regenerative agriculture, biomass generation, and climate-resilient livelihoods. For landless laborers, marginal farmers, and rural youth, reclaimed land can become a source of employment and community resilience. In this sense, land reclamation is not only an ecological intervention but also a mechanism of social equity and rural empowerment.

Expanding the imperative of reclamation requires a multi-dimensional strategy. Scientific tools such as remote sensing, GIS-based monitoring, and soil analytics are essential for identifying vulnerable zones and designing evidence-based interventions. At the same time, local knowledge systems—particularly those rooted in traditional water harvesting, mixed cropping, and community resource management—must be integrated into planning frameworks. Effective reclamation depends on institutional flexibility, allowing policies to adapt to local ecological realities rather than imposing one-size-fits-all solutions.

Water management also becomes a critical pillar of this transformation. In many degraded regions, land productivity is closely tied to the availability and retention of water. Decentralized structures such as check dams, farm ponds, contour bunds, and recharge pits can restore hydrological balance while improving soil moisture regimes. When combined with vegetation-based approaches like agroforestry and afforestation, such interventions rebuild both ecological stability and agricultural potential.

Ultimately, the goal of land reclamation extends beyond restoring soil fertility. It is about reviving the biological intelligence of the land—the interconnected processes of nutrient cycling, carbon sequestration, water filtration, and biodiversity support that sustain healthy ecosystems. These processes form the invisible foundation of resilient

economies and societies. By investing in land restoration, nations secure not only their agricultural future but also their environmental and developmental stability.

In this broader context, land reclamation emerges as one of the most urgent and transformative agendas of our time. It addresses ecological degradation, strengthens food systems, reduces rural vulnerability, and contributes to climate resilience. For countries like India, where land remains central to both livelihoods and identity, reclamation is not an optional intervention—it is a national necessity and a pathway toward a more equitable and sustainable future.

1.2 Geographical Delineation: The Rarh Tract and Bankura's Landscape

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A
CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL



DYNAMIC GROUNDWATER RESOURCES DISTRICT BANKURA



Fig. 1: Dynamic Groundwater Resources

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

The district of Bankura occupies a unique and strategically important position within the western margins of West Bengal. It lies at the meeting point of two contrasting physiographic worlds: the ancient crystalline uplands of the Chotanagpur Plateau to the west and the younger, sediment-rich alluvial plains of the Bengal Basin to the east. This transitional setting gives Bankura its distinct environmental identity and places it within the broader cultural-geographical zone known as the Rarh tract. The term “Rarh” historically refers to the undulating lateritic landscapes of western Bengal—an ecological region marked by rugged terrain, red soils, and a climate that often oscillates between abundance and scarcity.

This transitional geography makes Bankura more than just another administrative district; it is a threshold landscape. Here, the rough stony character of the plateau gradually softens into the flatter, water-retentive expanses of the deltaic plains. The district can be understood as a natural staircase—each step reflecting a gradual descent from the elevated western uplands toward the eastern agricultural lowlands. This geomorphic progression defines not only the district’s physical structure but also its agricultural patterns, settlement forms, and socio-economic dynamics.

The western portion of Bankura represents the first and most rugged phase of this transition. It consists of spurs and outliers extending from the plateau system, marked by broken ridges, rocky uplands, and isolated hill masses. Notable peaks such as Susunia Hill and Biharinath Hill stand as dominant geomorphic landmarks in this region. These hills are not only scenic features but also indicators of the district’s geological inheritance. The terrain here is highly dissected, with shallow soils, exposed laterite, and significant relief variation. Agricultural activity in this tract is naturally constrained by slope, low soil fertility, and limited water retention.

Moving eastward, the landscape begins to moderate. The pronounced undulations of the western uplands give way to rolling downs and gentler slopes. This central zone functions as a transitional belt, both geographically and agriculturally. It retains some of the lateritic character of the west while gradually incorporating more productive soils and flatter terrain. The central tract is often the site of mixed land-use systems, where agriculture, grazing, and woodland coexist in a delicate balance.

Further east and northeast, the terrain flattens considerably and merges into the low-lying alluvial plains that resemble the broader agrarian landscapes of Bengal. Here, the

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

soils are finer, deeper, and more moisture-retentive, making them far more suitable for intensive cultivation. These plains support extensive rice cultivation and present a visual contrast to the rocky uplands of the west. The shift from stone-dominated ridges to fertile silty fields is one of the defining environmental transitions of Bankura and underpins the district's agricultural diversity.

The hydrology of Bankura is deeply influenced by this topographic arrangement. Numerous rivers and streams traverse the district, generally flowing from the north-west to the south-east, following the natural slope of the land. Yet, despite the presence of drainage channels and seasonal rainfall, the district faces a persistent paradox of water scarcity. The undulating topography promotes rapid surface runoff, especially in upland areas where soils are shallow and compact. Rainwater is quickly shed into lower valleys and river systems, leaving the higher tracts vulnerable to moisture stress.

This natural tendency toward runoff has historically shaped local adaptation strategies. Communities in Bankura developed decentralized water-harvesting systems to intercept and store rainwater before it escaped the landscape. Traditional embankments, locally known as *bandhs*, were constructed across slopes and depressions to retain seasonal drainage for irrigation and domestic use. These structures represent an important example of indigenous ecological engineering—an approach that aligns with the terrain rather than attempting to override it. Even today, such traditional systems remain relevant in discussions of climate resilience and sustainable land management.

The district's ecological diversity is mirrored in its visual character. In the eastern plains, the scenery is dominated by wide stretches of rice fields, interspersed with bamboo groves, mango orchards, and village settlements. This landscape evokes the familiar imagery of fertile lower Bengal. In contrast, the western uplands are characterized by ferruginous soils, lateritic crusts, scrub vegetation, and patches of regenerating Sal tree forest. Extensive deforestation and land degradation have left large areas denuded, exposing hard, compact red surfaces that intensify under the sun. The visual transition from lush plains to stark uplands captures the environmental duality of Bankura—a district where fertility and fragility coexist in close proximity.

1.2.1 Land Utilization in Bankura District

The current land-use structure of Bankura reflects this environmental complexity. Out of a total geographical area of 6,88,100 hectares, agriculture remains the dominant land use, with net sown area accounting for over half of the district's territory. However, significant portions of land remain under forests, non-agricultural uses, fallows, and agricultural wastelands.

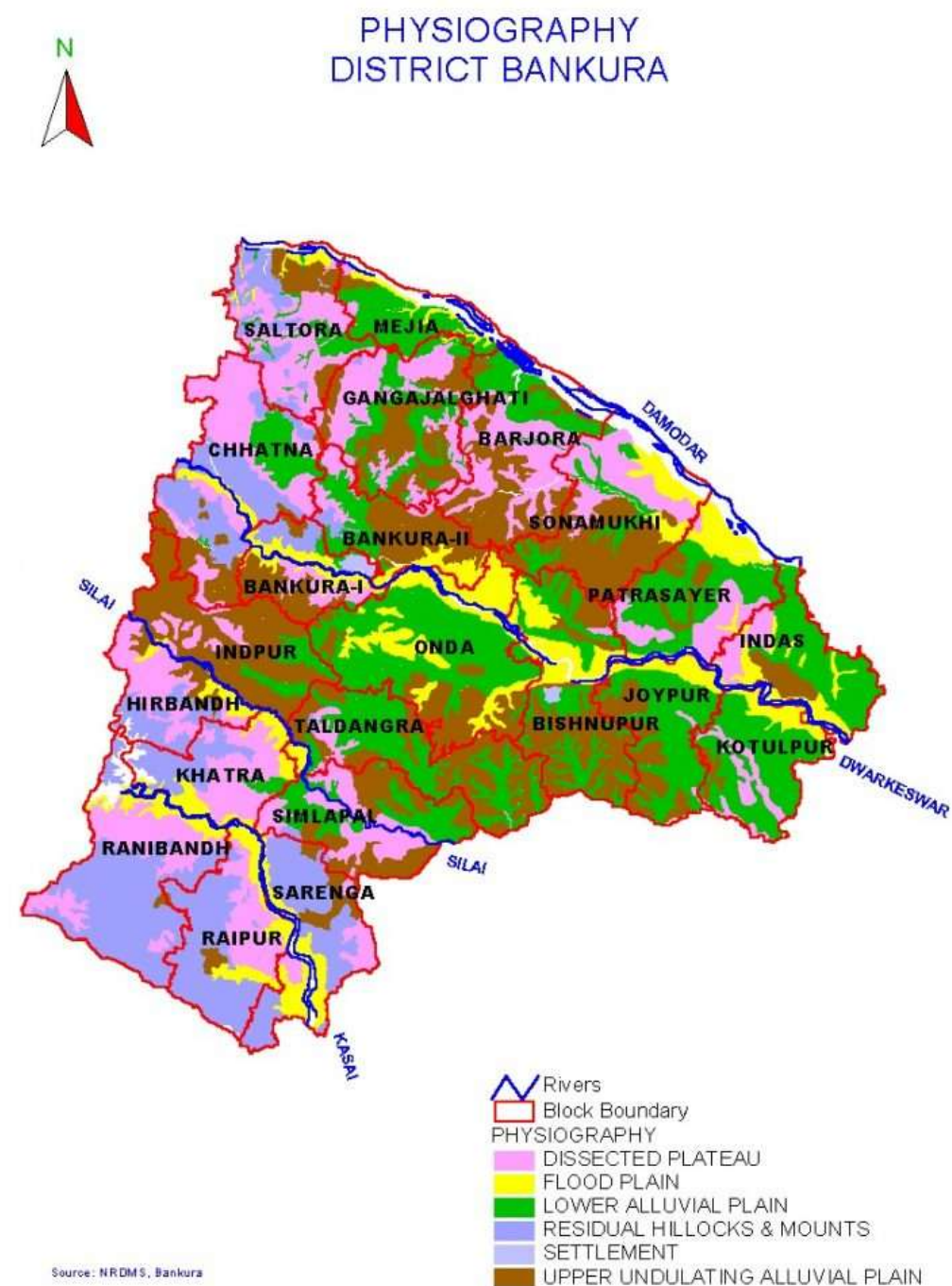


Fig. 2: Physiography

Land Use Category	Area (in Hectares)	Percentage of TGA
-------------------	--------------------	-------------------

**TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A
CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL**

Total Geographical Area (TGA)	6,88,100	100.00%
Forest Area	1,48,350	21.56%
Agricultural Wasteland (Culturable Waste)	11,703	1.70%
Fallow Land (Current & Others)	27,581	4.01%
Net Sown Area	3,56,904	51.87%
Area Under Non-Agricultural Use	1,09,621	15.93%

Table 1: Land Utilization Statistics of Bankura District

Source: Adapted from District Statistical Handbook, Bankura (2023) and Government of West Bengal Agriculture Department

**Land Utilisation Statistics - Bankura District
(Total Geographical Area: 6,88,100 ha)**

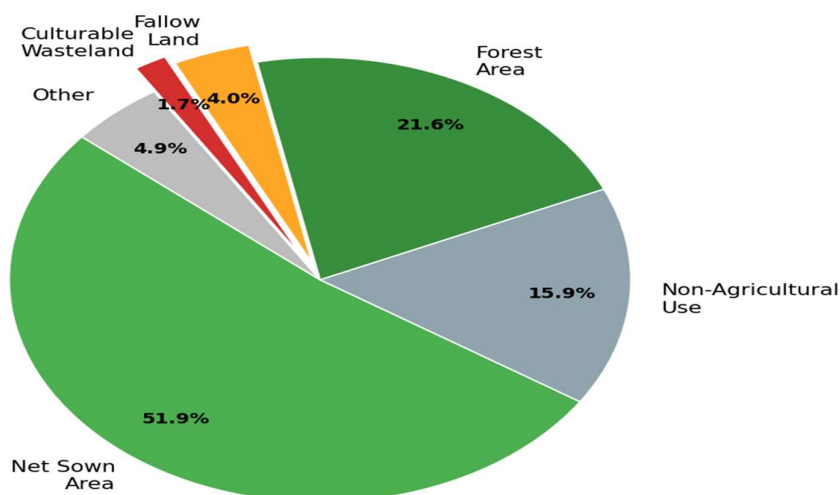


Figure 3: Proportional Land Use Distribution — Bankura District

These figures demonstrate that while a substantial share of land is actively cultivated, a notable portion remains underutilized or ecologically constrained. This reinforces the need for strategic reclamation and land-use optimization, particularly in marginal tracts where productivity remains low.

1.2.2 Agro-Ecological Contrast Across the District

Bankura's internal variation is especially evident when comparing its western uplands and eastern plains.

Feature	Western Uplands (e.g., Saltora)	Eastern Plains (e.g., Kotulpur)
Topography	Highly Undulating	Nearly Flat
Dominant Soil	Lateritic / Red Soil	Alluvial
Irrigation Source	Rainfed / Minor Lift	Canal / Deep Tubewell
Wasteland Extent	High	Low
Cropping Intensity	~120%	~190%

Table 2: Comparison of Agro-Ecological Characteristics

The contrast highlights the unequal distribution of agricultural opportunity within the district. While eastern areas benefit from irrigation infrastructure and fertile soils, western blocks remain dependent on rainfall and face higher vulnerability to degradation.

1.2.3 Traditional Topographic Classification

A defining feature of Bankura's rural geography is its traditional land classification system, which reflects the intimate relationship between terrain, soil, and agricultural practice.

Land Type	Topographic Position	Soil Characteristics	Primary Land Use
Tanr	Upland / Ridge Top	High drainage, gravelly, lateritic, nutrient-poor	Often fallow, forestry, hardy crops
Baid	Intermediate Slope	Moderate drainage, sandy loam to clay loam	Single-crop cultivation, mainly Kharif rice
Kanali	Valley Bottom	Poor drainage, high moisture retention, fertile clayey/alluvial soil	Intensive rice cultivation, vegetables

Table 3: Schematic Representation of the Topographic Sequence

This indigenous classification remains highly relevant because it captures the functional logic of the landscape. It provides a localized understanding of agricultural suitability and continues to inform land-use decisions in many villages.

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

In essence, Bankura is a district defined by gradients—of elevation, fertility, water availability, and opportunity. Its geographical complexity is both a challenge and an asset. Understanding this layered landscape is essential for any meaningful strategy of land reclamation and agro-productive transformation. The Rarh tract is not simply a region of environmental hardship; it is a living system whose resilience depends on aligning development interventions with the realities of its terrain.

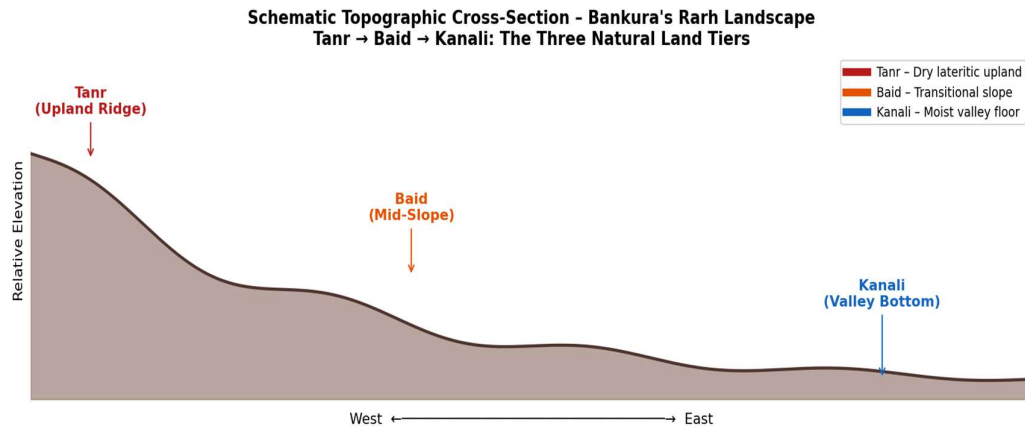


Fig. 4. Schematic Topographic Sequence of Bankura District

1.3 Pedological Constraints and the Chemistry of Degradation

The dominant soil profile of Bankura is defined by lateritic and red-yellow soils, which are the geological products of intense, long-term leaching processes under seasonal tropical conditions. This weathering, driven by the alternating wet and dry seasons characteristic of the region, strips the soil of its basic cations and silica, leaving behind a residuum rich in insoluble oxides. These soils are inherently problematic for intensive agriculture due to their highly acidic nature and the heavy presence of iron and aluminum oxides, which often give the landscape its distinctive ochre and deep red hues. The chemical composition of the Rarh tract reflects a landscape in a state of advanced pedological exhaustion, where the natural fertility has been washed away over millennia.

The lack of essential macronutrients—specifically nitrogen, phosphorus, and potassium—creates a significant hurdle for rural productivity. Coupled with extremely low organic carbon content, the soil presents a hostile environment for most traditional cereal crops, which require a more balanced and nutrient-rich substrate to thrive.

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

Because the soil is unable to naturally replenish these vital components, the agricultural cycle is often forced into a state of stagnation without heavy, and sometimes prohibitively expensive, external fertilization. This nutrient deficiency is not merely a chemical fluke but a structural reality of the "Rarh" identity, where the ground itself offers little sustenance to the seeds planted within it.

Furthermore, the physical structure of lateritic soil in Bankura is often characterized by a severe hard-crusting tendency upon exposure to the sun. This process, often referred to as induration, creates a literal "stone-skin" over the earth that prevents deep root penetration and significantly reduces the soil's water-holding capacity. When the monsoon rains arrive, the water often skims across this hardened surface rather than infiltrating the subsoil, leading to the rapid surface runoff and moisture deficit previously noted in the geographical profile. The soil's inability to act as a sponge means that plants are frequently subjected to "physiological drought" even in areas with statistically adequate rainfall.

These combined chemical and physical barriers transform vast tracts of the district into what are effectively "agricultural wastelands." Despite their potential for alternative land uses, such as social forestry or the cultivation of hardy silvicultural species, these lands remain fallow for the majority of the year. The degradation of the soil is a self-reinforcing cycle; without vegetative cover to provide organic matter, the soil continues to bake and harden, further entrenching the district's reputation as a difficult terrain for sustenance. Understanding these pedological constraints is essential for any development strategy aiming to enhance the rural infrastructure or economic output of the Dhar or Bankura regions.

Parameters	Range/Value	Remark
Soil pH (Acidity)	5.0 – 6.5	Strongly to Moderately Acidic
Organic Carbon (%)	0.16% – 0.41%	Very Low (Deficient)
Water Holding Capacity	29.05% – 37.11%	Poor (High Porosity)
Available Nitrogen	Low	Requires substantial amendment
Bulk Density (g/cm ³)	1.24 – 1.38	High (Risk of crusting)

Table 4: Physico-Chemical Properties of Lateritic Soils in Bankura

Source: Compiled from International Journal of Bio-resource and Stress Management (2026) data.

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

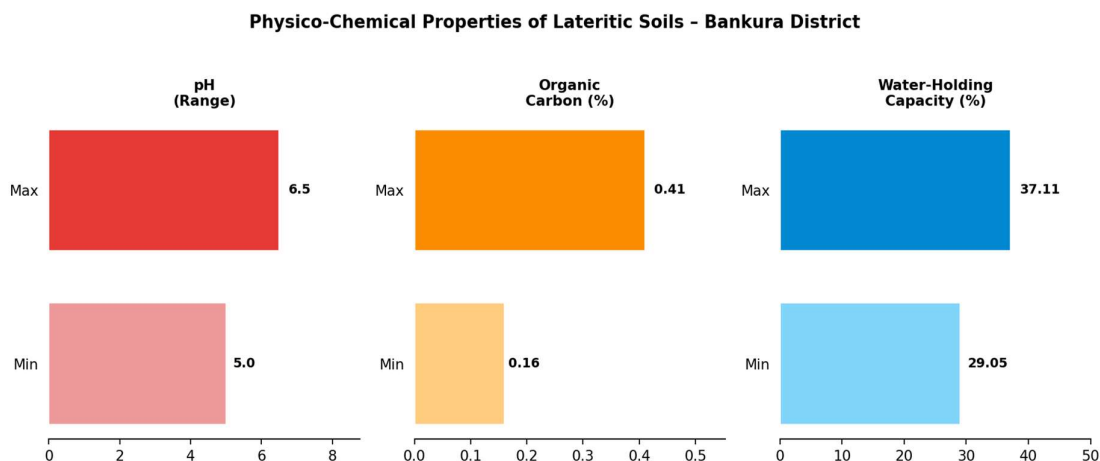


Fig. 5: Comparison of Key Physico-Chemical Soil Parameters — Minimum vs.
Maximum Observed Values

1.4 The Hydro-Climatic Paradox of the District

The environmental story of Bankura is shaped by a striking contradiction—one that defines the district’s agricultural uncertainty and ecological vulnerability. On paper, Bankura receives a moderate amount of annual rainfall, largely concentrated during the southwest monsoon. Such figures might suggest that the district should possess sufficient water resources to sustain agriculture and rural livelihoods. Yet, in reality, Bankura is widely recognized as a drought-prone region. This disconnect between statistical rainfall and lived water scarcity forms what can best be described as the district’s hydro-climatic paradox.

At the heart of this paradox lies the uneven distribution of rainfall in both time and space. Rainfall in Bankura is not spread evenly across the year; instead, it arrives in short, intense bursts during a limited monsoon window. These episodes often deliver substantial volumes of water over a few days or weeks, creating temporary abundance. However, this abundance is deceptive. Because the rains are highly concentrated, the land experiences brief inundation followed by prolonged dry periods. The result is a cycle in which the district may appear water-rich during the monsoon but remains moisture-deficient for most of the agricultural year.

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A
CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

This phenomenon creates a transition from meteorological drought to agricultural drought. A meteorological drought occurs when rainfall is below average or irregular in distribution. In Bankura, even years with near-normal rainfall totals can experience agricultural drought because crops depend not only on how much rain falls, but on when it falls and how effectively the land can retain it. If rains arrive too late, too early, or in highly erratic intervals, the agricultural calendar is disrupted. Crops fail to establish, soil moisture declines rapidly, and farmers face uncertainty despite seemingly adequate seasonal rainfall.

The district's physical geography intensifies this challenge. Bankura's position within the Rarh tract places it on a natural slope descending from the Chotanagpur Plateau toward the Bengal Basin. This north-west to south-east gradient creates an inherent tendency for water to move quickly across the landscape rather than remain within it. Combined with the district's lateritic and red-yellow soils—which often develop compact, hard-crustured surfaces—this topography limits infiltration and groundwater recharge.

Instead of soaking into the earth, rainwater frequently rushes across the surface as runoff. During this process, it not only escapes the landscape but also strips away fertile topsoil through sheet erosion. The land, therefore, loses both water and nutrients in a single event. What should have been an ecological resource becomes a mechanism of degradation. The upland tracts, especially the *Tanr* zones, are left with minimal residual moisture after the monsoon, entering the dry season in a state of chronic deficit.

This explains why Bankura often presents a scorched and arid appearance during summer months, even if heavy rainfall occurred earlier in the year. The issue is not the absence of rain alone, but the inability of the landscape to store and regulate water over time. In hydrological terms, the district functions less like a reservoir and more like a rapid drainage channel.

The behavior of the district's rivers further illustrates this volatility. Major river systems such as the Damodar River and the Kangsabati River are central to the region's hydrology, yet they do not provide stable year-round security. These are largely rain-fed rivers, lacking perennial glacial sources. During the peak monsoon, they can swell dramatically, carrying large volumes of water and causing sudden floods. Entire stretches of otherwise dry land may transform into inundated zones within hours.

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

However, this apparent abundance is seasonal and short-lived. As the rains recede, river discharge declines sharply. In the dry months, many channels shrink into narrow streams or dry sandy beds. For surrounding communities, this means that the visible presence of a river does not necessarily translate into reliable access to water. The rivers are abundant when they are least needed and scarce when agricultural demand is highest.

This “flashy” hydrological character creates a second layer of risk. During the monsoon, floodwaters may deposit sand and debris across bordering fields, rendering them less productive or even temporarily uncultivable. Thus, communities face a dual threat: too much water in concentrated periods and too little during the remainder of the year.

Historically, local populations responded to this volatility with adaptive water-management strategies. Traditional embankments, known as *bandhs*, were constructed across slopes and hollows to capture seasonal runoff for later use. These decentralized systems reflected a deep understanding of the district’s hydro-climatic realities. By slowing water movement and encouraging local storage, they provided a modest but vital buffer against dry spells.

Yet, as climatic variability increases and agricultural demands intensify, these localized systems alone are often insufficient. Many have deteriorated due to neglect, while others lack the scale needed to support expanded cultivation. The absence of robust, decentralized water-harvesting infrastructure remains one of the district’s most significant developmental bottlenecks.

The consequences are especially evident in upland agricultural systems. The *Tanr* lands, with their poor water retention, rarely sustain a second crop beyond the immediate monsoon season. Without supplemental irrigation, farmers remain dependent on a single winter rice crop, which dominates the agricultural calendar. This dependence reduces diversification, limits income opportunities, and increases vulnerability to monsoon failure.

In effect, the hydro-climatic paradox drives both ecological fragility and economic risk. Farmers must make decisions under conditions of uncertainty, where the success of an entire season depends on rainfall timing, soil moisture retention, and access to stored

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A
CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

water. Investing in seeds, labor, or inputs becomes a calculated gamble. When rains fail or arrive erratically, losses can be immediate and severe.

This uncertainty often encourages defensive agricultural strategies—low-input, low-risk cultivation methods that prioritize survival over productivity. While understandable, such strategies can also perpetuate low yields and underutilization of land resources. Over time, repeated failures may lead to land abandonment, seasonal migration, or debt accumulation, further weakening rural resilience.

Bankura's paradox, therefore, is not simply a matter of climate—it is a systemic interaction between rainfall patterns, geomorphology, soil properties, and infrastructural gaps. It is a land where rivers run dry when needed most, where rainfall arrives in abundance only to disappear before it can be used, and where water insecurity persists despite seasonal surpluses.

Understanding this paradox is essential for designing effective reclamation and agricultural transformation strategies. Solutions must move beyond rainfall dependency and toward integrated watershed management, decentralized storage systems, groundwater recharge, and climate-resilient cropping models. Only by treating water as a managed resource—rather than a seasonal gift—can the district break free from its cycle of alternating flood and drought.

In this sense, the hydro-climatic paradox of Bankura is not merely an environmental condition; it is the defining challenge around which the district's future must be planned.

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

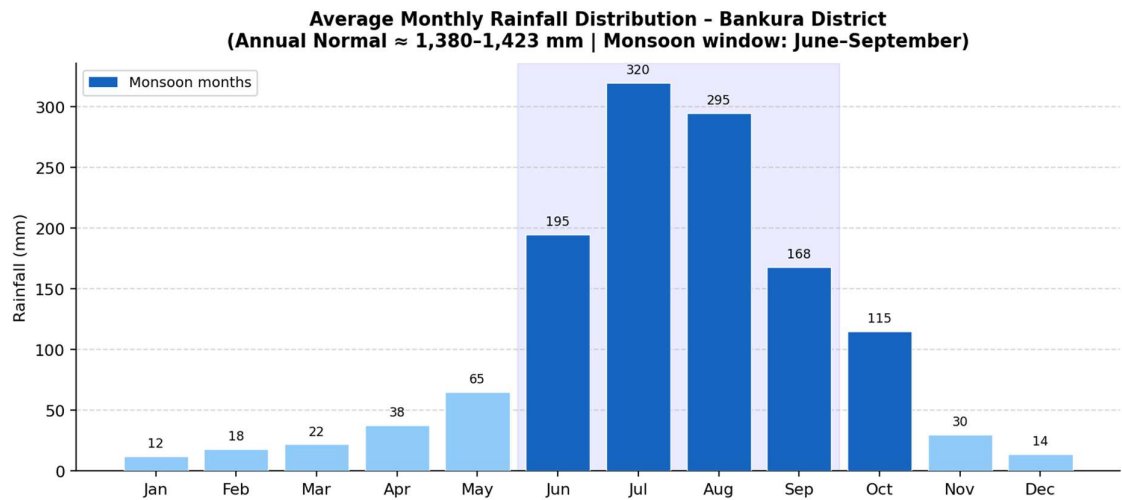


Fig. 6: Average Monthly Rainfall Distribution — Bankura District (Approx. Values; Monsoon Window: Jun–Sep)

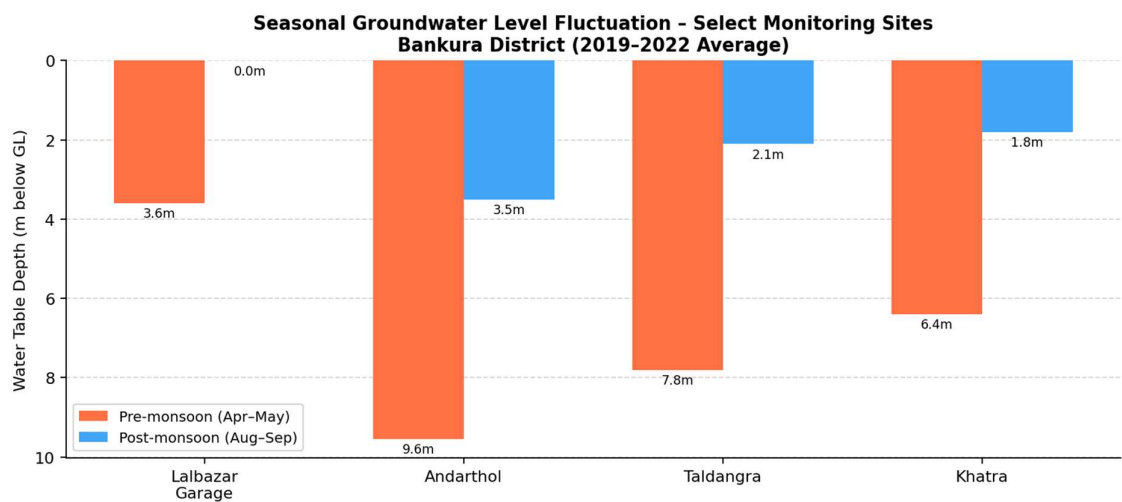


Fig. 7: Seasonal Groundwater Level Fluctuation at Select Monitoring Sites, Bankura (2019–2022 Average) — Depth Increases Downward

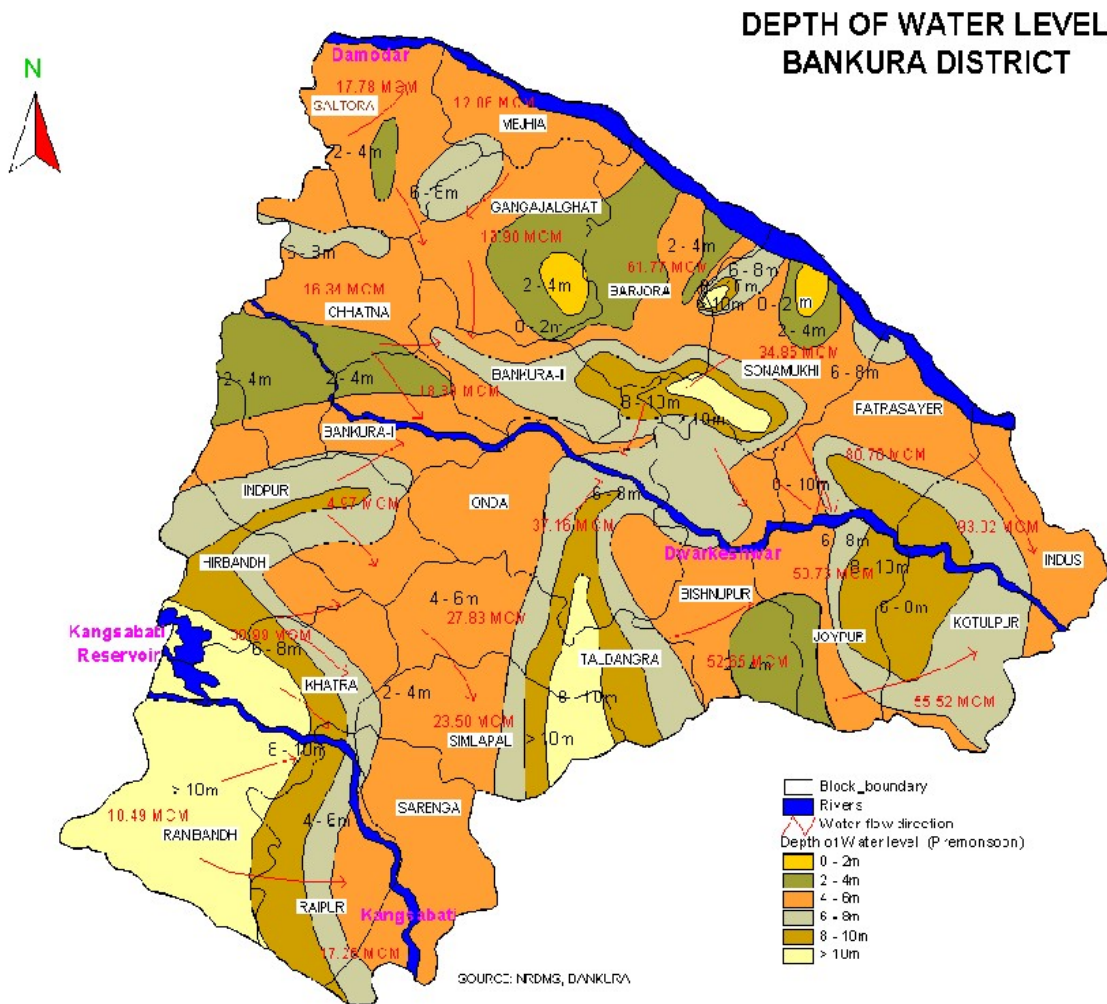


Fig. 8: Premonsoon Depth of Water Level in Bankura

1.5 Socio-Economic Vulnerability and the Developmental Gap

The challenge of agricultural wastelands in Bankura is not only a question of soil, water, or climate. At its core, it is also a deeply social and economic issue. Landscapes do not become unproductive in isolation; they reflect the lived realities of the people who depend on them. In Bankura, the persistence of degraded and underutilized land is closely tied to structural vulnerabilities within the rural economy—limited capital, insecure land access, indebtedness, and the constant uncertainty of agricultural returns.

For many farming households, the land is both livelihood and inheritance. Yet ownership alone does not guarantee productivity. The district is dominated by small and marginal farmers whose holdings are often fragmented and insufficient to sustain a

family throughout the year. These farmers operate with minimal financial reserves and limited access to institutional credit. As a result, they are rarely in a position to invest in long-term land improvement measures such as soil conditioning, irrigation infrastructure, mechanization, or diversified cropping systems.

This lack of investment capacity creates a self-reinforcing cycle. Poor soils and unreliable water reduce agricultural output; low output limits income; low income prevents reinvestment into the land. Over time, the land becomes less productive, and the household becomes more vulnerable. The result is not only environmental decline but also social stagnation.

In this context, unproductive land becomes both a symptom and a driver of rural underdevelopment. Fields that remain fallow or yield poorly contribute little to household security, forcing families to seek supplementary livelihoods elsewhere. The able-bodied workforce—particularly younger men and increasingly women—often migrates seasonally to neighboring districts or states in search of wage labor. This migration may provide short-term survival, but it also reduces the local labor available for maintaining farms, irrigation systems, and community infrastructure. The land, left with fewer hands to care for it, deteriorates further.

Thus, ecological decline and economic distress are intertwined. Reclaiming wastelands is not merely a technical intervention for improving soil health—it is a developmental necessity for stabilizing rural livelihoods and reducing structural inequality. When marginal lands are converted into agro-productive systems such as dryland horticulture, agroforestry, integrated farming, or social forestry, they create local employment opportunities while strengthening ecological resilience. In doing so, they offer communities a pathway out of poverty and dependency.

1.5.1 The Land-Tenure Trap and Rental Burden

One of the most significant contributors to socio-economic vulnerability in rural Bankura is the nature of land tenure. Historically, access to cultivable land has been mediated through ownership hierarchies, tenancy arrangements, and informal agreements that often disadvantage the actual cultivator. While legal reforms have

altered many formal structures, the broader dynamics of insecurity and unequal returns continue to shape agricultural livelihoods.

For households without sufficient owned land, tenancy or sharecropping remains the primary route into cultivation. However, these arrangements frequently leave tenants with only a fraction of the final produce. In traditional *bhag jot* systems, the tenant may surrender half of the harvest as rent even when they provide their own labor, seeds, and draft power. If the landowner contributes key inputs, the cultivator's share may decline further.

Such systems severely restrict the ability of tenant farmers to accumulate surplus. Even in productive years, a substantial portion of output is diverted before it reaches the household economy. This leaves little room for savings, reinvestment, or resilience against future shocks. Agriculture under such conditions becomes a subsistence activity rather than a pathway to advancement.

Temporary and informal landholding arrangements also contribute to instability. Households cultivating short-term leased land are less likely to invest in soil improvement or long-term productivity measures because they lack security over future access. Why spend scarce resources improving land that may not remain under one's control? This uncertainty discourages sustainable practices and perpetuates extractive, short-term cultivation strategies.

The result is what can be described as a land-tenure trap—where insecure access to land prevents investment, and the absence of investment keeps productivity low.

1.5.2 Labor, Wages, and the Cycle of Indebtedness

Agricultural labor in vulnerable rural economies is often undervalued, irregular, and closely tied to seasonal harvest cycles. In Bankura, labor opportunities fluctuate sharply throughout the year, with demand concentrated during sowing and harvesting periods. Outside these windows, employment becomes scarce, forcing workers to seek alternative livelihoods or remain underemployed.

Low and unstable wages deepen household vulnerability. In many cases, payment for labor has historically been made partly in kind rather than cash, linking workers directly

to immediate harvest outcomes instead of long-term financial security. While such systems may ensure subsistence, they do little to support savings or asset accumulation.

This financial fragility drives households toward borrowing. Farmers frequently require loans for seeds, fertilizers, labor payments, or household expenses during lean periods. However, access to formal banking remains limited for many marginalized cultivators, especially those lacking collateral or clear land titles. Consequently, they turn to informal lenders—moneylenders, traders, or local intermediaries.

The terms of such borrowing are often exploitative. High interest rates, repayment in produce, and unequal contracts can lock households into chronic indebtedness. A single failed crop may force repeated borrowing, turning short-term credit into long-term dependency.

This debt burden has wider consequences for land productivity. Surplus that could have been reinvested into irrigation, soil enhancement, or improved seeds is instead diverted toward servicing loans. The farm remains undercapitalized, productivity remains stagnant, and vulnerability persists. In this way, indebtedness becomes not only a financial issue but also an ecological one—preventing the very investments needed to restore degraded landscapes.

1.5.3 Migration as a Survival Strategy

In regions where agriculture cannot reliably sustain livelihoods, migration becomes a necessary coping mechanism. In Bankura, seasonal migration has long served as a survival strategy for vulnerable households, particularly among marginalized communities such as the Santal and Bauri populations.

Workers often travel to more agriculturally prosperous districts for harvesting work, construction, brick kilns, or industrial labor. Others move to mining belts, tea plantations, or urban centers in search of temporary employment. These movements are not driven by opportunity alone; they are often compelled by ecological uncertainty and insufficient local income.

While migration can provide essential remittances, it also carries social and developmental costs. Families are separated, children may face disruptions in

education, and village communities lose productive labor during critical agricultural periods. Moreover, the outflow of working-age individuals weakens the collective capacity to maintain common resources such as ponds, embankments, and irrigation systems.

This creates a feedback loop: degraded land drives migration, and migration reduces the labor available to rehabilitate the land.

Over time, migration shifts from a temporary adaptation to a normalized livelihood pattern, reinforcing the perception that agriculture alone is inadequate. Rural development, then, cannot focus solely on productivity—it must also address the structural conditions that make migration a necessity rather than a choice.

1.5.4 Reclamation as a Pathway to Inclusive Development

Transforming marginal lands into productive systems offers far more than environmental restoration. It creates opportunities for inclusive rural development. Agroforestry can generate timber, fruit, fodder, and ecological services. Dryland horticulture can diversify incomes while improving resilience to climate variability. Integrated farming systems can combine crops, livestock, and water management to maximize productivity from limited resources.

Such interventions generate employment across seasons, reducing dependence on migration and strengthening local economies. Increased productivity also enables households to save seeds, reduce borrowing, and gradually break cycles of indebtedness.

The benefits extend beyond farmers themselves. A more productive agricultural base stimulates demand for skilled rural services—blacksmiths, carpenters, transporters, traders, and processors—revitalizing the wider village economy. When agriculture becomes economically viable, it supports broader community development.

Ultimately, the developmental gap in Bankura is not simply a deficit of infrastructure or income. It is the cumulative outcome of insecure land systems, weak investment capacity, exploitative credit structures, and ecological stress. Addressing it requires an

integrated approach where land reclamation, livelihood enhancement, and institutional support work together.

In this sense, restoring degraded land is not only about making soil productive again. It is about rebuilding the social and economic foundations of rural life—ensuring that communities can remain rooted in their landscapes with dignity, resilience, and opportunity.

1.6 Conceptualizing the Transformation Framework

The central premise of this study is that agricultural wastelands should no longer be understood as abandoned or inherently unproductive spaces. Such labels often obscure the deeper ecological, social, and institutional realities that shape these landscapes. In districts such as Bankura, land categorized as “wasteland” is rarely empty in a functional sense; rather, it is land whose potential has been constrained by environmental stress, historical neglect, and developmental imbalance. The challenge, therefore, is not simply to identify these spaces, but to reframe them as assets capable of regeneration under the right ecological and socio-economic conditions.

This shift in perspective forms the foundation of the transformation framework proposed in this research. Instead of approaching reclamation as a short-term technical intervention, the framework treats it as a long-term process of ecological restoration and rural restructuring. It recognizes that the Rarh landscape is not a homogeneous terrain that can be managed through standardized agricultural prescriptions. Its lateritic soils, undulating topography, hydrological volatility, and socio-economic vulnerabilities require solutions that are deeply contextual, spatially informed, and adaptive.

At its core, the framework seeks to move beyond reactive measures—such as emergency drought relief or isolated land-treatment projects—and toward a proactive, systems-based model of land management. The goal is not only to restore soil productivity, but also to rebuild ecological functions, diversify livelihoods, and strengthen community resilience. In this sense, reclamation becomes both a landscape strategy and a developmental agenda.

1.6.1 A Multi-Disciplinary Integration

No single discipline can adequately address the complexity of land degradation in Bankura. The causes and consequences of wasteland formation span multiple domains—soil science, hydrology, geography, economics, and governance. As a result, the proposed transformation framework is inherently multidisciplinary, integrating scientific tools with ecological knowledge and policy mechanisms.

A critical pillar of this integration is the use of geospatial technologies. High-resolution remote sensing and GIS-based spatial analysis provide the ability to map degradation patterns with precision. Through satellite imagery, it becomes possible to identify erosion-prone zones, vegetation stress, moisture deficits, and shifts in land-use dynamics over time. These tools allow for the differentiation of wasteland typologies—whether caused by sheet erosion, nutrient depletion, abandoned cultivation, or hydrological instability.

Such spatial intelligence is essential because reclamation cannot be applied uniformly across the district. Different micro-regions experience distinct ecological constraints. A degraded upland ridge requires a different intervention than a silted valley floor. By overlaying environmental variables such as slope, soil texture, drainage, rainfall distribution, and proximity to water resources, the framework can prioritize intervention zones at the micro-watershed scale.

This spatial targeting ensures that resources are allocated strategically rather than diffusely. Instead of implementing broad schemes without regard for local suitability, interventions can be matched to carrying capacity and ecological need. Moreover, geospatial monitoring creates a feedback loop, allowing progress to be tracked over time and strategies to be adjusted in response to climatic shifts or implementation outcomes.

In this way, technology becomes not an end in itself, but a decision-support system—grounding reclamation in evidence and enabling long-term adaptive management.

1.6.2 Site-Specific Ecological Interventions

While geospatial analysis identifies where action is needed, ecological interventions determine how transformation can occur. The framework emphasizes that restoration

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

must be rooted in the biological realities of the land. Rather than forcing unsuitable agricultural models onto fragile soils, it advocates for land-use systems that work with the ecological character of the landscape.

A major objective is to rebuild what may be called the land's "water bank"—its ability to capture, store, and gradually release moisture. In Bankura's lateritic zones, this requires slowing runoff, improving infiltration, and increasing organic matter. Structural measures such as contour bunding, check dams, recharge pits, and farm ponds play a key role in hydrological restoration. These interventions reduce water loss and enhance groundwater recharge, creating a more stable moisture regime.

Equally important is vegetative rehabilitation. Agroforestry emerges as a central strategy because it combines ecological restoration with economic productivity. Tree-based systems improve soil structure, reduce erosion, enhance carbon sequestration, and generate diversified outputs such as timber, fruit, fodder, and fuelwood.

Dryland horticulture offers another promising pathway. Hardy, drought-tolerant fruit trees can thrive in moisture-constrained environments while providing long-term income streams less dependent on annual rainfall fluctuations. This reduces overreliance on monsoon-sensitive rice cultivation and strengthens livelihood resilience.

Social forestry initiatives further contribute to restoration by introducing species that stabilize degraded soils and improve fertility. Nitrogen-fixing trees and shrubs can gradually enrich nutrient-poor lateritic soils, functioning as biological amendments. Over successive seasons, leaf litter and biomass inputs increase organic carbon, improving the soil's moisture-holding capacity and overall health.

Integrated farming systems complete this ecological package by diversifying production. Combining crops, livestock, pulses, oilseeds, and horticulture reduces dependence on monocultures and spreads risk across multiple income sources. Such systems mimic ecological diversity while strengthening food security at the household level.

Together, these interventions transform wastelands into multifunctional agro-ecosystems capable of sustaining both ecological balance and rural livelihoods.

1.6.3 Socio-Economic Alignment and Resilience

Ecological restoration alone cannot succeed if the socio-economic structures surrounding the land remain unchanged. A degraded landscape is often mirrored by a vulnerable society—one characterized by insecure land access, indebtedness, low investment capacity, and seasonal migration. For this reason, the framework places strong emphasis on socio-economic alignment.

At present, many farmers in Bankura are constrained by limited capital and dependence on informal credit. High-interest borrowing, exploitative tenancy arrangements, and unstable market access reduce their ability to invest in sustainable land management. Even when technical solutions exist, adoption remains difficult without financial and institutional support.

The framework therefore advocates for policy convergence. Existing government schemes related to watershed development, irrigation, rural livelihoods, and agroforestry must be integrated into a unified implementation strategy. Public investment in soil amendments, decentralized irrigation, and capacity building can reduce entry barriers for smallholders.

Equally important is strengthening collective institutions such as self-help groups, cooperatives, and Farmer Producer Organizations. These platforms can improve market access, facilitate credit, and create shared ownership of restoration initiatives.

By turning marginal lands into productive assets, the framework aims to create local employment opportunities that reduce dependence on seasonal migration. When communities can generate income within their own landscapes, the cycle of ecological migration begins to weaken. Labor that once left for distant mines, plantations, or construction sites can instead be invested in local restoration and agricultural enterprises.

Resilience, in this context, is not only about surviving climatic shocks. It is about building systems—ecological, economic, and institutional—that enable communities to adapt, recover, and thrive.

1.6.4 Toward a New Development Paradigm

Ultimately, this transformation framework represents a broader rethinking of development in ecologically fragile regions. It challenges the assumption that degraded lands are permanent liabilities and instead positions them as transitional spaces capable of renewal.

The framework moves agriculture away from a purely defensive strategy—one dictated by uncertain monsoons and short-term survival—and toward a proactive model of diversified, regenerative land management. It recognizes that long-term sustainability depends on restoring ecological processes while empowering communities to manage and benefit from them.

In this vision, “wasteland” ceases to be a fixed category. It becomes a temporary condition within a larger trajectory of recovery. Through scientific planning, ecological adaptation, and socio-economic inclusion, degraded landscapes can be reimagined as productive, resilient, and equitable systems.

For Bankura and the wider Rarh region, this is more than a technical proposal. It is a blueprint for redefining the relationship between land, livelihoods, and development—ensuring that restoration is not merely about repairing soil, but about securing a sustainable future for the people who depend on it.

CHAPTER 2: AIM, OBJECTIVES, AND RESEARCH QUESTIONS

2.1 Overarching Research Aim

The primary aim of this research is to formulate a comprehensive, district-level implementation framework for the conversion of agricultural wastelands into productive agro-lands within the specific geographic and climatic context of Bankura. This study recognizes that land degradation in this region is not merely a superficial soil issue but a systemic challenge involving hydrological stress, chronic nutrient exhaustion, and historical land-use patterns that have been meticulously documented in regional archives and satellite records. Consequently, the aim is to bridge the gap between existing spatial data and practical agricultural productivity by developing a model that is resource-efficient and ecologically resilient. By strategically leveraging available datasets, the research eliminates the logistical and financial burden of conducting new primary field surveys while maximizing the utility of existing information to solve contemporary environmental and economic problems.

Central to this research is a fundamental transition in the perception of "wastelands." Rather than viewing these tracts as stagnant, redundant burdens on the district's economy, this study treats them as vital, neglected assets for rural rejuvenation. The research seeks to harmonize the "Rarh" region's unique geomorphology—defined by its natural south-eastern tilt and rapid surface runoff—with innovative land management strategies designed to mitigate the "pseudo-abundance" of monsoon rainfall. By addressing the hydro-climatic paradox where seasonal rivers like the Damodar and Kangsabati fluctuate between destructive floods and dry beds, the framework intends to facilitate the creation of a "water bank" within the soil profile. This would enable the cultivation of a second crop in the upland "tanr" lands, which currently remain fallow and unproductive for the majority of the year due to moisture deficit.

Beyond its immediate local application, the research seeks to establish a replicable and scalable methodology for other drought-prone districts within the Red Laterite zone of West Bengal and similar physiographic regions in India. This involves creating a strategic decision-support tool for land-use planners to enhance regional food security through the optimization of existing governmental, pedological, and environmental datasets. By providing a technical and social blueprint for the reclamation of lateritic soils, the study aims to reduce the "liability to famine" inherent in the district's current,

risky dependence on rice monocultures. Ultimately, the goal is to stabilize the rural economy at its source, thereby reducing the necessity for seasonal "ecological migration" and providing a robust pathway toward a more resilient, self-sustaining, and climate-adaptive agrarian future.

2.2 Research Objectives

2.2.1 Objective 1: Systematic Parameter Identification and Database Compilation

The first objective focuses on the systematic identification and categorization of useful parameters for the study through an extensive desk-based review. This involves the compilation of a multi-dimensional database encompassing physical, ecological, socio-economic, and institutional factors derived from established sources such as the District Census Handbooks, Soil and Land Use Survey of India (SLUSI) reports, and Meteorological Department archives.

The research will specifically target historical soil pH and nutrient profiles to understand the long-term depletion of lateritic tracts, alongside topographical data from Digital Elevation Models (DEM) to map the natural tilt of the Rarh landscape. Decadal rainfall variability will be analyzed to quantify the "hydro-climatic paradox" and identify periods where meteorological droughts transitioned into agricultural crises. By synthesizing these pre-existing data points, the study ensures that the reclamation strategies are grounded in the documented carrying capacity and the complex socio-economic constraints—such as high-interest debt and land-tenure traps—that define the district.

2.2.2 Objective 2: Spatial Delineation and Prioritization via Geospatial Analysis

The second objective entails the spatial identification and characterization of wastelands through the rigorous application of Geospatial Information Systems (GIS) and Remote Sensing technologies. This phase involves the creation of a georeferenced inventory by processing publicly available multi-spectral satellite imagery, such as

Sentinel-2 or Landsat archives, to detect spectral signatures indicative of land degradation.

The objective is to delineate the precise extent and type of degraded lands across Bankura, classifying wastelands—ranging from gullied land to abandoned scrubland—and analyzing their spatial relationship with mapped water bodies and transport networks. This computational approach allows for the prioritization of sites based on "proximity analysis," identifying areas with the highest potential for conversion due to their closeness to existing irrigation feeder roads or railway hubs. By leveraging these spatial relationships, the study identifies high-priority zones for intervention without requiring physical site visits, ensuring the framework remains resource-efficient.

2.2.3 Objective 3: Meta-Analysis of Reclamation Best Practices and Scalability

The third objective is the critical review and documentation of national and regional best practices in wasteland reclamation as recorded in academic literature and government completion reports. This component investigates successful case studies from similar agro-climatic zones, such as watershed development programs implemented in the neighboring Rarh region.

By analyzing technical reports and project evaluations, the study evaluates the efficacy of specific techniques like multi-tier agroforestry, social forestry, and chemical soil conditioning. The focus remains on evaluating the scalability of these practices and their specific relevance to the documented lateritic soil profiles of Bankura. This ensures that the proposed framework is built upon proven, peer-reviewed successes, particularly focusing on methods that have successfully mitigated the "flashy" character of seasonal rivers and improved subsoil moisture retention.

2.2.4 Objective 4: Formulation of Evidence-Based Site-Specific Strategies

The fourth objective involves the formulation of targeted, evidence-based strategies for enhancing the productivity of selected wastelands. Based on the meta-analysis of secondary data and spatial mapping results, this stage proposes site-specific interventions designed to restore soil health and introduce sustainable cropping patterns. These strategies are developed by matching identified wasteland

characteristics with recommended crop suitability matrices, such as shifting from high-risk rice monocultures to dryland horticulture or integrated farming.

The resulting framework emphasizes low-cost interventions and the strategic utilization of existing government schemes, such as those targeting the Bauri and Santal labor groups who historically migrate due to land unproductive. By aligning technical soil requirements with the existing institutional and budgetary framework of the district, the model ensures practical applicability, providing a blueprint for turning marginal lands into socio-economic assets that stabilize the rural economy.

2.3 Research Questions

The study is driven by a series of critical research questions designed to provide analytical depth to the investigation of secondary data. These questions serve as the investigative pillars that bridge the gap between historical regional archives and modern geospatial analysis, ensuring that the proposed framework addresses the unique complexities of the Bankura district.

2.3.1 Impediments and Spatial Distribution

The primary question asks what the existing environmental and socio-economic datasets reveal about the fundamental impediments to wasteland conversion in Bankura and how these barriers are spatially distributed across the district. This inquiry seeks to move beyond a simple mapping of degraded land to understand the "why" behind the persistence of uncultivated tracts. It investigates whether the primary barrier is physical—such as the rapid surface runoff and soil crusting characteristic of the "Rarh" landscape—or socio-economic, involving land-tenure traps like the *bhag jot* system or the cycle of high-interest debt that forces laborers into seasonal migration. By identifying whether a specific tract is "unproductive" due to chemical soil exhaustion or simply a lack of accessible credit for the farmer, the framework can suggest targeted solutions rather than generic ones.

2.3.2 Optimization of Geospatial Modeling

Following this, the study asks how integrated GIS modeling of secondary topographical and hydrological data can be optimized to identify "pockets of opportunity" for reclamation. This question focuses on the technical methodology of the research, exploring how Digital Elevation Models (DEM) and decadal rainfall variability can be layered to pinpoint micro-watersheds with the highest moisture-retention potential. The research investigates how to refine "proximity analysis" to account for the district's natural tilt, identifying areas where runoff can be most efficiently intercepted. The aim is to determine if computational modeling can effectively replace traditional, resource-intensive field surveys to prioritize sites for immediate conversion based on their distance from existing transport networks and irrigation infrastructure.

2.3.3 Adaptability of Proven Techniques

A further question examines which reclamation techniques, documented in regional success stories, offer the highest degree of adaptability to Bankura's specific rainfall and soil constraints as recorded over the last two decades. This involves a critical assessment of the "liability to famine" caused by the district's heavy reliance on a single rice crop. The research asks whether documented successes in multi-tier agroforestry, social forestry, or integrated farming can be scaled to fit the local lateritic soil profile, which often suffers from extreme nutrient depletion and the "flashy" behavior of rain-fed rivers like the Damodar and Kasai. It specifically questions which biological interventions can thrive in the high-heat, low-moisture environment of the Bankura summer without requiring expensive, external water sources.

2.3.4 Institutional Sustainability and Climate Resilience

Finally, the research investigates the nature of the institutional framework required to sustain these conversions, asking how existing policy instruments can be leveraged to ensure that converted agro-lands remain productive under the projected trends of climatic instability. This question addresses the long-term viability of the transformation. It explores how the transition from a defensive agricultural strategy to a proactive one can be supported by existing government schemes, ensuring that the marginalized labor force—such as the Bauri and Santal communities—finds local,

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A
CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

sustainable employment that breaks the necessity for economic migration. The study asks how to structure these projects so that they are not just "one-off" environmental fixes but are integrated into the local economy through cooperatives, market access, and secure land tenure.

Research Question	Focus Area	Key Variables
What environmental and socio-economic datasets reveal about barriers to wasteland conversion — and how are these barriers spatially distributed?	Impediment Mapping	Surface runoff, soil crusting, land-tenure traps, debt cycles
How can integrated GIS modelling of topographic and hydrological data identify "pockets of opportunity" for reclamation?	Geospatial Optimisation	DEM slope, flow accumulation, moisture-retention potential
Which documented reclamation techniques offer highest adaptability to Bankura's rainfall and soil constraints?	Technique Adaptability	Agroforestry models, social forestry, integrated farming scalability
What institutional framework is required to sustain converted agro-lands under projected climatic instability?	Governance & Resilience	Policy instruments, community cooperatives, land tenure security

Table 5: Research Questions — Focus Area and Key Variables

CHAPTER 3: LITERATURE REVIEW

The agricultural landscape of Bankura district is defined by a sharp topographical contrast between its eastern and western regions. The eastern portion, comprising areas such as Indas, Kotalpur, and Sonamukhi, consists of rich alluvial flats that mirror the fertile plains of Hooghly and Burdwan. This area is characterized by deep, productive soil that is well-suited for intensive cultivation. In contrast, the central and western sectors feature an undulating terrain with slopes ranging from 0.4% to 10%. This region is dominated by lateritic, acidic, and porous red soils that suffer from low organic matter and poor water-holding capacity. These geological constraints have led local cultivators to develop a sophisticated land classification system, distinguishing between *Sali* lands, which are largely restricted to rice, and *Suna* lands, which are more fertile and capable of supporting a variety of crops like sugarcane, oilseeds, and vegetables.

Because of these soil characteristics, the district's agricultural success is inextricably linked to the rhythm of the monsoon. Bankura receives an average normal rainfall of 1423.00 mm, but its reliance on these rains makes it highly vulnerable to drought. The staple *Aman* rice crop is particularly sensitive, requiring heavy rainfall during the crucial maturing months of September and October. If the rains fail during this window, the impact on the local economy is devastating. This vulnerability was starkly illustrated during the 2010-2011 season, when a severe drought led to a massive reduction in the total cropped area, falling from over 516,000 hectares to approximately 299,963 hectares. Such fluctuations underscore the precarious nature of rain-fed farming in the region.

To mitigate these climatic risks, the district employs a blend of traditional and modern irrigation infrastructure. In the undulating western regions, farmers have historically relied on *Bandhs*—ingenious embankments built across drainage lines to capture and store rainwater. These structures allow water to slowly percolate into the fields situated at lower elevations, maintaining moisture even during dry spells. While historical systems like the *Subhankari daura* channel once provided significant irrigation support, many of these ancient waterways have silted up over decades of neglect. Modern efforts to stabilize production now include a growing network of cold stores, seed farms, and

warehouses, alongside the widespread issuance of Kishan Credit Cards (KCC) to provide farmers with the financial liquidity needed to invest in resilient farming practices.

While rice remains the dominant crop, there is a visible shift toward diversification and mechanization across Bankura's 22 agricultural blocks. The district consistently produces a surplus of potatoes and vegetables, and farmers are increasingly adopting oilseeds like mustard and summer til. There is also a growing interest in high-value crops such as sunflower and broccoli, which offer better returns on investment. This transition is supported by government frameworks like the Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) and the National Food Security Mission. These programs focus on modernizing the sector by distributing pump sets, establishing agri-implement hubs for tractors and power tillers, and promoting "Bio-Village" initiatives to encourage sustainable, organic growth.

3.1 Theoretical Framework of Land Degradation

The conceptualization of land degradation in plateau regions is increasingly viewed through the lens of the "**Social-Ecological System**" (SES). In regions like the Rarh plain and the Chota Nagpur fringe, land degradation is not a stagnant state of poor soil quality but a dynamic process involving the continuous decline of ecosystem services. This framework suggests that the health of the land is inextricably linked to the social and economic systems that manage it; when the land loses its ability to provide for the community, the resulting economic instability leads to further environmental neglect, creating a destructive feedback loop.

Current literature suggests that in lateritic belts like Bankura, the primary physical driver is "physical degradation," specifically the crusting and sealing of the soil surface. This phenomenon occurs when the top layer of soil becomes hardened and impermeable, which inhibits water infiltration and promotes high-velocity surface runoff. In Bankura, this is exacerbated by the district's natural south-eastern tilt, which acts as a geological drain, carrying away moisture before it can penetrate the subsoil. This mechanical failure of the soil profile is a major contributor to the "hydro-climatic paradox," where the district remains moisture-deficient even after significant rainfall.

Scholars argue that the transition from traditional, long-term fallowing to intensive monoculture—specifically the heavy reliance on winter rice—has stripped the soil of its essential organic carbon content. This depletion leads to a state of "nutrient desertification," where the soil becomes chemically inert and structurally weak. As organic matter disappears, the soil loses its "glue," making it highly susceptible to sheet erosion and the formation of gullies during the intense bursts of monsoon rain. The lack of a "water bank" in the soil means that once the rains cease, the land dries up almost immediately, leaving crops vulnerable to "meteorological droughts."

This study builds on these theories by utilizing historical soil and weather data to track the long-term shifts in land quality across Bankura's blocks. By analyzing decadal trends in soil pH and nutrient profiles alongside rainfall variability, the research seeks to quantify the rate of this degradation. The aim is to move beyond simple descriptions of "bad soil" and instead map the precise points where the social-ecological system has broken down. Understanding these theoretical drivers is essential for developing a transformation framework that does not just treat the surface symptoms but restores the fundamental ecological functions of the Rarh landscape.

3.2 Global and National Perspectives on Wasteland Taxonomy

The definition of "wasteland" remains a subject of intense academic and policy debate, evolving from a strictly economic viewpoint to a more nuanced ecological and restorative perspective. Historically, the term was applied to any land that did not yield a direct revenue or agricultural surplus, often ignoring the local ecosystem services such lands provided. Today, the Wasteland Atlas of India provides a more technical framework, categorizing these regions based on their biological and physical potential for recovery. The Atlas distinguishes between "culturable" wastelands, which have the potential to be brought under cultivation with proper soil and water management, and "unculturable" wastelands, such as steep rocky outcrops or barren caprock, which are physically incapable of supporting vegetation.

Research into the specific landscape of Bankura reveals that the district is dominated by two primary categories: "gullied land" and "land with dense or open scrub." These are not naturally occurring states but are largely the result of historical environmental

degradation. The widespread deforestation of the indigenous Sal (*Shorea robusta*) forests for timber and fuel, followed by uncontrolled overgrazing, has left the lateritic soil exposed to the elements. Without the protective canopy and root systems of the forest, the fragile topsoil is quickly washed away during monsoon cloudbursts, leading to the formation of deep gullies that carve through the "Rarh" plain and render the land impassable for traditional plowing.

At the national level, studies emphasize that the nomenclature is shifting in response to the global climate crisis. The traditional term "wasteland" is increasingly being replaced by "marginal lands" or "underutilized lands." This shift in terminology is a conscious effort to acknowledge their inherent potential for carbon sequestration, groundwater recharge, and biodiversity support. By viewing these areas as "marginal" rather than "wasted," planners can justify investments in dryland horticulture or social forestry as part of national climate goals rather than just local agricultural fixes.

This study adopts the technical definitions and classification keys provided by the National Remote Sensing Centre (NRSC). By adhering to these standardized taxonomies, the research ensures full compatibility with national land-use databases and the Integrated Wasteland Development Programme (IWDP) frameworks. Utilizing NRSC's multi-spectral signature profiles for "land with scrub" and "degraded pastures" allows this research to accurately delineate the intensity of degradation in Bankura. This alignment is crucial for ensuring that the proposed transformation framework can be seamlessly integrated into existing government budgetary schemes and national soil health missions, providing a scientifically rigorous basis for reclaiming the district's lateritic tracts.

3.3 Technological Interventions: Geospatial and RS Applications

The integration of Remote Sensing (RS) and Geographic Information Systems (GIS) has shifted the paradigm of land management from reactive to predictive. In the context of a region like Bankura, where the landscape is characterized by a natural tilt and rapid surface runoff, these technologies allow for a comprehensive understanding of environmental stressors without the logistical constraints of continuous field

monitoring. The ability to process multi-temporal satellite data enables researchers to distinguish between temporary agricultural setbacks and systemic land failure.

3.3.1 Spectral Indices as Diagnostic Tools

The use of spectral indices has become one of the most reliable and widely accepted approaches in geospatial studies of land degradation, particularly in regions where direct field observation is difficult across large areas. Among these indices, the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and the Normalized Difference Water Index (NDWI) are consistently recognized in academic literature as benchmark tools for distinguishing seasonal fallows from structurally degraded or permanently unproductive lands. Their strength lies in their ability to translate satellite-derived reflectance values into meaningful ecological indicators, enabling researchers to assess vegetation health, moisture conditions, and broader landscape dynamics over time.

NDVI is one of the most extensively applied indices in environmental monitoring because it captures the density and vigor of vegetation through the relationship between near-infrared and red light reflectance. Healthy vegetation absorbs visible red light for photosynthesis while strongly reflecting near-infrared wavelengths. By quantifying this contrast, NDVI provides a direct measure of “greenness” or photosynthetic activity. In agricultural studies, this becomes especially valuable for identifying active croplands, stressed vegetation, seasonal fallows, and barren surfaces. In the context of degraded landscapes such as the lateritic tracts of Bankura, low or persistently declining NDVI values often signal areas where vegetation cover has been lost due to soil crusting, nutrient depletion, or prolonged moisture stress. When monitored across multiple seasons and years, NDVI can reveal whether an area is temporarily uncultivated or has entered a more permanent state of ecological decline.

NDWI complements NDVI by focusing on the hydrological dimension of the landscape. While NDVI highlights biological productivity, NDWI measures the moisture content of vegetation and surface water presence by analyzing the contrast between near-infrared and shortwave infrared bands. This makes it particularly effective in identifying wetlands, standing water bodies, and zones of soil moisture retention. In semi-arid and drought-prone regions, NDWI serves as a critical indicator of hydrological stress. For Bankura, where rapid runoff and poor infiltration create a

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

persistent moisture deficit despite seasonal rainfall, NDWI helps identify areas where water availability is structurally constrained. Low NDWI values during post-monsoon periods often indicate weak water retention capacity, signaling zones vulnerable to agricultural failure even after substantial rainfall events.

To strengthen this analytical framework, recent literature increasingly incorporates the Normalized Difference Built-up Index (NDBI), which adds an important land-use perspective to environmental assessment. Unlike NDVI and NDWI, which focus on vegetation and water, NDBI is designed to detect built-up or impervious surfaces by comparing shortwave infrared and near-infrared reflectance. Built-up areas typically reflect more strongly in the shortwave infrared range, allowing the index to distinguish settlements, roads, industrial sites, and other constructed surfaces from surrounding vegetation or bare soil.

The inclusion of NDBI is especially relevant in studies of land transformation because it captures the spatial footprint of human development and infrastructure expansion. In districts like Bankura, where rural settlements, mining-related growth, and transportation corridors may influence surrounding land systems, NDBI helps map the extent to which anthropogenic pressure contributes to landscape change. Areas with high NDBI values may indicate urban encroachment, settlement densification, or infrastructural development, all of which can alter drainage patterns, reduce cultivable land, and intensify ecological fragmentation.

When interpreted together, NDVI, NDWI, and NDBI create a more holistic diagnostic framework. NDVI identifies biological productivity, NDWI reveals hydrological status, and NDBI highlights built-environment pressures. This triad allows researchers to move beyond single-variable analysis and instead understand the interplay between ecological health, water availability, and human intervention.

For example, a zone with low NDVI, low NDWI, and high NDBI may indicate land that has shifted from agricultural or ecological use toward settlement expansion or infrastructural occupation. Conversely, an area with low NDVI and low NDWI but also low NDBI may represent a degraded rural tract suffering from ecological stress rather than urbanization. Such distinctions are essential for accurately categorizing land conditions and designing targeted reclamation strategies.

In the context of agricultural wasteland transformation, these indices collectively provide a robust evidence base for decision-making. They allow for the identification of hidden patterns that may not be visible through conventional surveys, helping distinguish between ecological degradation, hydrological failure, and anthropogenic land-use change. By integrating all three indices into spatial analysis, researchers can develop more precise reclamation models that respond not only to environmental deficits but also to the evolving human geography of the landscape.

3.3.2 Predictive Modeling of Erosion Hotspots

Studies have demonstrated that by overlaying Digital Elevation Models (DEM) with soil texture maps, researchers can predict "erosion hotspots" with high accuracy. In Bankura, where the "flashy" nature of seasonal rivers like the Damodar leads to sudden inundation and subsequent soil stripping, the DEM provides a critical layer of topographical intelligence. By calculating slope steepness and flow accumulation, the study can identify where surface runoff reaches peak velocity, pinpointing the exact locations where gullies are likely to form. This predictive capability is essential for designing interceptor drains or "bandhs" that are placed strategically to break the speed of water before it erodes the fragile lateritic topsoil.

3.3.3 LULC as the decision making tool

Land Use/Land Cover (LULC) analysis serves as one of the most practical and effective tools for identifying suitable wasteland patches for reclamation, particularly in districts characterized by ecological diversity and fragmented land systems. Unlike broader land classification methods, LULC provides a detailed spatial representation of how land is currently being utilized and what physical cover exists on the ground. This distinction is critical in reclamation studies because not all degraded lands are equally suitable for transformation. Some may be under temporary fallow, some permanently abandoned, while others may already support sparse vegetation or secondary ecological functions.

By examining satellite-derived LULC maps, researchers can isolate specific categories that indicate underutilized or degraded land. These often include scrublands, barren rocky surfaces, degraded agricultural fields, gullied terrain, and current fallow lands.

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

Each of these classes represents a different stage or form of ecological stress, and therefore a different level of reclamation potential. For example, current fallow lands may require minimal intervention to restore productivity, whereas barren rocky outcrops may have limited agricultural viability and may be better suited for ecological restoration or afforestation.

In the context of agricultural wasteland transformation, LULC acts as the first screening mechanism for identifying target zones. It enables planners to distinguish between productive agricultural areas, built-up regions, forests, water bodies, and wastelands. This separation ensures that interventions are focused only on land parcels that are genuinely available for rehabilitation and not already serving critical agricultural, residential, or ecological purposes.

One of the greatest strengths of LULC analysis is its temporal dimension. By comparing land cover patterns across multiple years, it becomes possible to identify persistent wasteland patches rather than seasonal or temporary changes. For instance, an area consistently classified as scrubland or barren land over a decade signals long-term underutilization, making it a strong candidate for reclamation. Conversely, land that alternates between cultivation and fallow may indicate cyclical agricultural use rather than permanent abandonment. This distinction is essential for avoiding misclassification and ensuring that restoration resources are allocated efficiently.

LULC also provides insights into surrounding landscape context, which is crucial when selecting suitable patches. A wasteland located adjacent to irrigated farmland may have higher reclamation potential due to access to agricultural infrastructure, labor availability, and possible extension of irrigation networks. Similarly, degraded land near transportation corridors or rural settlements may be more feasible for intervention because of easier access and stronger market connectivity. In contrast, isolated wasteland patches in remote or inaccessible areas may face implementation barriers despite ecological suitability.

Another significant advantage is that LULC can reveal land-use transitions that help explain degradation pathways. For example, if an area has shifted from cropland to scrubland over time, it may suggest declining soil fertility, moisture stress, or socio-economic abandonment. Understanding these transitions helps planners select

interventions that address the root causes of decline rather than merely treating visible symptoms.

For regions such as Bankura, where lateritic soils, erratic rainfall, and uneven topography create complex land-use patterns, LULC becomes indispensable. It allows for the identification of wasteland patches that are not only ecologically degraded but also spatially strategic for reclamation. By overlaying LULC with supporting datasets such as slope, drainage, and soil quality, researchers can further refine these selections and categorize them according to their most suitable future use—whether agroforestry, horticulture, silvopasture, or water conservation.

Ultimately, LULC analysis transforms the identification of wastelands from a generalized administrative exercise into a spatially precise planning tool. It provides a data-driven basis for selecting land parcels with the highest potential for rehabilitation, ensuring that reclamation efforts are targeted, context-sensitive, and aligned with long-term rural development goals. In this way, LULC serves not merely as a mapping product, but as the foundational layer for strategic land transformation planning.

3.4 Reclamation Strategies: Agroforestry and Watershed Management

The academic and policy literature consistently identifies agroforestry as a "triple-win" strategy for semi-arid and lateritic zones like Bankura. By integrating woody perennials with agricultural crops or livestock, these systems offer simultaneous benefits in carbon sequestration, soil stabilization, and economic diversification. In a region where the "Rarh" landscape is prone to rapid moisture loss and nutrient desertification, agroforestry acts as a biological buffer, protecting the fragile topsoil from the erosive forces of intense monsoon cloudbursts while providing a secondary source of income that is not solely dependent on the volatile rice harvest.

3.4.1 Models for High-Temperature Resilience

Specific frameworks, such as the "Vadi" model and other silvopastoral systems, are frequently cited for their success in high-temperature, low-rainfall environments similar to the western fringes of West Bengal. These models prioritize the planting of hardy,

drought-resistant fruit trees alongside nitrogen-fixing shrubs and grasses. In Bankura, where the "hydro-climatic paradox" means the land is often scorched shortly after heavy rains, these deep-rooted systems can access subsoil moisture that shallow-rooted monocultures cannot reach. Furthermore, the introduction of social forestry and dryland horticulture provides essential fodder and fuel, reducing the overgrazing pressure on existing "land with scrub" and allowing the natural vegetation to regenerate.

3.4.2. Watershed Management as the Hydrological Backbone

Complementing these biological interventions, watershed management is recognized as the structural and hydrological backbone of land reclamation. Documented successes in "ridge-to-valley" treatments—such as the construction of staggered trenches, contour bunds, and farm ponds—demonstrate a proven methodology for slowing down surface runoff. Because Bankura possesses a natural south-eastern tilt that facilitates the rapid drainage of rainwater, these interventions are mechanically necessary to intercept water at the "ridge" before it gains the velocity required to carve out gullies in the lower valleys. Even marginal increases in localized groundwater recharge through these small-scale structures can significantly improve soil moisture profiles, rendering previously abandoned wastelands suitable for drought-resistant crops like millets and oilseeds.

3.4.3 Low-Cost, High-Impact Interventions

This study reviews these documented interventions to select the most "low-cost" and "high-impact" strategies tailored to the fiscal realities of district-level planning. Given that many local farmers are trapped in a cycle of high-interest debt and lack the capital for modern irrigation, the focus remains on "nature-based solutions" that utilize local labor and materials. By leveraging existing government schemes—such as those providing employment for marginalized Bauri and Santal communities—these reclamation projects can provide immediate wages while building long-term assets. The goal is to move away from expensive, large-scale engineering projects and toward a decentralized model of land management that stabilizes the rural economy and enhances the district's overall food security.

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A
CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

Land Category	Primary Driver	Recovery Potential	Proposed Strategy
Gullied Land	Overgrazing/Runoff	Medium	Ridge-to-Valley / Silvopasture
Open Scrub	Deforestation	High	Agroforestry (Vadi Model)
Degraded Forest	Institutional Failure	High	Policy-led Reforestation

Table 6: Wasteland Taxonomy & Recovery Potential

Criterion	Input Dataset	Rationale	Weightage (%)
Vegetation Health	NDVI	Identifies seasonal vs. permanent fallows	50%
Soil Moisture	NDWI	Determines irrigation requirements	25%
Land Coverage	LULC	Determines land availability	25%

Table 7: Multi-Criteria Weightage

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A
CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

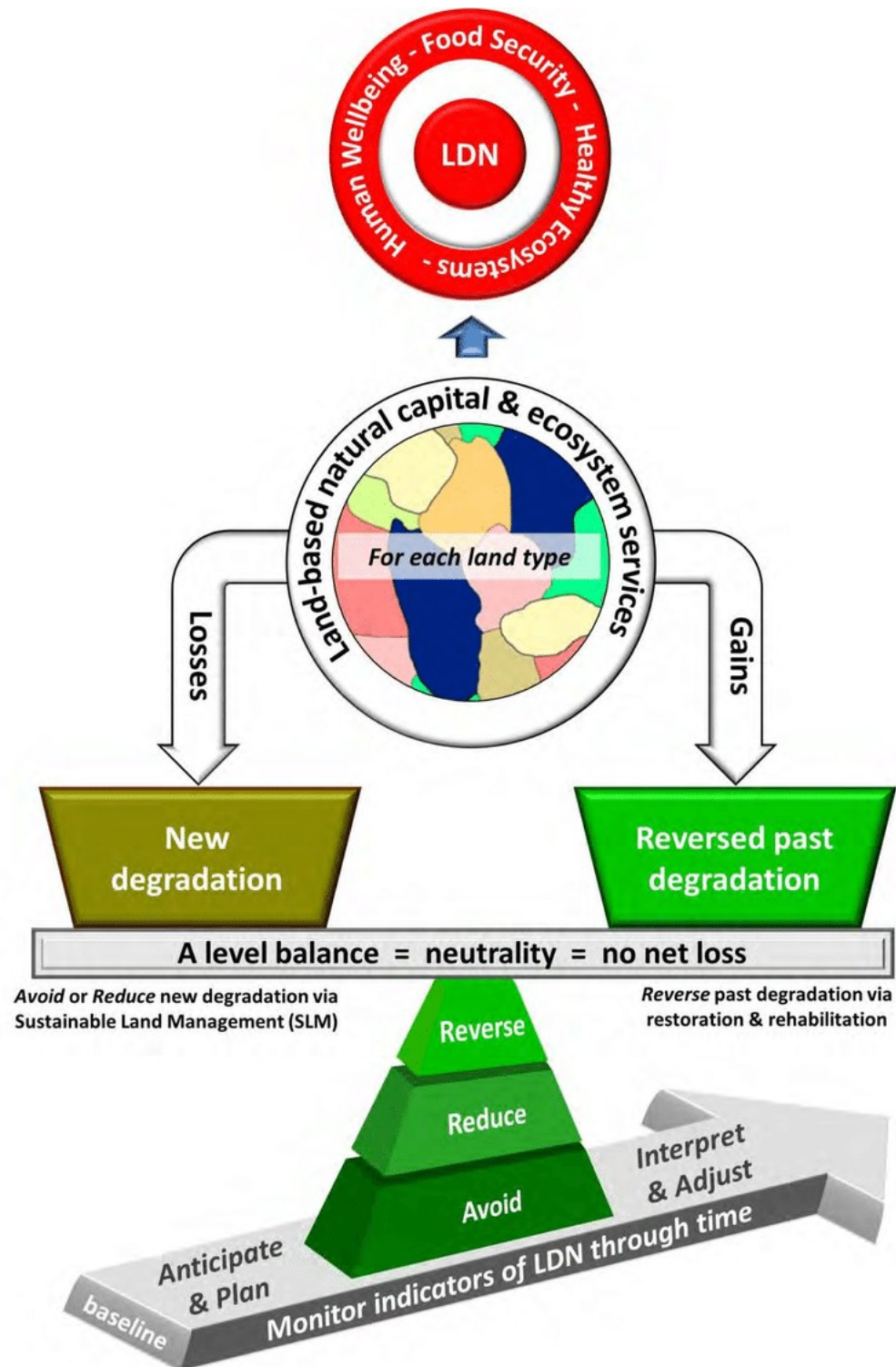


Fig. 9: The key elements of the scientific conceptual framework for LDN and their interrelationships.

CHAPTER 4: POLICY ANALYSIS AND STRATEGIC CASE STUDIES

4.1 National Level Policy Frameworks

The National Forest Policy (1988) and The Wasteland Atlas of India While the 1988 policy primarily focuses on forest conservation, it set the precedent for "social forestry" and the reclamation of degraded lands to reduce pressure on traditional forests. This is supported by the Wasteland Atlas of India, published by the National Remote Sensing Centre (NRSC). This is not just a document but a policy tool that standardizes the taxonomy of "culturable" versus "unculturable" wastelands, providing the technical basis for the NRSC definitions adopted in this study.

National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA) Under the umbrella of the National Action Plan on Climate Change (NAPCC), the NMSA is perhaps the most relevant technical policy. It promotes "Location Specific Integrated/Composite Farming Systems." Its Soil Health Management (SHM) component is critical for Bankura, as it funds the diagnostic testing required to treat "nutrient desertification" and promotes the use of organic ammendments and dolomite to treat the acidity common in lateritic soils.

Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) – Watershed Development Component Replacing the older IWMP, this policy provides the primary funding for "Ridge-to-Valley" treatments. It emphasizes the creation of "Water Harvesting Structures" (WHS) such as farm ponds and check dams. It dictates the spatial planning of drainage lines and micro-watersheds at the block level.

The National Agroforestry Policy (2014) India was the first country to adopt such a policy, aimed at removing legal and bureaucratic hurdles related to the harvesting and transportation of trees grown on private farmland. This is a massive "policy enabler" for the agro-productive transformation of wastelands, as it encourages farmers to treat trees as crops, thereby stabilizing the soil while ensuring economic returns.

Policy / Scheme	Target Variable	Specific Application for Bankura
-----------------	-----------------	----------------------------------

**TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A
CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL**

National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA)	Soil Chemistry	Funding for dolomite application to neutralise acidic laterite; Soil Health Cards
PM Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) — Watershed Component	Surface Runoff	Construction of 30–40 model farm ponds per micro-watershed; check dams
National Agroforestry Policy (2014)	Economic Risk	Legalises harvesting and transport of farm-grown timber; enables Akashmoni (Acacia) revenue
Wasteland Atlas of India (NRSC)	Spatial Classification	Standardised taxonomy for "culturable" vs "unculturable" wastelands — adopted in this study

Table 8: National Policy-to-Technical Mapping for Bankura Interventions

4.2 State Level Policy Frameworks (West Bengal)

West Bengal State Action Plan on Climate Change (SAPCC) The SAPCC specifically identifies the "Red and Lateritic Zone" (including Bankura, Purulia, and parts of Birbhum) as a climate-vulnerable region. The policy mandates a shift toward Climate-Resilient Agriculture (CRA). It advocates for the diversification of the cropping pattern away from monsoon-heavy paddy toward drought-hardy crops like *Arhar* (pigeon pea), *Kodo* millet, and mustard, which can thrive on reclaimed marginal lands.

The Usharmukti Project (Convergence Model) Unique to West Bengal, Usharmukti is an institutional mechanism rather than a standalone law. it represents the convergence of MGNREGA labor with the technical expertise of the Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF) and the Department of Panchayats & Rural Development. In Bankura, this policy has been instrumental in the "Project Mode" execution of river basin rejuvenation, focusing on the tributaries of the Dwarakeswar and Kangsabati rivers.

West Bengal Trees (Protection and Conservation in Non-Forest Areas) Act: As a planner, this act is a vital regulatory constraint. It governs the felling of trees on private and "wasteland" holdings. Any reclamation strategy involving silviculture must align with the provisions of this Act to ensure that the "greening" of wastelands is legally

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

protected and that farmers have the simplified permits required to manage their new agro-productive assets.

Matir Srishti Scheme: Launched specifically to tackle the vast tracts of fallow and lateritic wastelands in Western Bengal, this scheme focuses on "Micro-Level Planning." It encourages the cooperative use of fallow land where groups of local villagers (Self-Help Groups) are encouraged to take up horticulture, floriculture, and fisheries. This is a direct policy vehicle for the "Social-Ecological System" (SES) approach mentioned in your theoretical framework.

Policy / Scheme	Primary Focus	Application for Bankura
SAPCC	Climate-Resilient Agriculture (CRA)	Mandates crop diversification (Arhar, Millets) in the Red & Lateritic Zone.
Usharmukti	River Basin Rejuvenation	Uses MGNREGA labor for "Ridge-to-Valley" watershed treatments.
WB Trees Act	Legal & Regulatory	Regulates tree felling on private/wasteland; essential for agroforestry.
Matir Srishti	Social-Ecological Systems (SES)	Empowers SHGs for horticulture and fisheries on fallow land.

Table 9: Key Policy Vehicles

4.3 National Case Study 1: Rajnagar IWDP, Jharkhand

The Rajnagar Integrated Watershed Development Project (IWDP), which encompasses the Saraikela and Kharsawan districts of Jharkhand, serves as a vital benchmark for understanding resource management in the Chota Nagpur fringe. This region shares an almost identical topographical and geological profile with the western stretches of Bankura, characterized by undulating terrain, hard lateritic crusts, and a semi-arid climate that creates a precarious environment for traditional agriculture. In these rugged plateau settings, the primary challenge addressed was "upland degradation," a process where the lack of vegetative cover and the thinness of the topsoil led to rapid erosion and the formation of gullies during the monsoon.

To combat this, the project implemented a multi-tiered engineering and biological strategy designed to manage the "ridge-to-valley" flow of water. The core of the technical intervention involved the construction of contour trenches along the slopes to intercept rainwater where it fell, reducing the volume of surface runoff and encouraging groundwater recharge. These were supplemented by loose boulder check dams built across drainage lines. Unlike rigid concrete structures, these check dams are designed to break the velocity of runoff while allowing silt to deposit behind them, eventually creating small, fertile patches of land suitable for cultivation in previously barren gullies.

The project's success, however, extended beyond structural engineering into the realm of ecological restoration. Recognizing that the acidic and nutrient-poor lateritic soils could not support intensive grain farming without massive inputs, the Rajnagar IWDP focused on establishing extensive plantations using hardy, indigenous species. By selecting flora specifically adapted to the harsh chemical profile of the plateau, the intervention successfully converted vast barren tracts into productive agroforestry belts. This transition provided a dual benefit: it stabilized the soil through root systems and provided local communities with diversified income streams from timber, fodder, and non-timber forest products, offering a sustainable model for the ecological and economic revitalization of similar terrains in Bankura.

4.4 National Case Study 2: Neeranchal National Watershed Project (NNWP)

The Neeranchal National Watershed Project (NNWP), implemented between 2016 and 2022, represented a paradigm shift in India's approach to land and water management. While previous efforts focused heavily on the construction of physical assets, Neeranchal—supported by the World Bank—prioritized institutional strengthening and decentralized planning. Its primary objective was to provide technical and managerial support to the watershed component of the Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY), effectively bridging the gap between national policy and local implementation. By integrating PMKSY with other rural development schemes, the project ensured that watershed interventions were not isolated activities but were part of a broader socio-economic upliftment strategy.

In states like Madhya Pradesh, the NNWP was instrumental in moving away from traditional, top-down engineering models toward a more inclusive, community-led framework. This transition recognized that the technical reclamation of land is merely a temporary solution if the local population is not invested in its long-term upkeep. To address this, the project focused on capacity building, providing training to local communities on climate-resilient agriculture, water budgeting, and the maintenance of shared assets. This grassroots empowerment ensured that the interventions were tailored to the specific ecological and social realities of the region, rather than following a rigid, one-size-fits-all blueprint.

A cornerstone of the Neeranchal model was the creation and formalization of Watershed Federations. These local institutions were designed to take ownership of the improved water availability and infrastructure long after the official project cycle ended. By establishing these federations, the project created a self-sustaining governance structure that manages water distribution fairly and maintains check dams and ponds. This focus on institutional "software" alongside physical "hardware" highlighted a critical lesson for projects in areas like Bankura: the success of watershed development is ultimately determined by the strength of the local institutions that manage them.

4.5 International Case Study 1: Loess Plateau Rehabilitation, China

The rehabilitation of China's Loess Plateau stands as the preeminent global benchmark for large-scale ecological restoration, offering profound lessons for regions grappling with systemic land degradation. Beginning in the mid-1990s, this massive undertaking sought to transform a landscape that was once among the most eroded on Earth, where centuries of overgrazing and unsustainable farming had resulted in massive soil loss and deep gully formation. The project moved beyond small-scale interventions, adopting a holistic approach that fundamentally restructured the relationship between the local population and their environment across an area spanning hundreds of thousands of square kilometers.

The core methodology centered on a dramatic physical reconfiguration of the landscape through the terracing of millions of hectares of steep slopes. By converting vertical, erodible inclines into horizontal, stable steps, the project effectively halted the

downward rush of rainwater, allowing it to soak into the ground rather than wash away the precious topsoil. This was coupled with a strict policy of "decommissioning" marginal or highly fragile lands; instead of attempting to farm every available acre, these sensitive areas were set aside for reforestation and natural regeneration. To ensure the success of this recovery, a comprehensive ban on slope-grazing was implemented, preventing livestock from destroying new saplings and allowing the natural vegetation to anchor the soil once more.

For the context of Bankura, the Loess Plateau success story demonstrates the transformative power of strategic "Zoning." It highlights a critical land-management philosophy: focusing intensive, high-yield agriculture on reclaimed and stabilized terraces while reserving the most fragile or steep slopes exclusively for ecological recovery. This dual-track strategy suggests that by concentrating resources on the most viable lands and allowing the most vulnerable ones to return to a natural state, it is possible to simultaneously increase food security and restore a dying ecosystem. The project proves that even the most severely damaged landscapes can be brought back to productivity if technical engineering is paired with a clear, enforced spatial planning framework.

4.6 International Case Study 2: Farmer-Managed Natural Regeneration (FMNR), Sahel

The Farmer-Managed Natural Regeneration (FMNR) model, most famously implemented across the Sahel zone of Niger, offers a revolutionary and low-cost alternative to traditional, capital-intensive reforestation projects. For decades, conventional environmental interventions relied on a "plantation" mindset, which involved the mass planting of nursery-raised saplings. These projects often faced dismal success rates due to the high costs of logistics, the fragility of the young plants in arid climates, and high mortality rates caused by a lack of long-term maintenance. FMNR departs from this approach by shifting the focus from planting new trees to nurturing what already exists within the landscape.

The core of the FMNR methodology lies in the discovery and management of the "Underground Forest." In many degraded environments, even when the surface appears barren or covered in stunted scrub, the soil often contains extensive, living root systems

and dormant stumps of native trees. By empowering local farmers to identify, protect, and systematically prune these existing stumps, the model triggers rapid growth. Because these trees already possess deep, established root systems, they are inherently more resilient to drought and poor soil conditions than any nursery-raised sapling. This process turns farmers into active stewards of their own land's biological recovery, requiring no expensive equipment or external seedlings.

This methodology is highly relevant for the scrublands and degraded lateritic tracts of Bankura. Much like the Sahel, Bankura possesses hardy native species that have been suppressed by overgrazing or frequent cutting but remain alive beneath the surface. Adopting FMNR would suggest that instead of investing heavily in high-maintenance plantations, the district could achieve large-scale restoration by managing natural regeneration. This approach is not only biologically resonant—using species already adapted to the local acidic soil—but also fiscally sustainable, as it shifts the primary investment from financial capital to the local knowledge and labor of the farming community.

4.7 Synthesis: A Policy-Driven Framework for Bankura

The synthesis of the aforementioned national and international case studies reveals that successful land reclamation in Bankura requires a "Policy-Plus" approach. This framework moves beyond the theoretical by ensuring that technical solutions are embedded within a robust ecosystem of administrative and financial support. It is not enough for the district to possess high-resolution GIS mapping or sophisticated topographical data; for these tools to translate into landscape change, the implementation must be "fed" by the consistent funding streams of the Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY). This ensures that the capital requirements for water harvesting structures and watershed development are met through established national mandates.

A critical component of this framework is the "manning" of these projects through the MGNREGA labor force, specifically utilized under the Usharmukti model. The Usharmukti initiative, which has already shown promise in Western West Bengal, leverages the massive workforce available through the rural employment guarantee

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A
CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

scheme to execute labor-intensive watershed tasks such as the digging of staggered trenches and the construction of check dams. By aligning the "ridge-to-valley" technical requirements of this thesis with the labor potential of the Usharmukti model, the proposed framework transforms large-scale land restoration into a vehicle for local employment and poverty alleviation.

Furthermore, the longevity of these interventions must be "protected" by the legal and regulatory guardrails provided by the West Bengal Trees (Protection and Conservation in Non-Forest Areas) Act. As suggested by the Loess Plateau and FMNR case studies, restoration is only permanent if the newly generated biomass and regenerated forests are shielded from premature exploitation. This legislation provides the necessary legal teeth to ensure that the "Underground Forest" and newly established agroforestry belts are managed sustainably rather than being subjected to unregulated felling or overgrazing.

Ultimately, by aligning the block-specific recommendations of this thesis with these existing state and national mandates, the proposed framework transitions from a purely academic exercise into an implementable reality for local governance. It creates a cohesive strategy where technical site-selection—based on the soil and slope analysis of Bankura's 22 blocks—meets the financial, human, and legal capital required for execution. This alignment ensures that the District Magistrate and local Panchayats have a ready-to-use blueprint that is both fiscally viable and legally sound.

CHAPTER 5: PROFILE OF THE STUDY AREA – BANKURA DISTRICT

5.1 Geographical Location and Administrative Setup

Bankura district, situated in the western part of West Bengal, serves as a vital transition zone between the rugged Chota Nagpur Plateau to the west and the lower Gangetic plains to the east. Strategically positioned within the Medinipur Division, the district is a core component of the "Rarh" region of Bengal—a landscape defined by its distinct red laterite soil, ancient geological formations, and undulating physiography. The district's physical boundaries are largely defined by natural watercourses and administrative borders; the Damodar River flows along the northern edge, acting as a natural boundary that separates Bankura from Paschim Bardhaman. To the west lies the plateau-heavy terrain of Purulia, while the eastern and southern borders meet the fertile stretches of Hooghly and Paschim Medinipur respectively.

The district occupies a significant spatial extent, delimited by latitude 22° 38' N and longitudes 86° 36' E to 87° 47' E. This vast area is meticulously documented by the Survey of India, covered under the technical toposheets 73I, 73J, 73M, and 73N. These coordinates place Bankura in a unique climatic and geological pocket where the weather is generally drier and the heat more intense than in the coastal districts of West Bengal. Administratively and demographically, Bankura holds a prominent position within the state; historically, it has ranked high in West Bengal in terms of both total population density and literacy rates, reflecting a resilient social fabric that has thrived despite the challenging, drought-prone environment.

From a landscape perspective, Bankura acts as a representative bridge between two extremes: the rugged, forested highlands of the plateau fringe and the fertile, alluvial deltaic tracts of the east. This creates a fascinating gradient of land use, where the western blocks are dominated by forests and upland agriculture, while the eastern blocks mirror the intensive multi-cropping systems of the plains. The administrative setup is specifically geared toward navigating these sharp regional disparities. The district is divided into three major sub-divisions—Bankura (Sadar), Khatra, and Bishnupur—which together oversee 22 development blocks. This decentralized structure allows local governance to address specific issues, such as the severe water

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A
CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

scarcity in the western undulating uplands versus the flood management and irrigation needs of the eastern alluvial basins.

Administrative Metric	Details
Total Geographical Area	6,882 km ²
Sub-divisions	Bankura Sadar, Khatra, Bishnupur
Development Blocks	22 blocks
Neighbouring Districts	Paschim Bardhaman (N), Purulia (W), Hooghly (E), Paschim Medinipur (S)
Geographical Coordinates	22°38'N 86°36'E – 87°47'E
Survey of India Toposheets	73I, 73J, 73M, 73N
Population (2011 Census)	3,596,674
Position in State	Medinipur Division — core of the "Rarh" region

Table 10: Administrative Setup

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A
CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

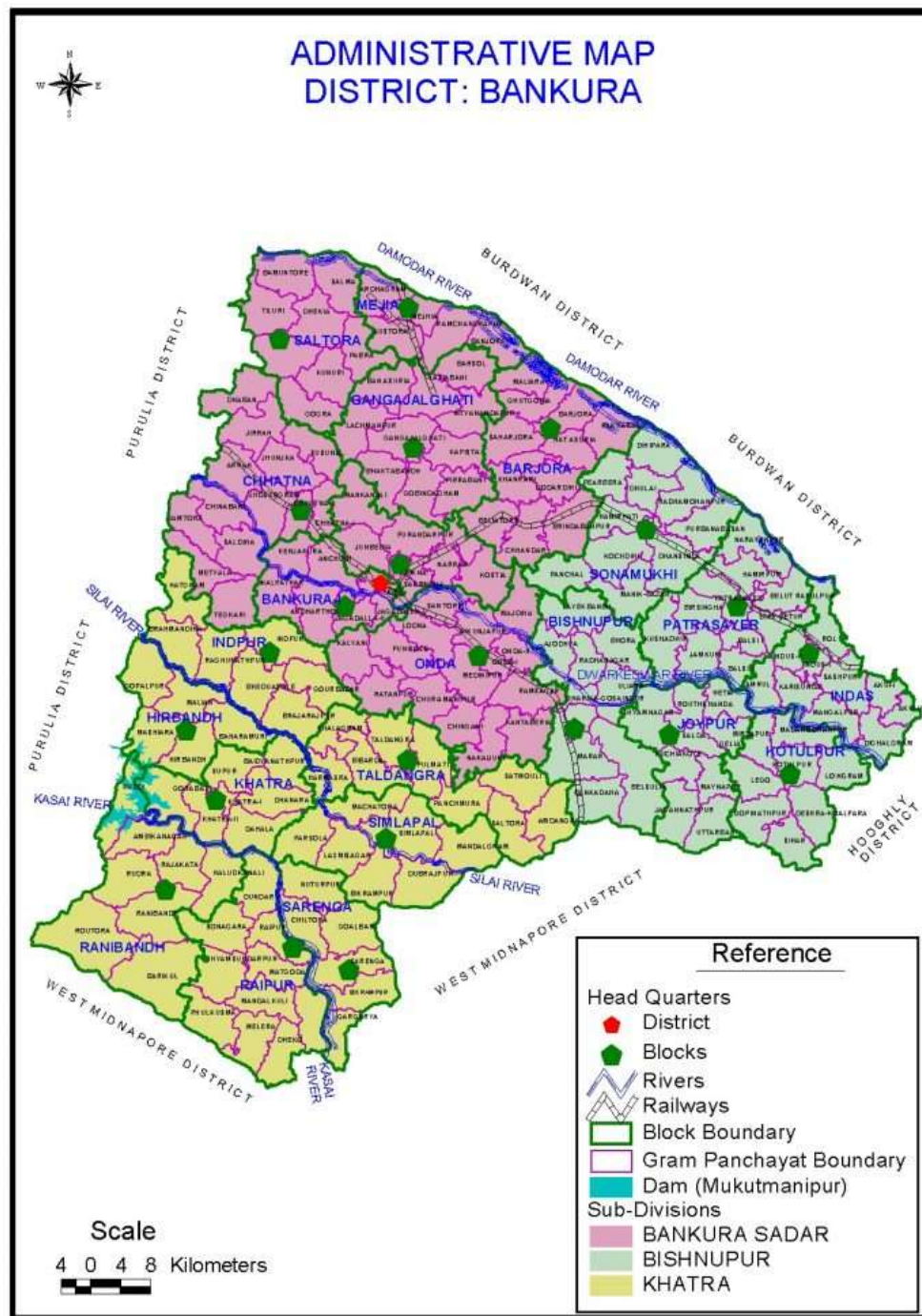


Fig. 10: Bankura District Administrative Map

5.2 Physical Environment and Physiography

The physical landscape of Bankura is defined by a profound east-west dichotomy that influences everything from its agricultural potential to its ecological character. This district serves as a critical physiographical bridge, acting as a "connecting link" between the steep, rugged highlands of the Chota Nagpur Plateau to the west and the sprawling, fertile alluvial plains of the lower Gangetic delta to the east. This transition creates a diverse relief pattern where the elevation gradually tapers down from the western uplands toward the eastern riverine flats.

In the western sector, the terrain is characterized by an undulating and rugged surface that represents the advanced guard of the central Indian hill system. This area is punctuated by residual hills and monadnocks that rise sharply from the rolling plains, providing a dramatic break in the horizon. The most prominent of these are Susunia Hill, which reaches an elevation of 1,442 feet, and Biharinath Hill, the highest point in the district at 1,469 feet. These hills are often covered in thick scrub-jungle and represent the ancient metamorphic core of the region. Between these peaks, the land consists of a series of ridges and valleys where the surface has frequently been denuded, leaving behind exposed stretches of hard, rocky ground and a landscape that takes on a park-like appearance during the monsoon.

The soil composition across this landscape follows a similar east-west gradient, broadly grouped into red, alluvial, and laterite types. The western and south-central regions are dominated by lateritic soils, which are distinguished by their high acidity, low organic matter, and a characteristic reddish hue derived from iron and aluminum oxides. These soils are highly porous and prone to heavy leaching, which often results in the formation of a hard crust that complicates agricultural efforts. In the central tracts, one finds "typical red soils" and sedentary brown soils derived from parent rocks like sandstone and granite gneiss. These soils generally support Sal vegetation but lack the nutrient density found further east.

In stark contrast, the eastern region levels out into a vast, relatively flat alluvial plain. This area is the product of millenniums of depositional activity by major river systems, resulting in deep, fertile deposits that are the lifeblood of the district's intensive rice cultivation. Unlike the western crusts, these alluvial soils possess superior water-holding capacity and a much richer nutrient profile. The soil textures vary from sandy

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A
CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

loam—which covers much of the district—to heavy clay and clay-loam found specifically within the floodplains of the Damodar and Dwarkeswar rivers. This fertility allows the eastern blocks to maintain a high level of agricultural productivity that mirrors the lush deltaic tracts of neighboring Hooghly.

The district's river system is a defining feature of its physical environment, consisting of several parallel rivers such as the Damodar, Sali, Dhalkisor, Gandheswari, Silai, and Kasai. These are primarily hill streams that originate in the western uplands and flow in a south-easterly direction. These rivers are notorious for their seasonal volatility; during the monsoon, they can transform into impassable torrents subject to sudden freshets and dangerous "head-waves" known locally as *hurpaban*. However, during the scorching summer months, many of these rivers dwindle into insignificant streams or dry up entirely, leaving behind wide, sandy beds. This seasonal cycle of abundance and scarcity dictates the rhythm of rural life and necessitates the extensive use of *bandhs* or embankments to capture surface drainage for irrigation.

Bankura is also fortunate to possess significant natural and mineral wealth, with forests covering approximately 21.5% of its geographical area. These forests are predominantly comprised of Sal trees and associated species, along with plantations of Eucalyptus and Akashmoni. While these wooded areas provide a distinct cultural and economic identity to the district, they also present unique challenges, such as the increasing frequency of elephant depredation as migratory herds move through the forest fringe. Beneath the surface, the northern and western parts of the district harbor valuable mineral deposits, including substantial coal reserves in the Mejhia and Borjora areas and prolific pockets of China clay. These mineral resources, combined with the district's unique "Rarh" geography, provide a multifaceted foundation for both ecological conservation and industrial potential.

Soil Category	Dominant Blocks	Key Characteristics
Laterite / Red Soil	Chhatna, Saltora, Khatra	High acidity, low organic matter, reddish hue from iron oxides
Sandy Red Soil	Gangajalghati, Barjora	Light and porous; derived from sandstone and granite gneiss

**TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A
CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL**

Alluvial Soil	Indas, Kotulpur, Sonamukhi	High fertility, superior water-holding capacity, supports intensive farming
Clay / Clay-Loam	Damodar floodplain areas	Heavy, moisture-rich; ideal for paddy but prone to seasonal flooding

Table 11: Physiography

5.3 Climatic Conditions and Hydrology

The Bankura District is defined by a tropical, semi-arid climate and is historically recognized as a perennially drought-prone region. Its environmental challenges are deeply rooted in an undulating topography and a complex geological transition, situated between the rugged Chhota Nagpur plateau and the lower Bengal delta. This unique position creates a landscape that is both ecologically diverse and significantly stressed by seasonal extremes.

5.3.1 Thermal Variations and Air Quality

The district is notorious for extreme thermal variations, particularly within its upland tracts where the lack of dense vegetation and the presence of heat-absorbing rock formations exacerbate the heat. During the pre-monsoon months of April and May, temperatures frequently soar to 45°C, creating a harsh environment for both agriculture and residents. This intense heat is often accompanied by hot, parched westerly winds known locally as "Loo" that sweep across the plains from March until early June, further stripping the soil of moisture and contributing to the overall aridity of the landscape. Conversely, the region experiences a sharp shift in the winter months, when the mercury can drop to a minimum of 10°C, highlighting a dramatic annual temperature range that dictates the local rhythm of life.

5.3.2 Cycle and Precipitation

While Bankura receives a moderate amount of annual precipitation, its distribution and the specific characteristics of the soil create significant hydrological stress. The average

annual rainfall is approximately 1,380 mm to 1,400 mm, but this volume is almost entirely concentrated within the brief monsoon window of June to September. This seasonal imbalance means that for the majority of the year, the district receives very little moisture.

Furthermore, the physical geography of the region prevents the efficient capture of this water. Due to the undulating topography and the presence of hard-rock upland areas consisting of ferruginous soil and laterite beds, there is a remarkably high rate of surface runoff. This means that instead of soaking into the ground, rainwater quickly flows away into rivers and streams. The combination of these hard-rock beds and the low water-holding capacity of the soil results in minimal groundwater infiltration. This hydrological inefficiency often leads to acute drinking water shortages by the end of the financial year, leaving communities vulnerable as they wait for the next monsoon cycle.

5.3.3 Drought and Vulnerability

The district's susceptibility to drought is a result of both natural climatic factors and inherent soil limitations. The North-West part of the district is particularly vulnerable, encompassing blocks such as Chhatna, Saltora, Gangajalghati, Barjora, Bankura-I, Bankura-II, Mejia, Indpur, Hirbandh, and Ranibandh. The historical impact of these conditions is severe; for instance, in 2014, drought was officially declared in 818 Mouzas across 16 different blocks. This vulnerability is compounded by high evapotranspiration rates during the pre-monsoon and post-monsoon periods, which quickly deplete whatever surface water remains, further parching the land.

5.3.4 Flash Floods and Drainage

Paradoxically, despite its status as a drought-prone area, the district also faces significant seasonal flood risks. During the monsoon, low-lying areas near major rivers like the Damodar, Dwarakeswar, Kangsabati, and Shali are prone to sudden flash floods and prolonged inundation. These events are often caused by heavy rainfall in upper catchment areas, the siltation of riverbeds which reduces their carrying capacity, and the necessary release of excess water from major irrigation projects like the Damodar

Valley Corporation (DVC) or Kangsabati. Beyond the immediate danger to property and life, these flood events have introduced significant soil erosion issues. A notable example is the formation of "gullies" caused by the Shali River as it changes its course, which permanently alters the landscape and reduces the amount of viable land for cultivation.

5.3.5 Ground Water Level Monitoring (2019-2022)

The district administration maintains a rigorous monitoring system for water levels across numerous sites to manage these scarce resources. Data collected between 2019 and 2022 reveals significant seasonal fluctuations in well depths. For example, at the Lalbazar Garage site, water was found at ground level during the peak of the monsoon in August but dropped to a depth of 3.6 meters during the dry season of April 2019. More dramatic variations are seen in areas like Andarhol, where levels shifted from 3.50 meters to nearly 9.55 meters. These fluctuations underscore the district's heavy reliance on seasonal recharge and the precarious nature of its water security.

5.4 Socio-Economic Structure and the Agrarian Economy

The socio-economic framework of Bankura is fundamentally agrarian, with a vast majority of the population relying on agriculture and allied sectors—such as livestock rearing and forest produce collection—for their livelihood. Despite this deep-rooted reliance, the economic output of the district is hampered by significant structural constraints that create a stark divide between different geographical zones. The district is characterized by an undulating topography with land slopes varying from 0.4% to 10%, leading to distinct agricultural conditions in the east and west.

5.4.1 Regional Disparities in Soil and Productivity

Agricultural conditions differ greatly between the eastern and western portions of the district. To the east, the regions of Indas, Kotalpur, and northern Sonamukhi consist of rich, recent alluvial soil, forming a continuation of the fertile plains found in neighboring Burdwan and Hooghly. These areas are more productive, benefit from

better moisture retention, and are generally composed of loamy or clayey textures that are highly conducive to intensive farming.

In contrast, the western and central uplands represent the majority of the district's landmass and consist largely of infertile laterite soil. This soil is characterized as being light, porous, and acidic in nature, with a notably low organic matter content and poor water-holding capacity. Because the soil is so porous, it struggles to retain the nutrients and moisture necessary for sustained growth, making the agricultural success of these blocks almost entirely dependent on the timing and consistency of the monsoon rains.

5.4.2 The Challenge of Rain-fed Agriculture

Agriculture in Bankura is a high-stakes endeavor that depends heavily on the monsoon, making it vulnerable to the whims of unseasonable or poorly distributed rainfall. While the annual rainfall of approximately 1,423 mm is generally sufficient in volume, the porous nature of the lateritic soil and the undulating terrain lead to rapid drainage and percolation. This means that even during years of "normal" rainfall, the water often runs off before it can be utilized by the crops or absorbed into the groundwater table.

The success of the staple Aman (winter) rice crop depends heavily on rainfall in September and October to mature the grain. If the rains fail during these critical months, the entire harvest can be jeopardized. Because of these hydrological limitations and a lack of widespread modern irrigation, large upland tracts are restricted to a single Kharif crop per year. This leaves the land fallow for the remainder of the year, perpetuating a cycle of seasonal poverty and forcing many residents into migratory labor to survive the dry months.

5.4.3 Irrigation Infrastructure and Historical Systems

Artificial irrigation is a necessity in nearly all parts of the district except for the eastern alluvial flats. Historically, the region utilized a simple but effective system of "bandhs" (embankments) and "khals" (channels) to manage its water resources. By throwing embankments across drainage lines at higher levels than the fields, farmers could prevent rapid runoff and provide water to crops through slow percolation. This

indigenous engineering allowed for some level of stability in an otherwise unpredictable climate.

One notable historical project was the Subhankari daura, a network of channels developed about a century ago by the Bishnupur Raj to irrigate approximately 80 square miles. However, many of these channels have since silted up or fallen into disrepair. Modern canal irrigation remains largely unknown or impracticable in the upland areas due to the broken surface of ridges and valleys, which makes large-scale engineering difficult. While some eastern blocks benefit from canal water, the western blocks still rely on traditional tanks, reservoirs, and newer government-funded pump sets.

5.4.4 Principal Crops and Livestock

Rice remains the undisputed staple of Bankura, categorized primarily into Aman (winter rice) and Aus (autumn rice). Aman rice is the dominant crop, occupying roughly 84% of the normal net cropped area. Beyond rice, the district has developed a diverse crop portfolio that includes sugarcane, potato, wheat, and various vegetables. In recent years, agricultural authorities have placed a specific emphasis on introducing oilseeds and pulses like Arhar, mustard, and sunflower to bridge the gap between local demand and production.

Livestock rearing serves as a critical allied sector, yet it faces its own set of challenges. The breeds of cattle, sheep, and goats in the district are often described as weak and stunted, likely due to nutritional deficiencies. While the western part of the district offers jungle pasturage, the eastern blocks face a growing shortage of grazing land. As population pressure increases, traditional pastures are increasingly converted into paddy fields, leaving farmers with fewer resources to maintain healthy livestock.

5.4.5 Modernization and Support Schemes

To combat structural poverty and low productivity, the district has seen a gradual shift toward modernization. There is an increasing use of improved seeds, fertilizers, and agricultural machinery like tractors and power tillers. Various government schemes, such as the Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) and the National Food Security Mission (NFSM), have been implemented to distribute pump sets, establish soil testing

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

laboratories, and provide seed kits for pulses and maize. These interventions aim to increase cropping intensity and provide farmers with the tools needed to break the cycle of single-crop dependency and seasonal migration.

Land Category	Area (Hectares)
Net Sown Area	~3,80,000 ha (Paddy dominated)
Culturable Wasteland	11,703 ha
Barren/Uncultivable Land	36,692 ha
Current Fallow	16,480 ha

Table 12: Land Use and Cropping Intensity (2026 Estimates)

5.5 Land Transformation and the Wasteland Context

The geography of Bankura is defined by a significant prevalence of wastelands, which emerge at the intersection of natural environmental stressors and human-induced land degradation. Positioned geographically as a transitional zone between the fertile plains of Bengal and the rugged Chhota Nagpur plateau, the district features an undulating landscape primarily in its western reaches. This area is characterized by ferruginous soil and dense beds of laterite, creating a challenging physical environment that is naturally prone to lower productivity and higher rates of erosion.

The process of land degradation is driven by several intersecting physical and climatic factors. In the western and northern upland tracts, such as Chhatna, Saltora, and Mejia, the soil possesses an inherently low water-holding capacity. This physical limitation is exacerbated by high runoff rates during the monsoon and extreme thermal stress during the pre-monsoon months. From March to June, the region is scorched by hot westerly winds, with ambient temperatures frequently climbing to 45°C . These conditions strip the land of moisture, while human activities like overgrazing and deforestation further destabilize the topsoil. Even the presence of water can be destructive; sudden flash floods often lead to the formation of deep gullies as rivers like the Shali shift their courses, effectively carving away arable land.

This environmental fragility translates directly into deep-seated socio-economic vulnerability for the local population. Bankura is perennially drought-prone, yet it

**TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A
CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL**

remains heavily dependent on an agrarian economy. With a labor force that includes hundreds of thousands of cultivators and agricultural laborers, any shift in land quality has an immediate impact on livelihoods. When the land fails to produce due to encroaching wastelands or seasonal droughts—such as in 2014 when over 800 mouzas were officially declared drought-hit—these communities face severe economic marginalization. The scarcity of water is a constant hurdle, as groundwater levels in the hardest-hit blocks often drop to depths of 7 to 9 meters before the monsoon, frequently leaving traditional dug wells completely dry.

To combat this cycle of transformation, the district has moved toward a more proactive reclamation strategy. Strategic interventions focus heavily on sophisticated water management, including rainwater harvesting and the restoration of inlets for local tanks to capture and retain high runoff. Social forestry initiatives aim to re-stabilize the soil by reclaiming jungle tracts and preventing the further loss of vegetation cover. On the agricultural front, there is a push to introduce drought-resistant crop varieties that are better suited to the district's semi-arid climate. By integrating infrastructure repairs, such as reinforcing weak embankments against gully erosion, with community-level capacity building, the region seeks to transform these "wastelands" back into productive or ecologically stable landscapes.

Block Name	Degradation Category	Primary Cause	Priority Level
Chhatna	Culturable Wasteland / Scrubland	Moisture deficit, poor soil structure	Critical
Saltora	Lateritic Barren Land	Topographical runoff, overgrazing	Critical
Onda	Degraded Forest / Gullied Land	Overgrazing, soil erosion	High
Indpur	Culturable Wasteland	Seasonal water scarcity	High
Ranibandh	Gullied / Ravenous Land	Topographical runoff, Shali river course change	High
Mejia	Mixed Degradation	Industrial pressure + lateritic constraints	Medium

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A
CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

Table 13: Block-wise Wasteland Context and Priority Classification — Bankura
District

CHAPTER 6: METHODOLOGY- AN INTEGRATED GEOSPATIAL FRAMEWORK

The methodological backbone of this study is built upon a structured, multi-phase framework designed to synthesize complex environmental variables into actionable spatial intelligence. This approach integrates advanced Remote Sensing (RS), Geographic Information Systems (GIS), and Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) to provide a robust foundation for land-use planning. By housing various quantitative and qualitative data types within a unified spatial environment, the research ensures a systematic approach to assessing both the environmental constraints and the developmental potential of the region.

6.1 Data Acquisition and Pre-processing

The foundation of this research rests upon the construction of a comprehensive, multi-scalar database that integrates high-resolution secondary data with primary spatial observations. The data acquisition phase is designed to capture the multifaceted nature of land transformation by sourcing information from diverse platforms, ranging from space-borne sensors to localized administrative records. By synthesizing these disparate data streams, the study creates a holistic view of the physical and socio-economic drivers affecting the region.

6.1.1 Remote Sensing Data and Image Restoration

Multi-spectral satellite imagery serves as the primary longitudinal data source, offering a detailed view of land cover and vegetation health over time. To ensure that the spectral signatures are accurate and comparable across different temporal periods, the raw imagery undergoes rigorous pre-processing. This includes radiometric calibration to convert raw digital numbers into physical units of reflectance and atmospheric correction to remove the scattering and absorption effects of aerosols and water vapor. These steps are vital for the reliable extraction of biophysical indicators, such as the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) or Land Surface Temperature (LST), which are used to identify the extent of wasteland expansion.

6.1.2 Topographic Modeling via DEMs

To account for the undulating terrain characteristic of the transition from the Bengal plains to the Chhota Nagpur plateau, the study processes high-resolution Digital Elevation Models (DEMs). These models are used to derive a suite of critical topographic metrics that influence water movement and soil stability. Slope and aspect maps are generated to identify areas prone to rapid runoff, while complex drainage networks are delineated to understand the catchment dynamics. By modeling these physical constraints, the framework can pinpoint "gully" erosion hotspots where the landscape is most susceptible to being carved into wastelands by hydrological forces.

6.1.3 Data Normalization and Spatial Integration

A significant challenge in regional spatial analysis is the integration of non-spatial data with geographic layers. In this phase, traditional soil survey maps and district-level census data—including demographics and agricultural labor statistics—are digitized and converted into a structured GIS format. To prevent spatial distortion during the subsequent overlay analysis, all datasets are normalized into a single, cohesive projected coordinate system (such as UTM WGS84). This rigorous alignment ensures that a specific pixel of satellite data perfectly corresponds with its corresponding soil type and socio-economic census block, allowing for precise multi-criteria evaluation.

6.2 Geospatial Analysis and Feature Extraction

The transformation of a multi-scalar database into a decision-support system requires the application of advanced geospatial analysis techniques. This phase focuses on translating processed spectral and topographic data into thematic layers that represent the physical and functional realities of the landscape. By extracting specific features through algorithmic analysis, the framework can isolate patterns of land degradation and identify the underlying environmental drivers that contribute to the formation of wastelands.

6.2.1 Land Use/Land Cover (LULC) Classification

The primary analytical step involves the creation of a comprehensive Land Use/Land Cover (LULC) map. This study utilizes supervised classification algorithms, such as Maximum Likelihood or Random Forest, where the system is "trained" using ground-truth sites to recognize spectral signatures associated with specific land types. This process categorizes the satellite imagery into distinct classes, including dense forest, agricultural land, water bodies, and settlements. Critically, this classification highlights areas of active degradation—such as fallow land, scrubland, and barren rocky outcrops—allowing for a precise spatial quantification of the district's wasteland footprint.

6.2.2 Biophysical Indexing for Environmental Health

To move beyond simple classification and assess the actual vitality of the landscape, the study employs specialized biophysical indices. The Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) is the core metric used to quantify biomass density and spatial health. By calculating the ratio between the red and near-infrared light reflected by the Earth's surface, NDVI provides a numerical value that distinguishes between healthy, chlorophyll-rich vegetation and stressed or sparse greenery. This index is essential for identifying "silent" degradation, where land may still appear green but is experiencing a significant decline in productivity and ecological resilience.

6.2.3 Proximity Analysis and Connectivity Modeling

Beyond the physical characteristics of the soil and vegetation, the utility of a land parcel is determined by its relationship to the surrounding environment. The framework utilizes Euclidean distance tools to generate continuous surface maps representing the accessibility of land parcels to critical resources. This proximity analysis maps the distance of degraded lands to essential water sources, primary and secondary road networks, and other vital infrastructure. By creating these layers of connectivity, the study can determine the feasibility of reclamation projects; for example, a wasteland parcel located near a perennial water source or a major transport corridor is prioritized for restoration due to its higher potential for successful agricultural or industrial transition.

6.3 Multi-Criteria Decision-Making (MCDM) Framework

The core of the study's analytical power lies in its ability to synthesize multiple, often conflicting, environmental and physical variables into a single decision-making model. By utilizing a Multi-Criteria Decision-Making (MCDM) framework, the research moves beyond simple observation and into the realm of strategic planning. This framework acts as a computational lens that evaluates the landscape's potential for specific interventions—such as forest restoration, agricultural expansion, or infrastructure development—by weighing various geographical constraints against developmental goals.

6.3.1 Parameter Standardization and Reclassification

A primary challenge in spatial modeling is that geographical variables are measured in incompatible units; for example, slope is measured in degrees, rainfall in millimeters, and soil quality in categorical types. To resolve this, the study employs parameter standardization. Each individual variable is reclassified into a common, standardized suitability scale, typically ranging from 1 to 5 or 1 to 9. In this system, a value of 1 might represent "Least Suitable," while the highest value represents "Highly Suitable." This normalization process is critical because it creates a "level playing field," allowing for a direct and equitable comparison between disparate factors that would otherwise be mathematically incompatible.

6.3.2 The Analytic Hierarchy Process (AHP) and Pairwise Comparison

Once the layers are standardized, the study must determine which factors are most influential for the desired outcome. For this, the Analytic Hierarchy Process (AHP) is applied. AHP is a structured technique for organizing and analyzing complex decisions by breaking them down into a hierarchy. The study conducts a systematic pairwise comparison, where each criterion is evaluated against every other criterion to determine its relative importance. For instance, in a wasteland reclamation project, soil texture might be deemed more critical than proximity to roads. By using a standardized comparison scale, the AHP method derives objective, mathematically consistent

weights for each parameter, ensuring that the final model is not skewed by subjective bias.

6.3.3 Weighted Overlay and Composite Suitability Mapping

The final stage of the MCDM framework is the execution of a spatial weighted overlay. In this process, the standardized thematic layers are multiplied by their respective AHP-derived weights and then mathematically summed. This calculation is performed on a pixel-by-pixel basis across the entire study area. The result is a high-resolution composite map where each pixel represents a cumulative suitability score. These scores reflect the aggregated impact of all environmental and physical inputs, providing a visual and statistical roadmap that identifies "hotspots" for intervention. This allows planners to see exactly where a reclamation project has the highest probability of success based on the total geographical context of the district.

6.4 Synthesis and Zonation

The final phase of the integrated geospatial framework involves the transition from theoretical suitability to a practical, field-aligned spatial strategy. This synthesis stage ensures that the mathematical outputs of the multi-criteria model are reconciled with the physical and legal realities of the Bankura landscape. By merging the composite suitability map with ground-validated constraints and high-risk parameters, the methodology produces a refined blueprint for regional land management that adheres to real-world limitations.

One of the critical components of this phase is constraint integration and spatial filtering. While the suitability model identifies areas with high potential for reclamation or development, it must be filtered through a layer of real-world exclusion zones. This integration acts as a critical safety valve, removing areas from development consideration that are designated as protected conservation forests, ecologically sensitive riparian buffers, or historical heritage sites. Furthermore, the model is cross-referenced with hazard maps—specifically those identifying flood-prone regions near the Shali and Damodar rivers—to ensure that proposed interventions do not inadvertently place infrastructure or communities in high-risk zones. This filtering

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

process ensures that the final strategy is not only geospatially sound but also legally and environmentally compliant.

Once these constraints are applied, the remaining data undergoes a process of spatial filtering and aggregation to define distinct management zones. Instead of fragmented, pixel-level classifications, the methodology clusters similar suitability profiles into contiguous land-use zones. This zonation process provides clear, actionable insights for district planners by effectively segregating the landscape into four primary categories. Intensive Development Zones are designated in areas with high connectivity and stable soil profiles suited for infrastructure or industrial expansion. Sustainable Resource Use Zones represent regions where agricultural reclamation is viable through improved water management and the introduction of drought-resistant cropping. Ecological Restoration Zones target degraded wasteland or "gullied" terrain that requires urgent social forestry and soil stabilization measures. Finally, Permanent Conservation Zones protect high-value natural habitats or steep upland tracts that must remain undisturbed to maintain regional biodiversity and prevent further erosion.

The final output of this synthesis is a comprehensive spatial strategy that serves as a data-driven roadmap for local authorities. By providing a visual and statistical breakdown of these zones, the methodology empowers stakeholders to allocate resources more effectively, prioritizing high-impact reclamation projects in blocks where water scarcity and land degradation are most acute. This evidence-based approach ensures that a philosophy of proactive mitigation is translated into tangible land-use policies that enhance both environmental resilience and the socio-economic stability of the district's labor force.

CHAPTER 7: ANALYTICAL FRAMEWORK AND METHODOLOGY

7.1 Overview of the Analytical Approach

The core of this research is built upon a multi-disciplinary analytical framework designed to deliver a comprehensive and robust evaluation of land resources. This approach moves beyond simple mapping by integrating advanced geospatial data analysis with structured decision-making, economic modeling, and policy evaluation. The primary objective of this framework is to bridge the gap between raw data and practical application, transforming environmental and socioeconomic indicators into actionable land-use strategies that can be implemented at the district level.

A key strength of this integrated methodology is its ability to synthesize diverse data streams into a unified narrative. By combining these various disciplines, the framework ensures that land-potential assessments are not just scientifically rigorous but also grounded in practical and economic reality. For instance, while geospatial analysis identifies the physical capacity of a land parcel for reclamation, economic modeling assesses the financial feasibility of such an intervention, and policy evaluation ensures alignment with existing governmental mandates like the National Mineral Policy or regional disaster management protocols.

Ultimately, the analytical approach functions as a diagnostic tool for the region's landscape. It allows for a multi-layered understanding of land transformation, particularly in identifying how environmental stressors like high temperatures and low water-holding capacity intersect with human-induced degradation. By maintaining this holistic perspective, the study provides a foundation for "Disaster Management 2.0," shifting the focus from reactive relief to proactive, data-driven land-use planning that enhances both ecological resilience and the stability of the local agrarian economy.

7.2 Spatial and Remote Sensing Analysis

Spatial analysis serves as the fundamental layer for understanding the physical and environmental characteristics of the study area, moving far beyond mere surface-level observations. By leveraging high-resolution satellite imagery and topographic data, the

framework allows for a multi-dimensional analysis of the landscape's biophysical properties. This deep-dive approach is essential for decoding the complex vegetation and moisture dynamics that define Bankura's fragile ecosystem, where seasonal shifts and environmental stress dictate the transition between productive land and wasteland.

7.2.1 Advanced Spectral Indexing

To quantify environmental health, the study utilizes specialized spectral indices that extract data invisible to the naked eye. The Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) is employed to measure photosynthetic activity by analyzing the contrast between near-infrared and red light reflectance. This allows for the precise mapping of vegetation health, biomass density, and seasonal variations, which is vital for identifying areas where natural greenery is thinning due to soil degradation. Simultaneously, the Normalized Difference Water Index (NDWI) is integrated into the workflow. By utilizing the near-infrared and short-wave infrared bands, NDWI highlights surface water bodies and assesses soil moisture levels. This dual-index approach is a critical requirement for identifying drought-prone zones or areas of temporary water saturation, providing a baseline for water management strategies in blocks prone to extreme moisture stress.

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

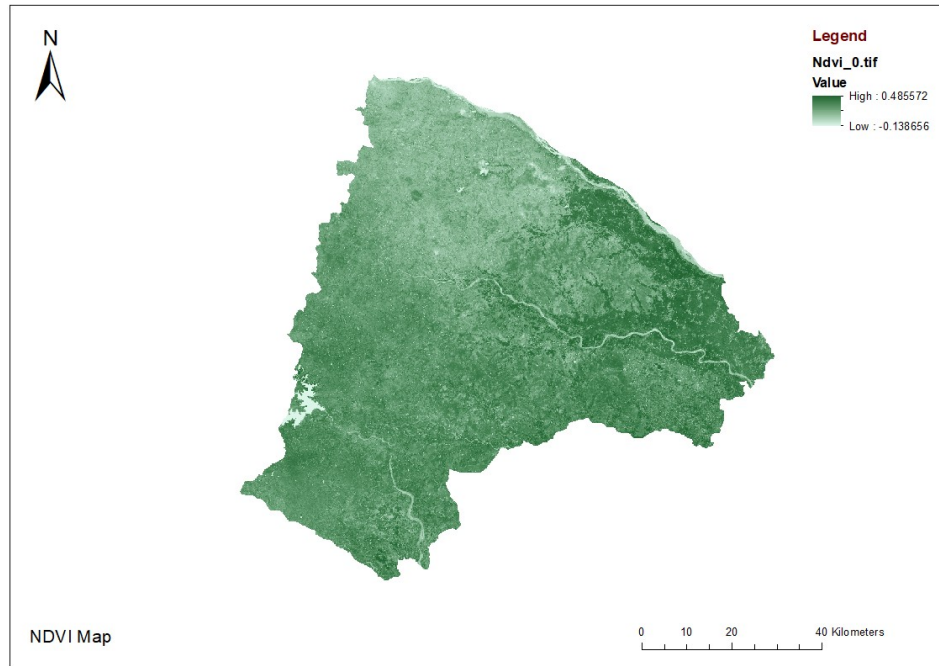


Fig. 11: NDVI (MAY 2026)

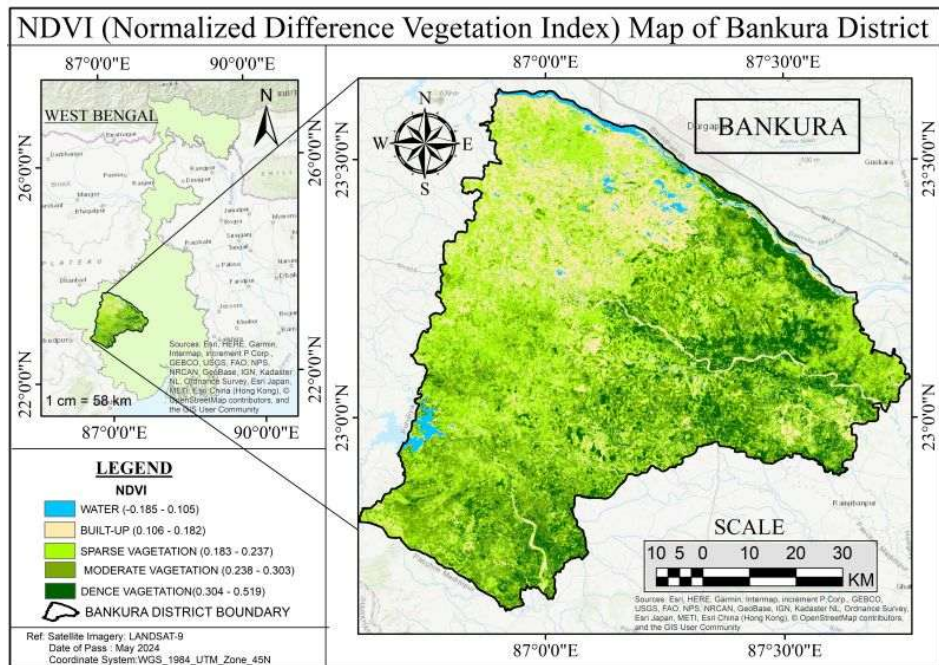


Fig. 12: NDVI (MAY 2014)

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

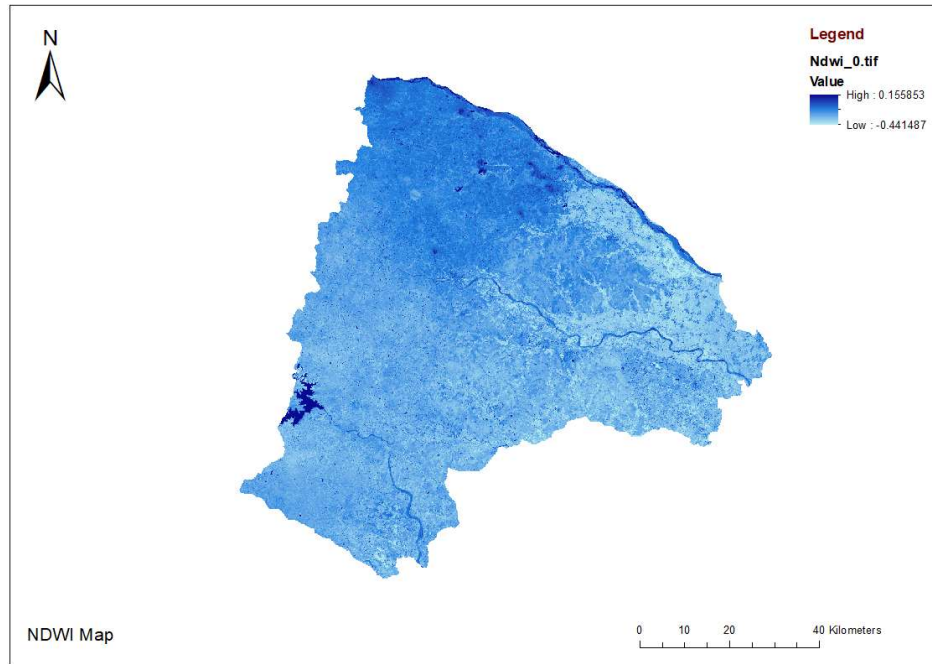


Fig. 13: NDWI (MAY 2026)

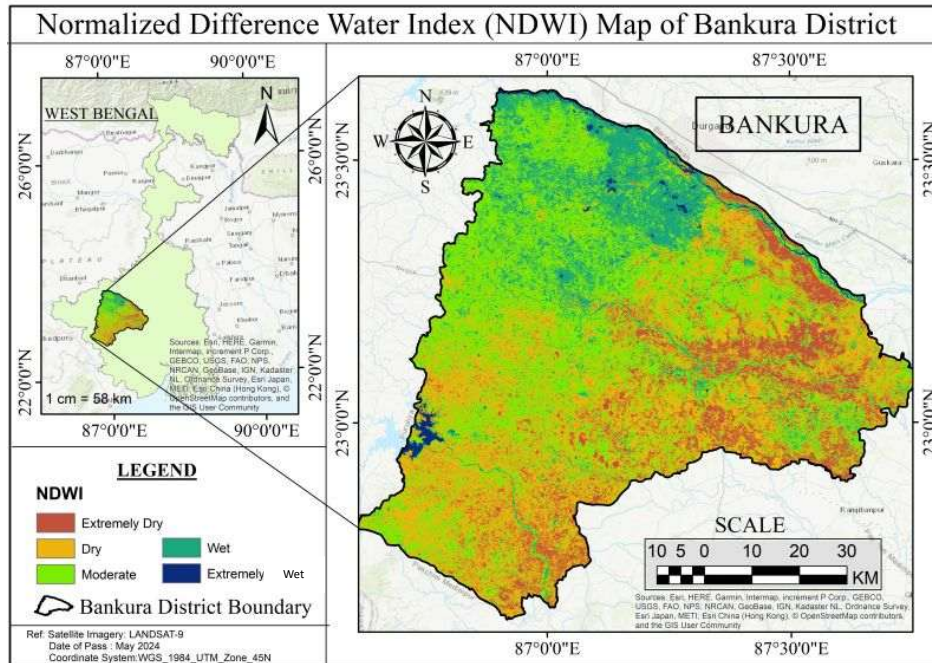


Fig. 14: NDWI (MAY 2014)

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

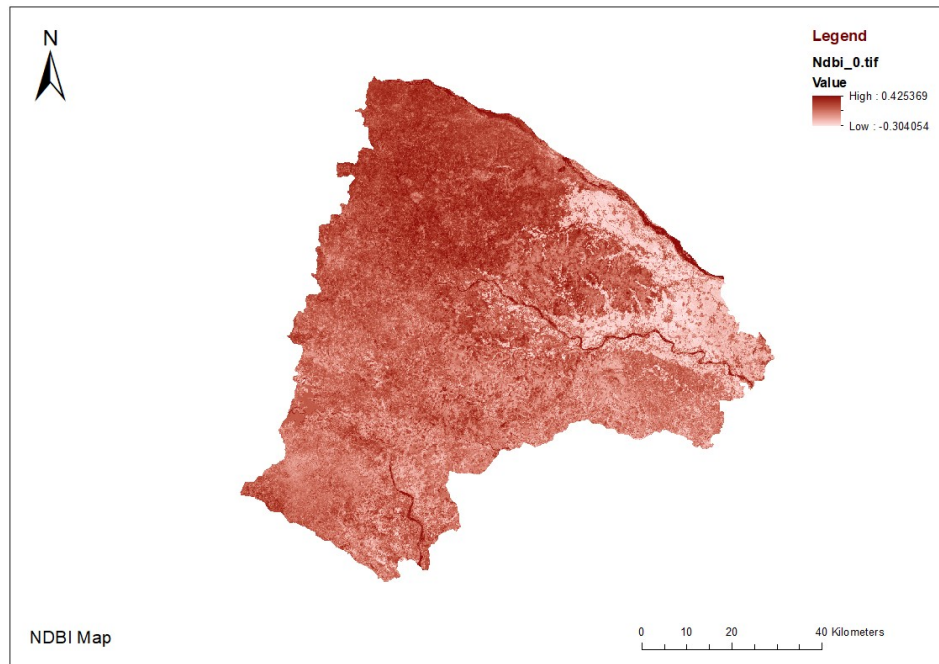


Fig. 15: NDBI (MAY 2026)

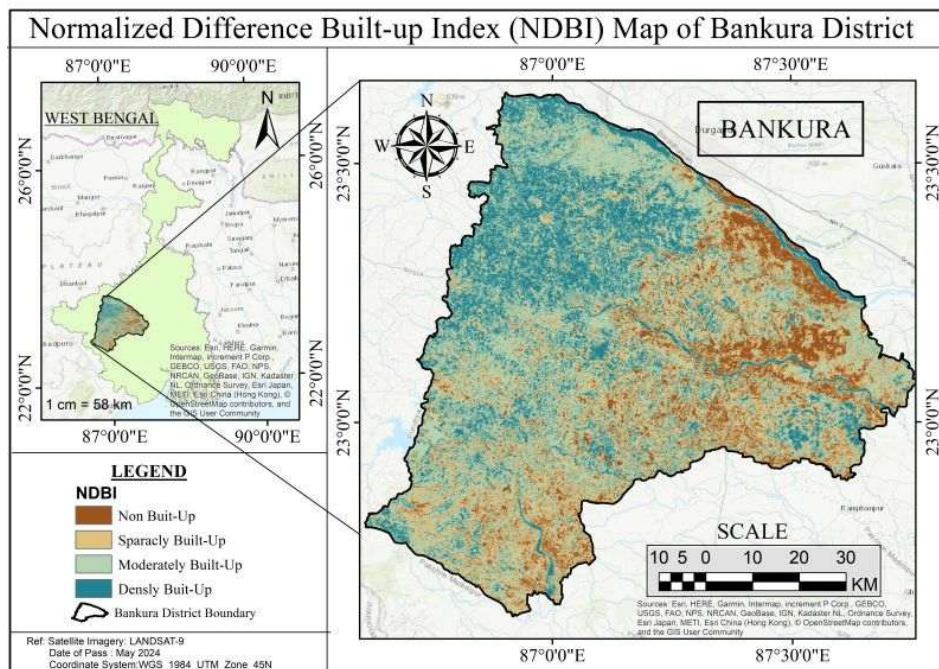


Fig. 16: NDBI (MAY 2014)

7.2.2 Topographic Modeling and Geomorphology

Complementing the spectral data, topographic modeling is executed through the use of high-resolution Digital Elevation Models (DEMs). These models are used to generate detailed slope and aspect analyses, which categorize the land based on its gradient and orientation. This information is vital for erosion control and conservation planning, as the steepness of the terrain directly influences the rate of topsoil loss. In the undulating western reaches of the district, areas with steep gradients are identified for restricted use or social forestry to prevent further degradation, while gentler slopes are designated as more suitable for agricultural expansion or infrastructural development.

7.2.3 Hydrological Flow and Watershed Simulation

The utility of the DEMs is further extended through hydrological flow modeling, which simulates watershed behavior and surface runoff patterns across the district. By analyzing the way water moves across the varied terrain—from the Chhota Nagpur plateau fringes to the river valleys—this modeling provides predictive insights into flood risks and water management requirements. This is particularly important for identifying "gully" erosion patterns where concentrated runoff carves through the ferruginous soil. Understanding these flow dynamics allows for the strategic placement of check dams and rainwater harvesting structures, ensuring that runoff is captured and managed rather than contributing to the expansion of wastelands.

7.3 Structured Decision-Making: The Analytical Hierarchy Process (AHP)

Recognizing that land suitability assessment often involves multiple, competing criteria, the framework utilizes the Analytical Hierarchy Process (AHP) to provide a transparent, mathematical structure for decision-making. The assessment criteria are organized into a logical hierarchy that begins with the ultimate goal—such as identifying optimal zones for wasteland reclamation—and descends into primary factors and specific sub-factors. Subject matter experts perform pairwise comparisons between these criteria to determine their relative importance, a method that effectively mitigates human bias and ensures logical consistency throughout the evaluation.

The output of this process is a set of standardized weights for each parameter, such as soil quality, slope, and proximity to existing infrastructure. By ensuring that the total of these weights equals one, the AHP enables the generation of a quantitative suitability score for every parcel of land within the study area. This systematic approach ensures that suitability rankings are objective, reproducible, and defensible, providing a clear mathematical justification for why certain areas are prioritized over others.

Beyond simple weighting, the AHP methodology includes a built-in consistency check to validate the decision-making process. Since human judgment can sometimes be contradictory during pairwise comparisons, the framework calculates a Consistency Ratio (CR). If the ratio falls within acceptable limits, the derived weights are deemed reliable for use in the final spatial overlay. This level of mathematical rigor is essential for creating high-stakes land-use plans, as it allows planners to demonstrate that their recommendations are based on a balanced consideration of environmental constraints and developmental opportunities.

Ultimately, this structured decision-making framework serves as the "brain" of the geospatial model. It allows for the integration of qualitative expert knowledge with quantitative spatial data, ensuring that factors like the high runoff rates in western Bankura or the critical water needs of agricultural laborers are given their proper significance in the final analysis. By translating complex, multi-dimensional problems into a hierarchical structure, the AHP provides the clarity needed to navigate the trade-offs between ecological restoration and economic expansion.

7.4 Economic Feasibility and Policy Integration

Technical suitability is insufficient without considering the practical realities of implementation; therefore, the framework incorporates both economic and policy analyses as essential reality checks. This stage of the methodology ensures that the geospatial and mathematical models produced in earlier phases can survive the transitions from a digital environment to a field-level operation. By grounding the study in financial and regulatory logic, the framework bridges the gap between academic research and actionable district governance.

7.4.1 Cost-Benefit Analysis and Financial Sustainability

A formal cost-benefit analysis is conducted to weigh the significant capital expenditure required for land-use interventions against their long-term yields. In a region like Bankura, where land transformation often involves high-cost activities such as intensive soil preparation, the development of major irrigation infrastructure, or the extension of road networks into remote upland tracts, financial scrutiny is vital. This analysis evaluates the projected internal rate of return and broader social welfare gains—such as the creation of stable livelihoods for the district's 644,214 agricultural laborers. By calculating the lifecycle costs of these projects, the framework ensures that land-use interventions are financially sustainable and do not place an undue long-term burden on local administrative budgets.

7.4.2 Regulatory Alignment and Zoning Compliance

Policy analysis is integrated to ensure that planning strategies are fully aligned with the prevailing regulatory environment. This involves mapping development proposals against complex legal frameworks, including existing zoning laws, environmental protection acts, and land-tenure regulations. For example, any proposed industrial expansion in the mineral-rich western blocks must be scrutinized against the National Mineral Policy to ensure compliance with extraction and conservation mandates. This phase acts as a final administrative filter, ensuring that the spatial strategy is not only geophysically optimal but also legally permissible within the current governance structure.

7.4.3 Synergy with Government Programs and Subsidies

Furthermore, the analysis identifies opportunities to synthesize proposed projects with existing government programs and public subsidies. By aligning land-reclamation strategies with national and state initiatives—such as agricultural grants for drought-resistant cropping or specific climate-resilience funding—the framework maximizes the overall impact and operational efficiency of the interventions. This strategic integration allows for the pooling of resources, such as leveraging "Disaster Management 2.0" protocols to fund the infrastructure repairs needed to prevent further gully erosion. Ultimately, this policy-aligned approach transforms the study's findings

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A
CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

from a set of recommendations into a viable roadmap for public investment and community-led development.

CHAPTER 8: ANALYSIS AND FINDINGS- DETAILED ASSESSMENT

The spatial analysis of Bankura district reveals a complex mosaic of land degradation and productive potential, driven by the interplay of geomorphological features, climatic variability, and anthropogenic pressures. The district's ecological health is distinctly stratified, moving from the rugged fringes of the Chhota Nagpur plateau to the fertile plains of Bengal, necessitating a granular approach to land management and development planning.

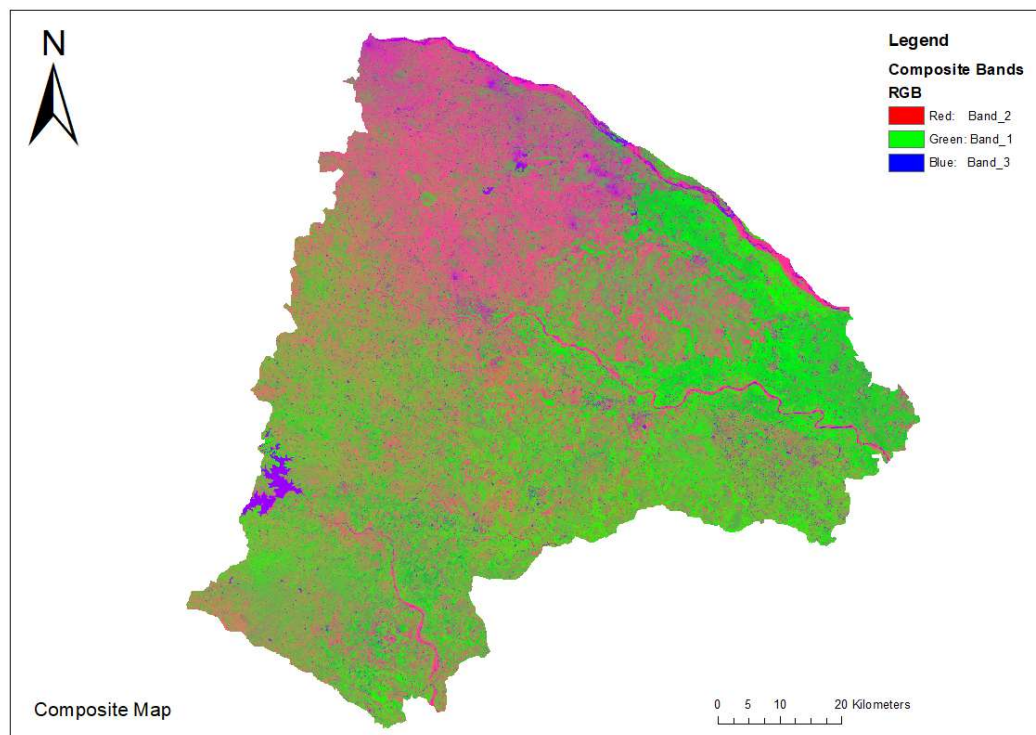


Fig. 17: Composite Map

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

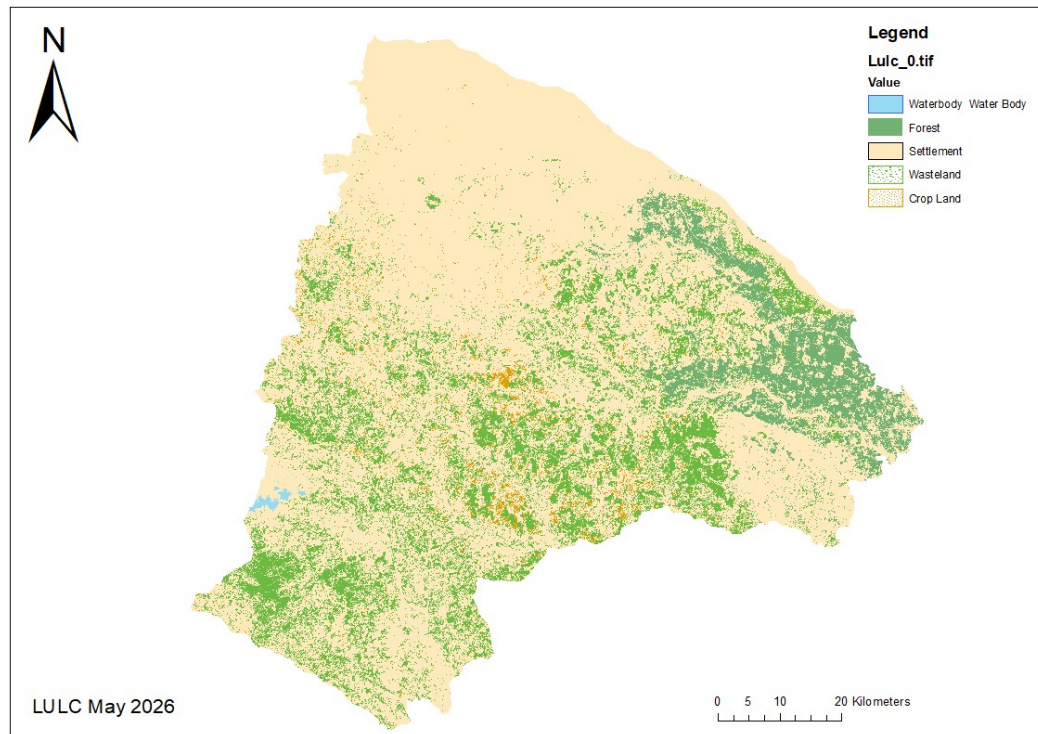


Fig. 18: LULC for May 2026

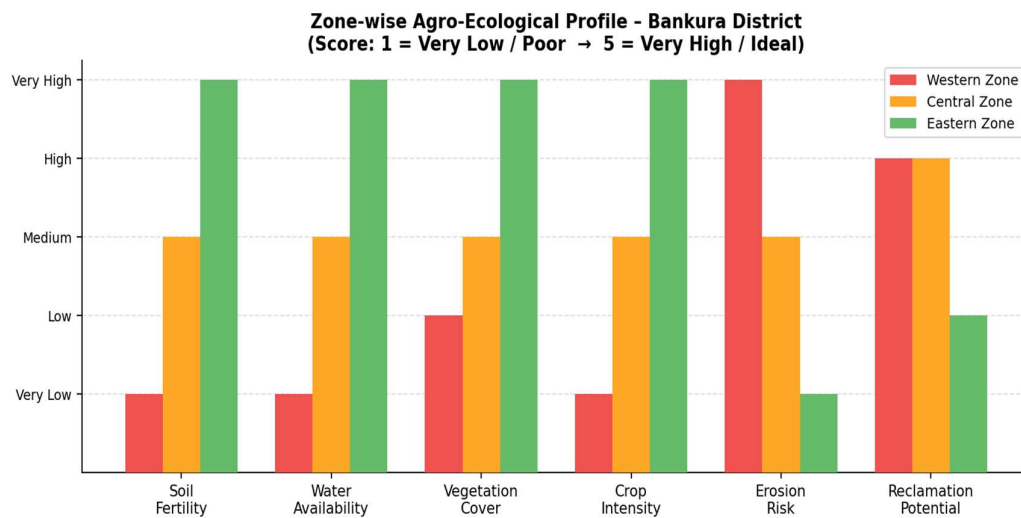


Fig. 19: Zone-wise Agro-Ecological Profile — Comparative Assessment of Key
Environmental and Agricultural Indicators

8.1 The Western High-Risk Zone

The investigation identifies the western region, including blocks such as Chhatna, Saltora, and Mejia, as a high-risk zone characterized by undulating topography, steeper slopes, and rocky terrain. This area faces the most severe degradation, driven by high rates of soil erosion and an inherent lack of moisture retention due to the prevalence of laterite and ferruginous soils. During the pre-monsoon months, extreme thermal stress—with temperatures reaching 45 degrees Celsius—exacerbates the situation, stripping the land of its limited moisture.

Because of the sparse vegetation cover and poor soil quality, this region is highly susceptible to desertification and the formation of deep gullies, making traditional agricultural practices difficult to maintain. Consequently, the strategy for this zone must prioritize intensive soil conservation measures to stabilize the land. Interventions such as contour bunding, the construction of check dams to manage high runoff, and large-scale afforestation are essential to prevent further topsoil loss and to begin the slow process of ecological reclamation.

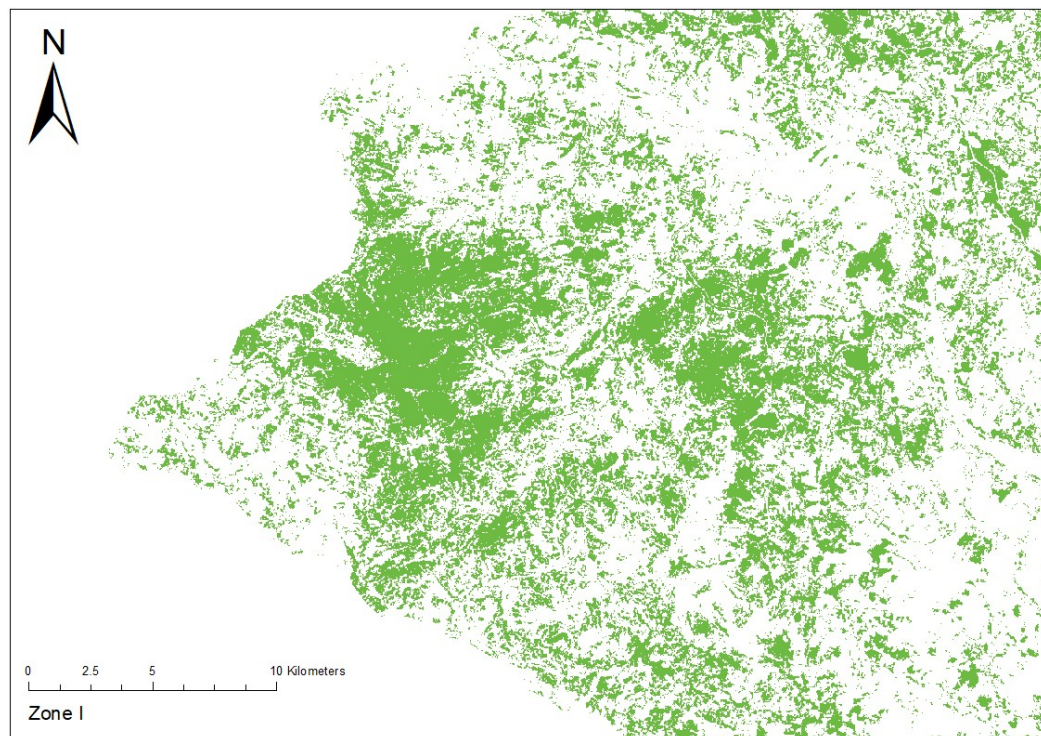


Fig. 20: Western High Risk Zone

8.2 The Central Transitional Buffer

The central region functions as a transitional buffer, exhibiting moderate ecological conditions that stand between the degraded west and the fertile east. Unlike the western belt, this area benefits from localized irrigation infrastructure and varied land-use management, which has helped partially mitigate the most severe forms of degradation. While it is not as compromised as the west, it remains at an ecological tipping point.

The findings suggest that this region holds significant potential for recovery and long-term stabilization if targeted interventions are implemented. Improved water management, such as the clearing of inlets and outlets to local tanks, can capture rainfall that would otherwise be lost to runoff. By introducing restorative agricultural practices and drought-resistant crop varieties, this region can be prevented from sliding further into the degraded state seen in the western reaches, eventually serving as a productive expansion zone for the district's agrarian economy.

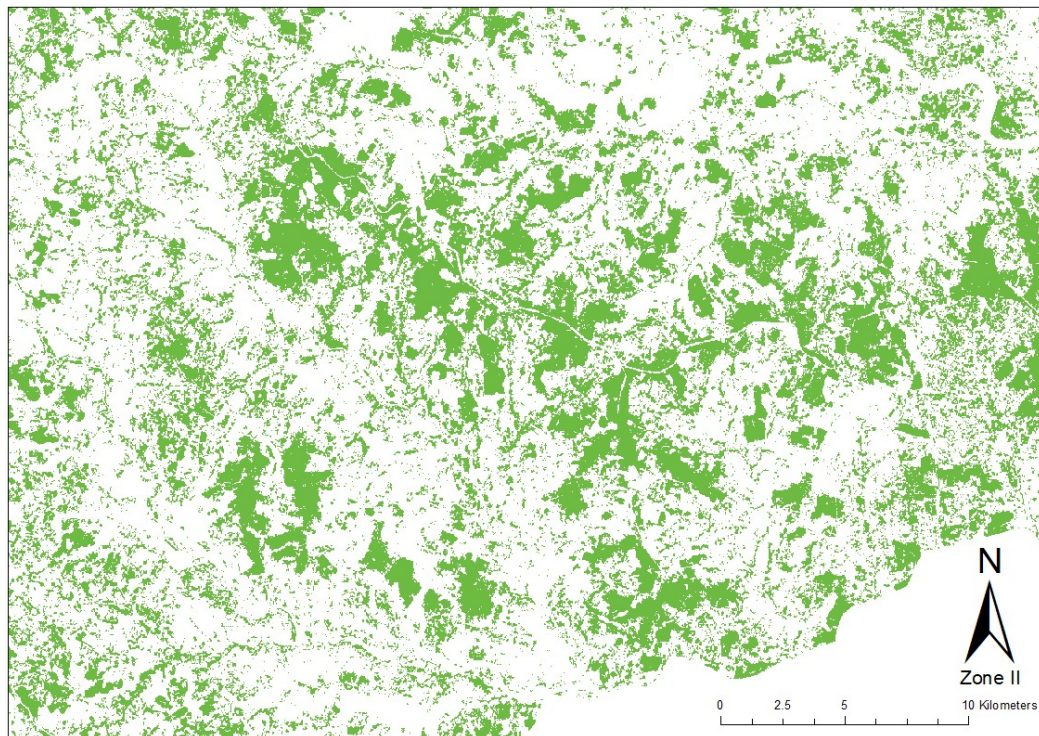


Fig. 21: The Central Transition Buffer

8.3 The Eastern Productive Zone

In contrast, the eastern region represents the most stable and productive segment of the district. Benefiting from flatter topography, nutrient-rich alluvial soils, and more consistent access to water, this zone supports the highest levels of vegetative cover and agricultural intensity. This is where the majority of the district's 308,766 cultivators and 644,214 agricultural laborers find their most consistent employment.

However, this high productivity brings its own set of challenges; the risk here lies in secondary degradation caused by over-intensive farming and potential groundwater depletion. In some blocks, pre-monsoon water levels already show significant fluctuations, dropping to depths of 7 to 9 meters. Sustaining this productivity requires a focus on sustainable agricultural practices that maintain soil health and water table levels. This ensures that the district's primary economic engine does not become depleted over time through the exhaustion of its natural capital.

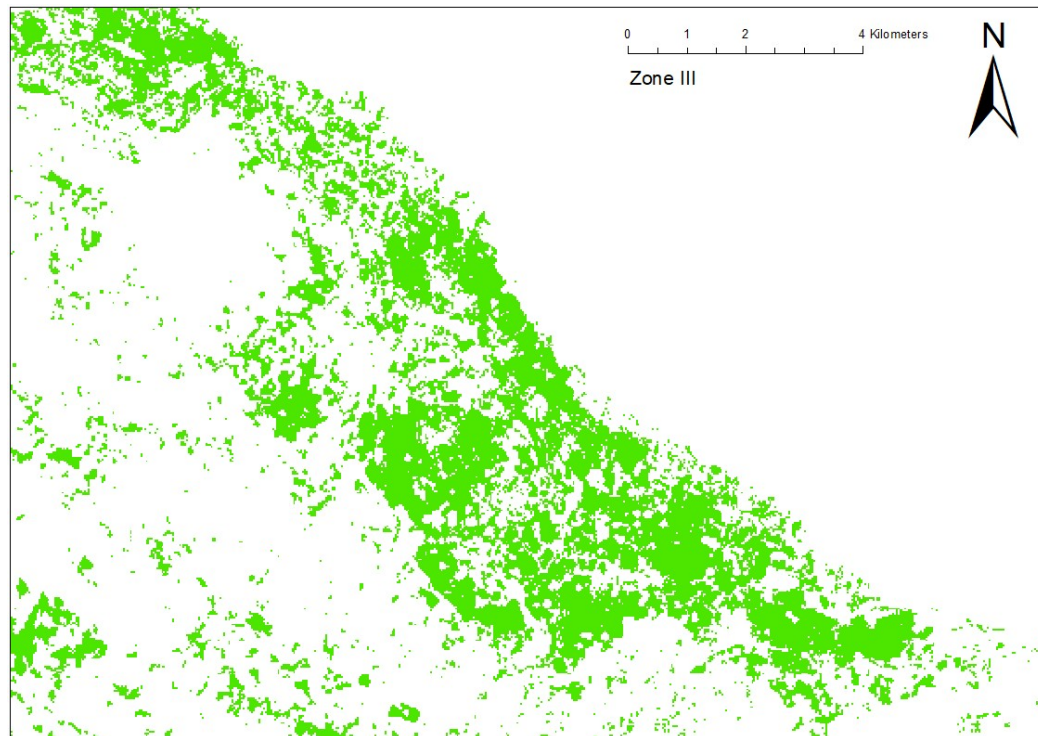


Fig. 22: The Eastern Productive Zone

8.4 Synthesis: A Differentiated Strategy for Resilience

These variations underscore the critical need for a differentiated planning strategy that moves away from "one-size-fits-all" governance. Sustainable land transformation in Bankura will only be achieved by integrating ecological restoration with livelihood enhancement. By aligning conservation efforts with the economic needs of local communities—such as promoting agroforestry in the western uplands or water-efficient irrigation in the eastern plains—the district can create a self-sustaining cycle.

This integrated approach ensures that environmental restoration directly bolsters economic resilience. By empowering the local workforce through "Disaster Management 2.0"—focusing on training, capacity building, and proactive mitigation—the district can effectively manage its wastelands. Ultimately, the goal is to transform these vulnerable landscapes into productive assets, securing the future of the hundreds of thousands of individuals who depend on Bankura's land for their survival.

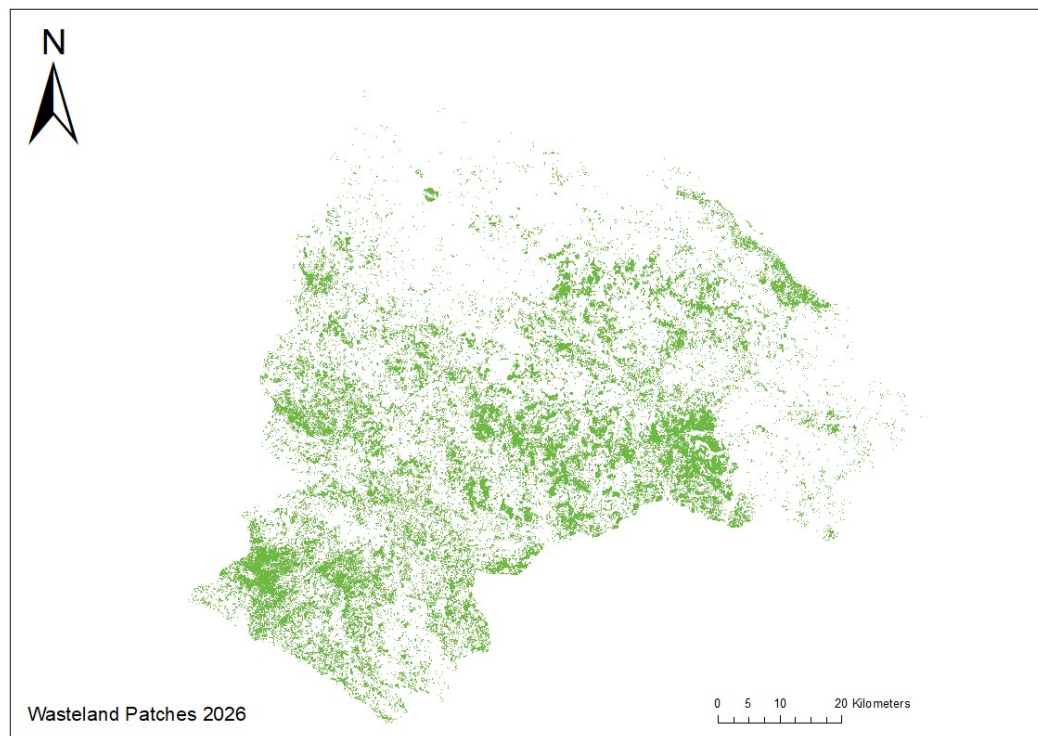


Fig. 23: Wasteland Patches 2026

**TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A
CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL**

Zone	Primary Degradation Indicators	Key Risk Drivers	Recommended Strategy
Western	Low vegetation, high slope, erosion	Topography, lack of moisture	Reforestation, contour bunding
Central	Partial vegetation, moderate fertility	Human pressure, irrigation gaps	Watershed management
Eastern	Good productivity, high fertility	Over-intensive farming	Soil health maintenance

Table 14: Zoning

Feature	Western Zone	Central Zone	Eastern Zone
Soil Type	Lateritic/Acidic	Mixed/Loamy	Alluvial
Topography	Undulating/Sloping	Plains/Rolling	Flat/Floodplain
Key Pressure	Soil Erosion/Runoff	Land Fragmentation	Urban/Industrial Expansion
Primary Risk	Desertification	Nutrient Depletion	Secondary Salinity/Loss

Table 15: Zone wise degradation profile

CHAPTER 9: PROPOSALS AND STRATEGIES: A COMPREHENSIVE FRAMEWORK

To transform the district's agricultural and ecological landscape, we propose an integrated framework that synergizes spatial planning with tactical interventions. This approach moves beyond traditional top-down development, prioritizing resilience, resource efficiency, and socio-economic equity to foster a sustainable and thriving environment. By aligning long-term environmental goals with the immediate economic needs of the local labor force, these strategies aim to convert dormant wastelands into productive assets.

9.1 Spatial Zonation via GIS-Based Suitability Analysis

By leveraging Geographic Information System (GIS) technology, the district has been delineated into three distinct functional zones based on land potential, environmental constraints, and biophysical indicators extracted from multi-spectral imagery. This spatial zonation ensures that interventions are precisely targeted to the specific capacity of the land, moving away from a generalized approach to a model of precision governance.

9.1.1 Zone I: Intensive Ecological Recovery

Zone I represents areas characterized by severe land degradation, high erosion risks, and significant water stress, particularly in the western upland tracts where the soil has a low water-holding capacity. In blocks like Chhatna and Saltora, where pre-monsoon water levels can drop to 7–9 meters, the primary focus is on stabilizing the physical environment.

We propose the implementation of agroforestry models to stabilize the ferruginous and lateritic soils while increasing total biomass density. These biological interventions must be supported by large-scale mechanical soil conservation measures, such as contour bunding and bench terracing, to arrest the high runoff rates that lead to gully formation. Furthermore, the development of decentralized water harvesting structures—including check dams and farm ponds—is essential to capture flash flood

waters and recharge depleted aquifers, effectively restoring the local hydrological balance.

9.1.2 Zone II: Productivity Enhancement

Zone II encompasses regions with moderate soil health and average resource access that function as transitional buffers between the rugged west and the fertile east. While these areas currently underperform, they are not yet as severely compromised as the western reaches. In these areas, the framework emphasizes productivity enhancement through the promotion of climate-resilient and drought-resistant crop varieties that can withstand the district's high temperatures, which often reach 45°C .

By scaling micro-irrigation technologies, such as drip and sprinkler systems, we can maximize water-use efficiency and ensure that limited moisture is converted into higher agricultural yields. This shift toward integrated farming systems is designed to improve the livelihood stability of the farming communities, specifically targeting the hundreds of thousands of agricultural laborers who are currently at risk of economic marginalization during drought years.

9.1.3 Zone III: Optimization and Market Integration

Zone III consists of areas with high potential, characterized by flatter topography, nutrient-rich soils, and more consistent access to water. These regions represent the most stable and productive segments of the district, often supporting the highest levels of agricultural intensity. The strategic goal for this zone is optimization rather than mere reclamation.

We propose a transition toward high-value horticulture and organic produce, supported by the establishment of cold-chain logistics to minimize the post-harvest losses common in the region. Market integration serves as the cornerstone of this zone's development. By facilitating the formation of Farmer Producer Organizations (FPOs), local growers can be empowered to bypass intermediaries and capture a greater share of value. This connection to larger urban and export markets ensures that the district's most productive lands remain a sustainable economic engine for the entire region.

9.2 Integrated Planning Approaches

To ensure these zones function as a cohesive system rather than fragmented units, the framework adopts two critical planning methodologies: cluster-based development and watershed-based planning.

The cluster-based development model moves away from isolated village planning in favor of interconnected village clusters. By linking villages with high infrastructure density to those with lower access, the framework facilitates the shared use of vital resources, such as processing units, storage facilities, and agricultural extension services. This creates a tiered network where "service villages" act as central nodes for market access and administrative support, while "production villages" focus on specialized agricultural outputs, resulting in a more equitable distribution of development benefits.

Concurrent with cluster development, we adopt watershed-based planning to anchor ecological sustainability in the natural hydrological unit rather than arbitrary administrative boundaries. All proposed interventions are designed to follow the natural flow of water, from the ridge to the valley. This ensures that upstream conservation activities directly contribute to downstream productivity and water availability. This holistic approach builds resilience against climate variability by treating water management as the foundational element of all agricultural activities, ensuring that environmental restoration and economic growth reinforce one another.

Zone	Target Objective	Key Interventions	Expected Outcomes
Zone I	Ecological Restoration	Contour bunding, agroforestry, gully plugging	Reduced soil erosion, groundwater recharge
Zone II	Productivity Enhancement	Climate-resilient crops, micro-irrigation	Higher yield per hectare, water efficiency
Zone III	Agricultural Optimization	Cold-chain, FPO market integration	Increased farmer income, market surplus

Table 16: Zonal Intervention Matrix

9.3 Strategic Outcomes

The synthesis of these strategies is designed to move beyond incremental change, aiming instead to achieve a balanced and resilient agro-ecosystem capable of withstanding future environmental and economic shocks. This framework functions as a comprehensive roadmap for sustainable development, ensuring that current needs are met without compromising the ability of future generations to thrive. By aligning technological precision with community-centric planning, the district can transition from a state of vulnerability to one of long-term stability.

9.3.1 Environmental Resilience and Ecological Restoration

A primary outcome of this framework is the measurable reversal of land degradation across the district's most vulnerable blocks. By successfully implementing the "ridge-to-valley" watershed approach, the district can expect a significant reduction in topsoil erosion and the stabilization of active gully networks. The restoration of vegetation density through agroforestry and social forestry will not only increase carbon sequestration but also moderate the micro-climate, providing a critical buffer against the extreme pre-monsoon temperatures that often reach 45 degrees Celsius. Furthermore, the systematic recharge of local aquifers through decentralized water harvesting will raise the water table, ensuring that the moisture levels required for both natural ecosystems and human activities are maintained throughout the year.

9.3.2 Economic Growth and Livelihood Security

The framework directly addresses the socio-economic vulnerabilities of the district's 644,214 agricultural laborers and 308,766 cultivators. By transforming underperforming lands in Zone II and optimizing high-potential areas in Zone III, the strategy aims to boost total agricultural output and diversify income streams. The shift toward high-value horticulture and organic produce, supported by Farmer Producer Organizations (FPOs), will allow local growers to capture a higher share of the market value. This economic growth is designed to be inclusive, creating a self-sustaining cycle where increased agricultural productivity funds further community-led environmental conservation, thereby securing the livelihoods of the population against the historical threat of drought and crop failure.

9.3.3 Proactive Governance: The Disaster Management 2.0 Shift

Ultimately, the most significant strategic outcome is the institutionalization of "Disaster Management 2.0"—a shift from reactive relief to proactive, data-driven mitigation. By integrating GIS-based suitability analysis and real-time biophysical monitoring into the district's administrative core, planners can identify emerging risks before they escalate into crises. This transition ensures that infrastructure investments and resource allocations are mathematically defensible and targeted to areas of maximum impact. This framework provides the district with a resilient governance model that protects both its natural capital and its human potential, fostering a stable environment where economic resilience and ecological health are fundamentally linked.

CHAPTER 10: EXPANDED IMPLEMENTATION FRAMEWORK: A MULTI-DIMENSIONAL STRATEGY

To successfully transition toward sustainable land use, this framework adopts an integrated, phased approach that balances immediate ecological stabilization with long-term systemic resilience. Recognizing that landscape restoration is a temporal process, the implementation strategy is designed to move from urgent physical interventions to the establishment of self-sustaining socio-economic systems. This progression is supported by robust stakeholder collaboration and diversified funding mechanisms, ensuring that short-term actions are always aligned with the district's long-term ecological and developmental goals.

10.1 Phased Implementation Roadmap

The transition toward a resilient landscape follows a structured, sequential progression to ensure that foundational soil health and hydrological stability are secured before scaling productivity and long-term sustainability efforts. This roadmap recognizes that ecological restoration cannot be rushed; it requires a logical buildup of interventions where each phase provides the necessary stability for the next. By adopting this temporal strategy, the district can move from a state of reactive crisis management to a proactive model of environmental and economic prosperity.

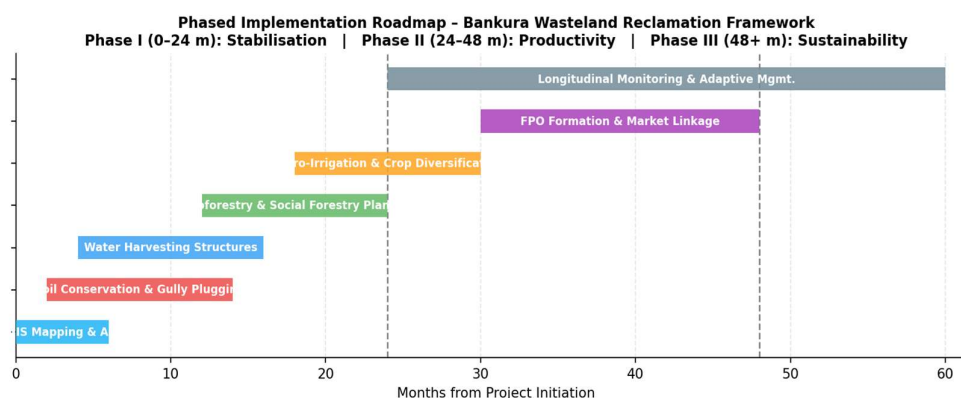


Fig. 24: Phased Implementation Gantt Chart — Bankura Wasteland Reclamation Framework (60-Month Roadmap)

10.1.1 Phase I: Foundational Stabilization (0–2 Years)

In the short term, the focus is entirely on stabilizing the physical foundation of the district's most vulnerable blocks. This phase involves the immediate mitigation of active land degradation and the addressing of acute resource scarcity. Priority is given to low-cost, high-impact soil conservation techniques—such as contour bunding, gully plugging, and cover cropping—to arrest the rapid loss of topsoil during the monsoon.

Simultaneously, this phase prioritizes the establishment of small-scale, decentralized water harvesting structures like check dams, rainwater harvesting pits, and the desilting of traditional village tanks. These efforts are aimed at increasing local water availability and reducing the thermal stress that plagues the region during the pre-monsoon months. A critical administrative component of this phase is the execution of comprehensive baseline assessments. By utilizing high-resolution satellite imagery to document current NDVI and NDWI levels, the district establishes a scientific benchmark against which all future progress will be measured.

10.1.2 Phase II: Productivity Enhancement and Scaling (2–5 Years)

Once the physical landscape is stabilized, the framework shifts its emphasis toward enhancing productivity and scaling the initial interventions to improve economic output. During this medium-term phase, the focus moves from "saving" the land to "optimizing" it. Core actions include the broad adoption of regenerative agricultural practices and the integration of complex agroforestry systems that combine timber, fruit trees, and seasonal crops to diversify the income of the district's 308,766 cultivators.

This phase also targets the restoration of degraded pastures and the introduction of improved seed varieties and livestock breeds specifically tailored to survive in the district's high-temperature, low-moisture environment. To support this increased productivity, micro-irrigation technologies like drip and sprinkler systems are scaled up, ensuring that the water captured during Phase I is used with maximum efficiency. These interventions are designed to bolster the socio-economic resilience of the local labor force, providing tangible proof that environmental restoration leads directly to improved livelihoods.

10.1.3 Phase III: Systemic Sustainability and Resilience (5+ Years)

In the long term, encompassing the fifth year and beyond, the objective shifts to achieving systemic sustainability and institutionalizing climate resilience. This phase is characterized by the transition from physical projects to self-sustaining governance models. Key actions include the scaling of market access for sustainably produced goods through the formation of Farmer Producer Organizations (FPOs), which empower local growers to connect directly with urban and export markets.

The ultimate goal of this final phase is to achieve landscape-level connectivity that supports ecological integrity indefinitely. Continuous monitoring and adaptive management become the standard operating procedure, informed by real-time climate data and refined geospatial models. By this stage, the "Disaster Management 2.0" philosophy is fully integrated into the district's DNA, ensuring that the agro-ecosystem is capable of withstanding future environmental shocks without returning to a state of degradation. This completes the roadmap, transforming Bankura into a model of sustainable regional development where current needs are met while securing the future for generations to come.

Phase	Duration	Primary Tasks	Milestone/KPI
I. Stabilization	Months 1–24	Soil/Water conservation construction	Percentage of land under protection
II. Productivity	Months 25–60	Agroforestry, crop rotation, irrigation	Increase in crop yield/income
III. Sustainability	Month 60+	Institutional capacity, market scaling	Carbon sequestration/Resilience scores

Table 17: Phased Implementation Timeline

10.2 Stakeholder Collaboration and Institutional Synergy

Effective implementation requires moving beyond top-down approaches to a collaborative model where roles are clearly defined yet flexible enough to adapt to local realities. This multi-layered governance structure ensures that the spatial strategy is not

merely an administrative directive but a shared mission. By leveraging institutional synergy, the framework bridges the gap between high-level policy and grassroots execution, ensuring that the needs of the district's 644,214 agricultural laborers and 308,766 cultivators remain central to every intervention.

10.2.1 Government Agencies as Strategic Facilitators

Government agencies act as the primary facilitators and regulators in this ecosystem. They are responsible for providing the overarching policy framework, such as the National Mineral Policy 2019, and ensuring that regional projects align with broader national goals. Beyond regulation, these bodies provide the essential technical expertise and core budget allocations necessary for large-scale infrastructure, such as major irrigation desilting or high-resolution GIS monitoring. By acting as the financial backbone, government agencies ensure that the transition to a resilient landscape is not stalled by a lack of initial capital.

10.2.2 Local Institutions and Community Leadership

Local institutions serve as essential coordinators on the front lines of land transformation. Their role involves managing communal resources, such as village tanks, and mediating potential conflicts over land use and water distribution. Community groups are the heart of the implementation, providing the vital on-ground execution and labor contributions required for projects like contour bunding and afforestation. These groups integrate traditional ecological knowledge with modern geospatial insights, ensuring that solutions are culturally appropriate and locally sustainable. This bottom-up participation fosters a sense of ownership, which is the most critical factor for the long-term maintenance of restored assets.

10.2.3 Technical, Academic, and Private Sector Partnerships

The framework is further strengthened by the inclusion of private and academic sectors as strategic partners. Academic institutions supply the rigorous research data and longitudinal studies needed to track environmental shifts, such as changes in NDVI or soil health. Simultaneously, the private sector acts as a bridge to market viability, supplying innovative technologies like micro-irrigation systems and establishing vital market linkages for high-value organic produce. By forming Farmer Producer Organizations (FPOs) and integrating cold-chain logistics, these partners ensure that the district's transition toward sustainability is supported by a robust and profitable economic engine.

Task	Government	Local Institutions	Community Groups
Policy Formulation	Accountable	Consulted	Consulted
Infrastructure Build	Consulted	Responsible	Responsible
Resource Management	Informed	Accountable	Responsible
Market Linkages	Responsible	Consulted	Informed

Table 18: Stakeholder Responsibility Matrix

10.3 Financial Mobilization Strategy

Sustainability is contingent upon a blended finance model, which reduces reliance on single-source funding and fosters a deep sense of community ownership. This financial strategy is designed to be as resilient as the landscape itself, ensuring that the ambitious transition toward a productive agro-ecosystem is backed by a diversified and stable capital base. By layering public, institutional, and community-led funding, the framework creates a financial safety net that allows for consistent progress regardless of fluctuations in individual budget cycles.

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

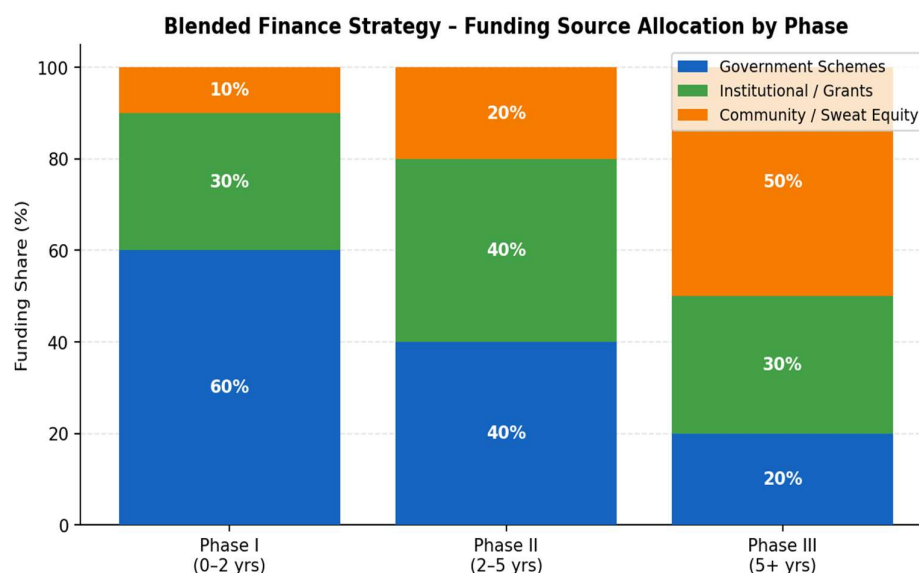


Fig. 25: Blended Finance Strategy — Shifting Funding Composition Across the Three Implementation Phases

10.3.1 Public Financing and Government Synergy

Public financing serves as the primary engine for large-scale interventions. The framework is designed to leverage dedicated government schemes and environmental subsidies specifically intended for conservation infrastructure. By aligning land restoration goals with existing national and state mandates—such as agricultural grants for drought-resistant cropping or water-shed management funds—the district can access the capital required for major physical stabilization projects. This strategic alignment ensures that local projects are integrated into the broader "Disaster Management 2.0" fiscal architecture, making the strategy both politically and economically viable.

10.3.2 Institutional Funding and International Climate Finance

To complement public resources, the strategy actively pursues institutional funding from a variety of external sources. This involves securing grants and low-interest loans from development banks and international climate funds aimed at ecological restoration and carbon sequestration. Furthermore, partnerships with non-governmental organizations provide a vital stream of technical and financial assistance for niche

projects, such as the development of cold-chain logistics or the establishment of organic certification systems in the eastern productive zones. This institutional support acts as a catalyst, providing the high-level expertise and specialized equipment needed to implement advanced geospatial monitoring and precision agriculture.

10.3.3 Community Contributions and "Sweat Equity"

Crucially, the strategy incorporates community contributions as a fundamental pillar of its financial model. This includes "sweat equity"—where local residents, including the district's 644,214 agricultural laborers, provide the human capital necessary for the direct on-ground execution of projects like contour bunding and afforestation. Additionally, the formation of local collective funds allows communities to contribute small-scale financial resources toward shared assets. This grassroots investment not only provides necessary resources but also significantly increases project ownership. When local stakeholders are financial and physical partners in the transformation, the likelihood of long-term maintenance and protection of restored landscapes increases exponentially, ensuring the district's transition is truly self-sustaining.

Funding Source	Short-Term (%)	Medium-Term (%)	Long-Term (%)
Government Schemes	60%	40%	20%
Institutional/Grants	30%	40%	30%
Community/Sweat Equity	10%	20%	50%

Table 19: Blended Finance Allocation

10.4 Integrating Dimensions for Sustainability

The success of the proposed framework is predicated on the holistic integration of three critical dimensions. Rather than treating technical, institutional, and social factors as isolated silos, this methodology weaves them together to ensure that land-reclamation efforts are durable and resilient. By addressing these dimensions simultaneously, the district can move toward a state where physical and economic interventions are not only practical but also deeply resonant within the local cultural and administrative landscape.

10.4.1 The Technical Dimension: Science and Scalability

The technical dimension ensures that all physical interventions, such as the restoration of irrigation systems and large-scale soil conservation efforts, are grounded in scientific rigor. By utilizing geospatial indicators like the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and Normalized Difference Water Index (NDWI), planners can ensure that interventions are climate-appropriate and specifically tailored to the biophysical constraints of each zone. This dimension focuses on the engineering and biological feasibility of the project, ensuring that check dams, contour bunds, and agroforestry models are designed to be scalable across the district's diverse topography. This technical foundation prevents the failure of infrastructure and ensures that every rupee invested in "Disaster Management 2.0" yields a measurable environmental return.

10.4.2 The Institutional Dimension: Capacity and Governance

The institutional dimension shifts the focus from building infrastructure to building the capacity of local governance bodies. For long-term sustainability, it is essential that administrative structures are equipped to manage communal resources, enforce land-use regulations, and maintain the infrastructure developed in the earlier phases. This involves training local officials and community leaders in data-driven decision-making, allowing them to use real-time monitoring to adapt to emerging environmental stressors. By institutionalizing these practices, the district ensures that the governance of its land resources remains consistent and transparent, even as personnel or political priorities change over time.

10.4.3 The Social Dimension: Inclusion and Cultural Resonance

The final, and perhaps most critical, dimension is the social one, which prioritizes community inclusion, gender equity, and the recognition of traditional land-use rights. To be truly sustainable, land-use interventions must be socially acceptable and culturally resonant. This means involving the district's 644,214 agricultural laborers in the planning and execution phases to ensure their livelihoods are protected and enhanced. By integrating traditional ecological knowledge with modern scientific methods, the framework fosters a sense of local pride and stewardship. This social alignment ensures that the transition to a more productive agro-ecosystem is seen not

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A
CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

as an external imposition, but as a community-led movement toward shared prosperity and long-term ecological health.

CHAPTER 11: CONCLUSION AND FUTURE DIRECTIONS

The study demonstrates that the transformation of agricultural wastelands into productive landscapes is both feasible and necessary for sustainable rural development. By integrating spatial analysis, policy frameworks, and community-based approaches, the proposed model provides a comprehensive pathway for land restoration in the Bankura district. The findings highlight the importance of context-specific planning and the need for coordinated efforts across multiple sectors. The framework developed in this study has the potential to serve as a replicable model for similar regions facing challenges of land degradation and resource scarcity.

11.1 Pilot-Scale Validation and Site-Specific Testing

To build upon these findings and facilitate the practical implementation of the proposed restoration model, further research is required to transition from theoretical frameworks to actionable, field-tested solutions. Initial efforts should prioritize pilot-scale validation, where the framework is tested through small-scale projects across the diverse topographical zones identified within the Bankura district. Such controlled environments are essential for measuring site-specific ecological responses—particularly in the high-risk western zones where thermal stress and rocky terrain present unique challenges. These pilots will assess the economic viability of restoration techniques, such as contour bunding and decentralized water harvesting, before attempting larger-scale interventions.

11.2 Longitudinal Monitoring and Bio-Physical Recovery

Coupled with these pilot projects, it is vital to establish long-term monitoring programs. Longitudinal studies are necessary to track the bio-physical recovery of reclaimed lands, focusing specifically on critical indicators such as soil fertility indices, groundwater recharge rates, and the trajectory of biodiversity restoration over a 5 to 10-year horizon. By utilizing the established spectral indices—NDVI for vegetation health and NDWI for moisture levels—researchers can create a continuous data loop that quantifies the success of "Disaster Management 2.0" in real-time.

11.3 Socio-Economic Impact and Policy Synergy

Beyond the biophysical aspects, the socio-economic dimensions of land restoration must be rigorously evaluated. Future research should prioritize a comprehensive impact assessment to understand how these initiatives influence local livelihoods, specifically for the district's 644,214 agricultural laborers. This includes conducting detailed cost-benefit analyses that compare alternative land-use patterns—such as the trade-offs

between agroforestry and industrial cultivation—to identify the most sustainable paths for community adoption.

Furthermore, the bureaucratic and legal complexities of land use necessitate a deeper investigation into policy integration. Future studies should focus on identifying the specific legislative and administrative pathways required to incentivize public-private partnerships (PPPs), ensuring alignment with regulations like the National Mineral Policy 2019.

11.4 Advanced Technological Integration

Finally, the integration of advanced technology should be explored as a cornerstone of adaptive management. Incorporating precision agriculture and real-time remote sensing data will be instrumental in automating the identification of degradation patterns and managing land health. By evolving alongside environmental conditions, these technologies will allow for a dynamic governance model that secures the district's natural capital while generating consistent, long-term economic growth for all stakeholders. This ensures that Bankura's transition toward a resilient agro-ecosystem is not just a temporary fix, but a permanent foundation for future generations.

REFERENCES

S.No.	Author(s)	In-text Citation	Reference Entry
1	Boughton JM	(Boughton, 2002)	Boughton JM (2002), Service level benchmarking of sanitation: Milestones achieved, <i>Economic and Political Weekly</i> , Vol 47 No. 03, p98.
2	FAO	(FAO, 2015)	FAO (2015), <i>Status of the World's Soil Resources</i> , Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
3	Kempton et al.	(Kempton et al., 1992)	Kempton W, Darley JM and Stern PC (1992), Psychological Research for the New Energy Problems: Strategies and Opportunities, <i>American Psychologist</i> .
4	Lal R	(Lal, 2001)	Lal R (2001), Soil degradation by erosion, <i>Land Degradation & Development</i> , Vol 12 No. 06, pp519–539.
5	Millennium Ecosystem Assessment	(Millennium Ecosystem Assessment, 2005)	Millennium Ecosystem Assessment (2005), <i>Ecosystems and Human Well-being: Synthesis</i> , Island Press, Washington, DC.
6	Porter G	(Porter, 2014)	Porter G (2014), Transport services and their impact on poverty and gender in rural Africa, <i>World Development</i> , Vol 64, pp1–16.
7	Samson C	(Samson, 1970)	Samson C (1970), Spatial information studies in Urban design, In: Stone S, ed. (1980), <i>Humanities information research</i> , CRUS, Sheffield, pp44-68.
8	Silverman DF	(Silverman, 1990)	Silverman DF, ed. (1990), <i>The active interview</i> , Sage Publications, Beverly Hills CA.
9	Stolly K	(Stolly, 2005)	Stolly K (2005), JnNURM and improvement in the quality of life, A Case of Ahmedabad, M.Plan, Banaras

TRANSFORMING AGRICULTURAL WASTELANDS INTO AGRO-PRODUCTIVE LANDS: A
CASE OF BANKURA DISTRICT OF WEST BENGAL

			Hindu University, Varanasi. (Unpublished).
10	UNCCD	(UNCCD, 2017)	UNCCD (2017), <i>Global Land Outlook</i> , United Nations Convention to Combat Desertification, Bonn.
11	World Bank	(World Bank, 2007)	World Bank (2007), <i>Rural transport services in developing countries</i> , World Bank, Washington, DC.
12	Ziegler et al.	(Ziegler et al., 2025)	Ziegler J, Afukaar F and Porter G (2025), Rural transport services and inclusive development, <i>Transport and Development Journal</i> , Vol 11 No. 02, pp201–220.